राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 7 अंक 312

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, शनिवार, 20 अप्रैल, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी होंगे अगले नौसेना प्रमुख

>>7

लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं का जयकारा

लोस चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर करीब 63 प्रतिशत मतदान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकतंत्र के महापर्व में मतदान को लेकर देशभर के मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। पहले चरण में 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को हुए मतदान में छत्तीसगढ़, मणिपुर व बंगाल के कुछ स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो देश के बाकी हिस्सों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। छत्तीसगढ़ में दुर्घटनावश ग्रेनेड फटने से एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई।

तेज गर्मी के बाद भी लोगों ने घरों से निकलकर जमकर मतदान किया, हालांकि सुबह व शाम के समय मतदान की रफ्तार अधिक रही। हिंसा से जूझते मणिपुर व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। पहले चरण में लगभग 62.37 प्रतिशत वोटिंग हुई है। इनमें सबसे अधिक वोटिंग त्रिपुरा में करीब 80 प्रतिशत व बंगाल में 77 प्रतिशत हुई। सबसे कम वोटिंग बिहार में करीब 48.5 प्रतिशत हुई है। उत्तर प्रदेश में 58.49, उत्तराखंड में 54.06 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में करीब 63 प्रतिशत मतदान हुआ है। 2019 के सभी चरणों की औसत वोटिंग 67.4 प्रतिशत थी।

पहले और सबसे बड़े चरण का मतदान सुबह सात बजे प्रारंभ हुआ। इस चरण में अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम विधानसभा के लिए भी मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए सबसे खास रुझान जम्मू-कश्मीर से देखने को मिला, जहां अनुच्छेद-370 हटने के बाद पहली बार आम चुनाव हो रहे है। वहां लोग इस कदर उत्साहित दिखे कि सुबह अचानक हुई बारिश के बाद भी मतदान केंद्रों पर लाइनों में लगे रहे। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के इस उत्साह को सराहा भी है। लंबे समय से जातीय संघर्ष से घिरे मणिपुर में भी लोगों ने मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जहां करीब 69 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके साथ ही पहले चरण में उतरे 1,625 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है।

- गर्म मौसम भी कम न कर सका मतदाताओं का जोश और जज्बा
- हिंसा से जूझते मणिपुर व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिखा मतदाताओं का उत्साह
- छत्तीसगढ़, मणिपुर व बंगाल में कुछ जगह हिंसा, बाकी देश में मतदान शांतिपूर्ण
- अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभा के लिए भी डाले गए वोट
- त्रिपुरा एवं बंगाल में सबसे अधिक और बिहार में सबसे कम हुआ मतदान

लोकतंत्र के महापर्व में प्रथम चरण के मतदान को लेकर देशभर के मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। उत्तर प्रदेश के कैराना में शुक्रवार को पोलिंग स्टेशन पर लगी मतदाताओं की कतारें। रायटर

कहां कितने प्रतिशत मतदान (शाम नौ बजे तक)

राज्य	सीटें	मतदान प्रतिशत (अनुमानित)
बंगाल	3	77.57
उत्तर प्रदेश	8	58.49
उत्तराखंड	5	54.06
त्रिपुरा	1	80.17
तमिलनाडु	39	65.19
सिक्किम	1	69.47
राजस्थान	12	56.58
पुडुचेरी	1	73.50
नगालैंड	1	56.91
मिजोरम	1	54.23
मणिपुर	2	69.13
मेघालय	2	74.21
महाराष्ट्र	5	55.35
मध्य प्रदेश	6	64.77
लक्षद्वीप	1	59.02
जम्मू-कश्मीर	1	65.08
छत्तीसगढ़	1	63.41
बिहार	4	48.50
असम	5	72.10
अरुणाचल प्रदेश	2	67.15
अंडमान निकोबार	1	56.87

(स्रोत- चुनाव आयोग)

गड़करी, भूपेंद्र, सोनोवाल व बलूनी की किस्मत ईवीएम में हुई कैद

पहले चरण के 1,625 प्रत्याशियों में से 134 महिला उम्मीदवार हैं। इसी चरण में आठ केंद्रीय मंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व राज्यपाल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में जो अहम चेहरे मैदान में थे, उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सर्वानंद सोनोवाल, भूपेन्द्र यादव, किरण रिजिजू, अर्जुनराम मेघवाल, कांग्रेस के गौरव गोगोई, भाजपा के अनिल बलूनी जैसे चेहरे शामिल हैं। 2019 के चुनाव में इन 102 सीटों में से संप्रग के पास 45 और राजग के पास 41 सीटें थी।

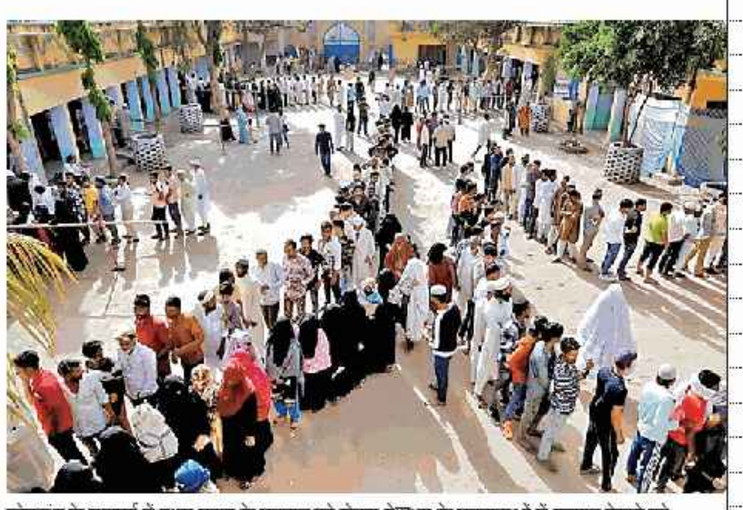

ईवीएम में मामूली गड़बड़ियों की खबरें पेज>>4

पहली बार अंडमान की शोम्पेन जनजाति के लोगों ने किया मतदान पेज>>4

स्वास्थ्य की स्वतंत्र जांच से क्यों कतरा रहे केजरीवाल: ईडी

नई दिल्ली: आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल में आम, आलू-पूड़ी व मिठाई खाने के आरोप का विरोध किया। वहीं ईडी ने कहा, सीएम स्वतंत्र जांच से क्यों कतरा रहे हैं। उधर केजरीवाल ने नई याचिका दायर कर कोर्ट से मधुमेह को लेकर प्रतिदिन 15 मिनट चिकित्सक से परामर्श की मांग की है। (पेज-2)

ममता सरकार को भ्रष्टाचार के एक और मामले में लगा झटका

कोलकाता: ममता सरकार को भ्रष्टाचार के एक और मामले में झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआइ जांच के निर्देश को बहाल रखा। इससे पहले राशन घोटाले में भी ममता सरकार को हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। (पेज-7)

भारत ने फिलीपींस को सौंपी ब्रह्मोस मिसाइल

मनीला: भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला सेट सौंप दिया है। भारतीय वायुसेना के सी-17 ग्लोबमास्टर विमान से मिसाइलों को फिलीपींस पहुंचाया गया। देश के रक्षा निर्यात में ये एक बड़ा कदम है। भारत और फिलीपींस के बीच दो साल पूर्व ब्रह्मोस को लेकर समझौता हुआ था। यह सौदा 37 करोड़ 50 लाख डालर का है। (पेज-11)

यात्रा

इतिहास और आस्था संग प्रकृति दर्शन का संगम

बुरहानपुर: मप्र के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले की यात्रा मात्र इतिहास से साक्षात्कार नहीं कराती है बल्कि प्रकृति दर्शन के साथ उस समय की समृद्ध इंजीनियरिंग और सोच से भी भेंट कराती है। ● पेज-7

संपादकीय

पश्चिम एशिया का खत्म न होने वाला टकराव: इजरायल-ईरान की तनातनी धीरे-धीरे और उग्र रूप धारण कर विश्व के लिए संकट बन सकती है। **दिव्य कुमार सोती** का विश्लेषण।

चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप का खतरा: बाहरी संस्थाएं अन्य देशों में चुनावों को प्रभावित करने के बाद भारत पर भी नजर टेढ़ी किए हुए हैं। **शशि शेखर वेम्पति** का आलेख। ● पेज-8

विमर्श

न्याय तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग: भारतीय न्याय प्रणाली में कई विसंगतियां व्याप्त हैं। ऐसे में इसे पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के सुझाव दे रहे हैं, **सुभाषचंद्र अग्रवाल**।

गर्मी भी नहीं पैदा कर पाई गर्मी: शुक्रवार को लोकसभा के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। बिहार में भी चार सीटों पर चुनाव हुए, परंतु मत प्रतिशत अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम रहा, जिसे विश्लेषित करती **आलोक मिश्रा** की डायरी। ● पेज-9

इजरायल का ईरान के सैन्य ठिकाने पर हमला

- ईरान ने कहा, इस्फहान शहर के ऊपर तीन ड्रोन मार गिराए
- हमले की न इजरायल ने जिम्मेदारी ली, न ईरान ने दोष दिया
- टकराव पर दोनों देशों के स्वर मंद, तनाव में कमी के संकेत

इजरायल की ओर से हमले की आशंका के बीच ईरान के इस्फहान शहर के जर्दनजान क्षेत्र में स्थित परमाणु सेंटर पर निगरानी करते सैन्यकर्मी। रायटर

तेहरान, रायटर: इजरायल ने भारतीय समयानुसार शुक्रवार सुबह ईरान पर हमला कर उसके सैन्य ठिकाने को क्षति पहुंचाने का दावा किया है। इजरायल ने यह हमला 14 अप्रैल को ईरान के दागे 300 से ज्यादा ड्रोन व मिसाइलों के जवाब में किया, पर इजरायल सरकार के किसी उच्चपदस्थ व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले का दावा सरकारी सूत्रों के जरिये इजरायली मीडिया ने किया है। ईरान ने इस हमले को गंभीरता से नहीं लिया है। कहा है कि इस हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने जवाब में इजरायल पर हमला करने की मंशा भी जाहिर नहीं की है। इस हमले के बाद सर्वाधिक संपन्न लोकतांत्रिक देशों के समूह जी 7 ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है।

ईरानी मीडिया के अनुसार, इस्फहान शहर में कुछ धमाकों की आवाज सुनी गई, जो कि एयर डिफेंस द्वारा तीन ड्रोनों को निशाना बनाए जाने से आई थीं। ईरानी अधिकारियों ने इन ड्रोन हमलों के लिए इजरायल को नहीं बल्कि किन्हीं बाहरी तत्वों को जिम्मेदार बताया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस घटना के लिए इजरायल पर हमले की कोई योजना नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फार न्यू अमेरिकन सिक्युरिटी में मध्य-पूर्व मामलों के प्रमुख जोनाथन लार्ड के अनुसार, ईरान के इस रुख से साफ है कि वह इजरायली हमले को तूल नहीं देना चाहता है।

इजरायली मीडिया ने शुक्रवार सुबह इस्फहान सहित ईरान के सात शहरों पर हमले के दावे किए पर समय बीतने के साथ उसके दावे के स्वर धीमे होते चले गए। इस्फहान में ईरान के सैन्य ठिकाने हैं, नजदीक ही नातांज में देश का सबसे बड़ा परमाणु प्रतिष्ठान है। शुक्रवार को शाम घिरने तक दशकों से छद्म युद्ध लड़ रहे दोनों देशों के स्वर सीधी लड़ाई को लेकर शांत पड़ चुके थे। वैसे गुरुवार-शुक्रवार की रात इजरायल ने सीरिया व इराक पर भी हवाई हमले किए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव का नतीजा है कि इजरायल ने ईरान पर कमजोर प्रहार किया जिससे तनाव बढ़ाए बगैर उसका पलटवार का एलान पूरा हो जाए।

इजरायली मंत्री ने कहा, शक्तिहीन हमला

इजरायली हमले पर वहां के आंतरिक सुरक्षा मंत्री इत्मार बेन गिविर ने असंतोष जाहिर किया है। दक्षिणपंथी नेता गिविर ने एक्स पर पोस्ट कर ईरान को इजरायल के जवाब को शक्तिहीन करार दिया।

ईरान ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करेंगे पेज>>11

'सच्चे यदुवंशी हैं तो श्रीकृष्ण का अपमान करने वालों के साथ कैसे'

जय प्रकाश पांडेय, जागरण ● अमरोहा

- अमरोहा में अखिलेश व लालू-तेजस्वी का नाम लिए बिना पीएम ने जनता से किया प्रश्न
- कहा-पूर्व की सरकारों ने एससी, एसटी और ओबीसी के साथ किया छल
- कहा, फिर शूटिंग पर निकले दो रिजेक्ट शहजादे सनातन धर्म व आस्था पर कर रहे चोट

सजी-धजी एक ढोलक मुख्यमंत्री के हाथों से सरकती हुई प्रधानमंत्री के हाथों तक पहुंची। उसे संभालते हुए मोदी एक हाथ से ढोलक बजाने लगे और वहां उपस्थित लोग बजाने लगे ताली। बिना कुछ बोले नेता का जनता से सीधा कनेक्शन जुड़ चुका था, इसी को दुनिया मोदी मैजिक कहती है। मोदी ने तुरंत संवाद शुरू कर दिया, 'अमरोहा भगवान श्रीकृष्ण की भूमि है जिनकी त्रैलोक्यन्यारी द्वारका गुजरात में है समुद्र के नीचे। अभी हम वहां गए और मोरपंख भी चढ़ाया लेकिन, कांग्रेस के शहजादे ने कहा कि समुद्र के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं।' आगे मोदी ने अखिलेश यादव और लालू-तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना जनता से सीधा प्रश्न किया, 'बताइए कि यदि वो लोग सच्चे यदुवंशी हैं तो श्रीकृष्ण का अपमान करने वाले के साथ बैठ कैसे सकते हैं'। जनता मोदी-मोदी का गगनभेदी नारा लगाने लगी।

पीएम नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को अमरोहा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गजरौला कस्बे में भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सफेद कुर्ता पहने मोदी ने राहुल और अखिलेश का नाम लिए बिना व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 'आप द्वारा रिजेक्ट किए जा चुके दो शहजादे फिर शूटिंग करने निकले हैं यूपी में। इस बार भी इनकी फिल्म पिट जाएगी। मत भूलिएगा कि पहले की सरकारों ने सामाजिक न्याय के नाम पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों संग केवल धोखा किया है। महात्मा ज्योतिबा, आंबेडकर और चौधरी चरण सिंह के सामाजिक न्याय को केवल भाजपा पूरा कर रही है'। अमरोहा की ढोलक को अद्भुत बताते हुए मोदी ने कहा कि इसकी थाप का डंका दुनिया में बज रहा है। यहां के खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने दुनिया को भारत का कमाल दिखाया है।

अमरोहा में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। साथ में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रेट्र

उज्ज्वला, शौचालय, आयुष्मान, हर घर पानी, आवास, गन्ना बकाया भुगतान, व मुफ्त राशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि, भाजपा बहुत बड़े सोच के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हमने जो दस वर्षों में किया है, वह फिल्म का ट्रेलर मात्र है। वस्तुतः यह चुनाव भारत का भाग्य सुनिश्चित करेगा इसलिए संविधान प्रदत्त मताधिकार का प्रयोग कर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनें। भारत माता की जय बोलने में शर्म महसूस करने वाले ऐसे लोगों को सिर उठाने का अवसर न दें जो निमंत्रण मिलने के बाद भी अयोध्या नहीं गए, श्रीराम का दर्शन नहीं किया। ऐसे लोगों के शासन में ही 'मकान बिकाऊ है' के बोर्ड लगा करते थे और समूह में पलायन हुआ करता था। जब योगी सरकार ने यहां काम संभाला, तब जाकर यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ। अमरोहा की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने पाकिस्तान को भुखमरी का शिकार बताते हुए कहा कि इधर भारत में 80 करोड़ जरूरतमंदों को सरकार मुफ्त राशन दे रही है। आने वाले और पांच वर्षों तक यह सुविधा मिलने की घोषणा मोदी पहले ही कर चुके हैं।

मप्र में बोले मोदी-आतंक का सप्लायर आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा पेज>>4

सुरक्षा परिषद में सुधार पर भारत के रुख का अमेरिका ने किया समर्थन

वाशिंगटन: अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार के भारतीय रुख का समर्थन करते हुए कहा है कि 70 साल पूर्व की यूएनएससी आज की वास्तविकताएं नहीं दर्शाती। अमेरिका ने भारत समेत जी-4 देशों को यूएनएससी में स्थान देने की मांग की। (पेज-11)

यूपीएससी टापर आदित्य श्रीवास्तव ने हासिल किए 54.27 प्रतिशत अंक

नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा, 2023 में चयनित अभ्यर्थियों के अंक शुक्रवार को जारी कर दिए। परीक्षा के टापर आदित्य श्रीवास्तव ने 54.27 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। (पेज-13)

आइपीएल

आज का मैच

दिल्ली कैपिटल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद

शाम 7:30 बजे | स्थान: दिल्ली

प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स/जियो सिनेमा

सप्तरंग

जोश नई राहों का

आप भी बन सकते हैं आइएएस!

फिर से करना चाहती हूं हिंदी से स्नातक

● पेज-13

महासमर 2024

अपनी लोकप्रियता और बजरंगबली के सहारे नवनीत राणा पेज>>3

भारत में लोकतंत्र के उत्सव में चीनी मूल के नागरिक भी भागीदार पेज>>3

वोट की 'तीर्थयात्रा' पर सत्तू-प्याज ले 40 किलोमीटर चले पैदल पेज>>4

दस साल गड्ढे भरने में लगे, अब तैयार होगा 'विकसित भारत': शाह पेज>>5

इस समय मोदी मैजिक चल रहा है: डा. शर्मा पेज>>6

अब विज्ञान की दुनिया में बजेगा भारत का डंका

बढ़ता कद

प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर ने कहा, आर्थिकी के साथ विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार है भारत, शोध के लिए वित्तीय मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा कर अहम योगदान दे सकता है निजी क्षेत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। देश में हो रहे इस बदलाव के कई सकारात्मक आयाम दुनिया को दिखाई देने लगे हैं। प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर ने कहा है कि आर्थिकी के साथ भारत विज्ञान के क्षेत्र में भी एक बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार है। मिसाल के रूप में पिछले वर्ष चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बनने और चंद्रमा पर साफ्ट लैंडिंग कराने वाले चौथे देश का तमगा हासिल करके दुनिया को अपनी तकनीक का लोहा मनवा चुका है। भारत की यह सफलता इसलिए और भी विशेष बन जाती है, क्योंकि यह अभी शोध एवं विकास पर अपनी जीडीपी का महज एक प्रतिशत से भी कम खर्च कर रहा है। साइंस जर्नल ने कहा है कि अगर निजी क्षेत्र भी शोध एवं विकास में योगदान बढ़ाएं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत साइंस का सुपर पावर बनकर वैश्विक पटल पर चमकेगा।

प्रतिष्ठित ब्रिटिश साप्ताहिक ने अपने संपादकीय में कहा है 'एक आर्थिक ताकत होने के साथ भारत विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी ताकत बनाने की दिशा में बड़ी छलांग लगाने को तैयार है।' संपादकीय में कहा गया है कि 2021-22 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पास विश्व की तीसरी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री थी। भारत सस्ती व जेनरिक दवाओं का अग्रणी सप्लायर है। इनमें से कुछ दवाएं विश्व में कोविड-19 महामारी से निपटने में बेहद अहम रहीं। पत्रिका का कहना है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद उन अग्रणी देशों में से एक है, जहां सबसे अधिक शोध किए जा रहे हैं। भारत में 2014 से 2021 की अवधि में विश्वविद्यालयों की संख्या 760 से बढ़ कर 1,113 हो गई है। 21 वीं सदी के दूसरे दशक में सात और आइआइटी स्थापित किए गए है। इस तरह आइआटी की संख्या 23 हो गई है। इसी अवधि में दो नए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भी स्थापित किए गए हैं। ये सफलताएं ऐसे देश ने हासिल की हैं, जिसने 2020-21 में शोध एवं विकास पर जीडीपी का 0.64 प्रतिशत खर्च किया है।

प्रतीकात्मक

पत्रिका का कहना है शोध पर भारत का 60 प्रतिशत खर्च केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा विश्वविद्यालयों से आ रहा है, करीब 40 प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्र का है। वहीं, दूसरे देशों में शोध पर निजी क्षेत्र का खर्च इससे काफी अधिक है। 2022 में यूरोपीय संघ के देशों में शोध पर खर्च में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 66 प्रतिशत थी। संपादकीय में कहा गया है कि आज भारत में कंस्ट्रक्शन, आइटी, मैन्यूफैक्चरिंग और फार्मा सेक्टर में कई ग्लोबल कंपनियां हैं। ये शोध के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया करा कर और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके देश के शोध एवं विकास में अधिक योगदान दे सकती हैं।

आज का मौसम

आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
20 अप्रैल	39.0	21.0
21 अप्रैल	38.0	22.0
नोएडा		
20 अप्रैल	36.0	23.0
21 अप्रैल	37.0	23.0
गुरुग्राम		
20 अप्रैल	36.0	24.0
21 अप्रैल	36.0	25.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ी

नई दिल्ली: आबकारी घोटाले में अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी। ईडी ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। वहीं, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जो जमानत पर बाहर हैं, भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। सिसोदिया ने 12 अप्रैल को अदालत में अंतरिम जमानत की मांग की थी, ताकि वह आगामी चुनावों के लिए प्रचार कर सकें। वहीं, अदालत ने आरोपित चनप्रीत सिंह को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। (जासं)

अब मेट्रो रेल से हथियार लेकर यात्रा कर सकेंगे जवान

नई दिल्ली: आपात स्थिति में ट्रैफिक जाम से बचने और घटनास्थल पर जल्द पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान अब हथियारों के साथ भी मेट्रो ट्रेनों से यात्रा कर सकेंगे। डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन) और मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा में तैनात सीआइएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के साथ 16 अप्रैल को हुई दिल्ली पुलिस की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। (जासं)

राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा के दो शूटर दबोचे

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के दो शूटर कृष्ण कुमार और एक किशोर को दबोच लिया है। इनके दबोचे जाने से गोदारा के इशारे पर रची जा रही एक व्यवसायी की हत्या की साजिश टल गई। शूटरों के पास से दो अत्याधुनिक पिस्टल व पांच कारतूस बरामद किए गए। गोदारा के दो शूटर ने ही हाल में अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर उन्हें डराने के मकसद से फायरिंग की थी। दोनों के पास से अवैध पिस्टल व कारतूस बरामद किया गया। (जासं)

स्वास्थ्य की स्वतंत्र जांच से क्यों कतरा रहे केजरीवाल : ईडी

सुनवाई ▶ सीएम ने शुगर लेवल में उतार चढ़ाव को लेकर प्रतिदिन 15 मिनट चिकित्सा परामर्श की मांग की

कोर्ट ने कहा-मेडिकल बोर्ड को जांच करने दीजिए कि इसके लिए क्या आवश्यकता है

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अदालत में ईडी के जेल में आम, आलू-पूड़ी और मिठाइयां खाने के आरोप का विरोध किया। उन्होंने शुगर लेबल में उतार-चढ़ाव को लेकर सप्ताह में तीन बार चिकित्सक से परामर्श करने की याचिका वापस लेते हुए एक नई याचिका दायर कर अदालत से मधुमेह और शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव को लेकर प्रतिदिन 15 मिनट के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग से चिकित्सक से परामर्श की मांग की। साथ ही अनुरोध किया कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उनकी पत्नी भी शामिल हों। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दोनों पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद फैसला 22 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया और तिहाड़ जेल अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर शनिवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

ईडी ने दावा किया था कि मेडिकल जमानत के लिए आधार बनाने के लिए टाइप-2 मधुमेह होने के बावजूद केजरीवाल आम व मिठाई जैसी मीठे वाली चीजें खा रहे थे। अदालत ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि मेडिकल बोर्ड को जांच करने दीजिए कि इसके लिए क्या आवश्यकता है। सिंघवी ने कहा वो 15 मिनट की वीसी की मांग कर रहे हैं न कि मेडिकल जमानत या अस्पताल में इलाज की मांग कर रहे हैं। ईडी के वकील जुहेब हुसैन ने कहा कि कानूनी मुलाकातों का तो पहले भी दुरुपयोग किया गया है। ये समझ नहीं आता कि केजरीवाल स्वतंत्र जांच से क्यों कतरा रहे हैं। वे ऐसी रिपोर्टें तैयार कर रहे हैं जो विशेषज्ञों की राय के अनुरूप नहीं हैं। कोई भी डाक्टर इनका सेवन करने के लिए नहीं कहेगा।

अरविंद केजरीवाल। फाइल

केवल तीन बार खाया आम : सीएम

केजरीवाल की ओर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर तुच्छ होने और जेल में केजरीवाल ने जो खाया उसका राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने जो खाना खाया वह उनके डाक्टर द्वारा तय किया गया था व आहार चार्ट के अनुरूप था। गिरफ्तारी के कारण उन्हें इंसुलिन देने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के घर से 48 बार भेजे गए भोजन में से सिर्फ तीन बार आम आए थे।

अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार : सिंघवी

ईडी के इस आरोप कि केजरीवाल जमानत पाने के लिए अपने शुगर लेवल के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, पर सिंघवी ने कहा कि ईडी के आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। यह जानते हुए कि वो अदालत को जेल अधिकारियों के इंसुलिन न देने के आचरण के बारे में बताएंगे तो इसे रोकने के लिए जेल अधिकारियों ने ईडी के साथ मिलकर मीडिया से बात करने की कोशिश की है। केजरीवाल एक कैदी हैं, क्या उन्हें सम्मानजनक जीवन व अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है?

निर्धारित डाइट चार्ट का पालन नहीं कर रहे केजरीवाल : ईडी

ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल जो खाना खा रहे थे वह उनके डाक्टर द्वारा निर्धारित डाइट चार्ट से मेल नहीं खाता। केजरीवाल के लिए निर्धारित आहार में किसी मिठाई या फल या मीठी वस्तु का कोई संदर्भ नहीं है। उनके निर्धारित आहार को देखकर ही समझ आता है कि इसमें कई खाने की चीजें प्रतिबंधित हैं।

..तो घर के खाने को बंद कर दिया जाएगा : तिहाड़ प्रशासन

तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि वह पहले इंसुलिन लेते थे, लेकिन कुछ समय से इंसुलिन लेना बंद कर दिया। डाक्टर की सलाह में ऐसा नहीं है कि खाने में कुछ फल भी होने चाहिए। केजरीवाल घर से भेजे गए भोजन में निर्धारित आहार का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्हें जिस चीज को खाने से बचना है, आम उनमें से एक है। उन्हें डाइट प्लान का पालन करना चाहिए ताकि शुगर लेवल सही रहे। ऐसा नहीं हुआ तो घर के खाने को बंद करने का आवेदन दिया जाएगा।

आम, मिठाई, चीनी पर मुख्यमंत्री के जवाब

● ईडी- **केजरीवाल प्रतिदिन आम व मिठाई खा रहे हैं।**

अभिषेक मनु सिंघवी- ये आरोप सच्चाई से बहुत दूर हैं। 48 बार घर से भेजे गए खाने में केवल तीन बार, छह, सात और आठ अप्रैल को आम भेजे गए थे। आठ अप्रैल के बाद एक बार भी आम नहीं भेजा गया। मिठाइयां शुगर फ्री थीं और इससे शुगर का स्तर नहीं बढ़ता। शुगर फ्री मिठाई भी सिर्फ छह बार आई। केजरीवाल के लगातार शुगर लेवल के बढ़ने के पीछे की असली वजह जेल अधिकारियों की ओर से उन्हें इंसुलिन देने से इन्कार करना है, जबकि वो उनके लिए जीवनरक्षक दवा है।

● ईडी- **केजरीवाल चाय में भी चीनी ले रहे हैं।**

सिंघवी- ये आरोप सरासर गलत है। केजरीवाल अपनी चाय में शुगर फ्री का उपयोग करते हैं और चाय में उन्होंने कभी भी चीनी नहीं ली। ये आरोप बिना किसी सुबूत के गैरजिम्मेदाराना तरीके से लगाया गया है।

● ईडी- **केजरीवाल आलू-पूरी खा रहे हैं।**

सिंघवी- 48 बार आए खाने में केवल एक बार केजरीवाल ने आलू-पूरी खाई थी वो भी नवरात्र का प्रसाद था। यह चौंकाने वाली बात है कि ईडी को आशंका है कि कोई व्यक्ति मेडिकल जमानत पाने के लिए जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं। वो अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे।

अदालत ने प्रत्युतर दाखिल करने का समय दिया

आबकारी घोटाले में ईडी के समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर ईडी द्वारा दायर दो शिकायत पर अदालत ने सुनवाई टाल दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के अधिवक्ता को ईडी के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया।

मुख्यमंत्री को जान से मारने की साजिश हो रही : संजय सिंह

राज्य ब्यूरो, जागरण : नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि तिहाड़ में सीएम केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही है। डाइट चार्ट को लेकर झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जान से मारने की साजिश हो रही है। संजय सिंह ने प्रेसवार्ता कर कहा कि भाजपा राजनीति के न्यूनतम पायदान पर पहुंच गई है। बृहस्पतिवार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा के नेताओं को शुगर की परेशानी नहीं है। उनसे पूछें कि इस बीमारी से उन्हें कैसे कैसे जूझना पड़ता है। जिसे शुगर हो जाता है उसे बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं। भाजपा के लोग इस तरह की राजनीति नहीं करें। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े अपराधी का इलाज एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में होता है, लेकिन तीन बार से निर्वाचित मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल प्रशासन इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है।

संजय सिंह।

अब आरएमएल के सुपर स्पेशियलिटी की ओपीडी में देखे जाएंगे रेफर मरीज

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: आरएमएल अस्पताल के कार्डियोलाजी, न्यूरोलाजी, पल्मोनरी जैसे सुपर स्पेशियलिटी विभागों की ओपीडी में अब यदि कोई मरीज सीधे पहुंच जाए तो इलाज कराना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि सुपर स्पेशियलिटी विभागों में अब सिर्फ रेफर मरीज ही देखे जाएंगे। इसका मकसद सुपर स्पेशियलिटी विभागों में मरीजों का अनावश्यक दबाव और इलाज में वेटिंग कम करना है। इस बाबत अस्पताल प्रशासन ने आदेश जारी कर सुपर स्पेशियलिटी विभागों को अमल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

अस्पताल प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से सुपर स्पेशियलिटी विभागों की ओपीडी में मरीजों का दबाव कम होगा और उन मरीजों का इलाज आसान होगा जिन्हें वास्तव में सुपर स्पेशियलिटी इलाज की जरूरत होती है। अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 6500-7500 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पहले सुपर स्पेशियलिटी विभागों में मरीज अपनी मर्जी से बीमारी के लक्षण के आधार पर सीधे पहुंचते थे।

सिर्फ सात मिनट में कनाट प्लेस से गुरुग्राम पहुंचाएगी हवाई टैक्सी

▶ **इंटरग्लोबल एंटरप्राइजेज व आर्चर एविएशन 2026 से शुरू करेंगे सेवा**

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज और अमेरिका की आर्चर एविएशन भारत में 2026 की शुरुआत में पूरी तरह इलेक्ट्रिक हवाई टैक्सी सेवा शुरू करेंगी। ये हवाई टैक्सियां यात्रियों को दिल्ली के कनाट प्लेस से हरियाणा के गुरुग्राम तक सिर्फ सात मिनट में पहुंचाएंगी। सात मिनट की उड़ान की लागत लगभग 2,000 से 3,000 रुपये हो सकती है। आर्चर एविएशन 200 'इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकआफ एंड लैंडिंग' (ईवीटीओएल) विमान उपलब्ध कराएगी। विमान में चालक के अलावा चार यात्री सवार हो सकते हैं। ये विमान कम शोर और बेहतर सुरक्षा के साथ हेलीकाप्टर की तरह चलते हैं। इन विमानों की कीमत लगभग एक अरब डालर होगी। प्रत्येक विमान में 12 'रोटर' होंगे। इंटरग्लोब और आर्चर एविएशन के संयुक्त उपक्रम के तहत दिल्ली के अलावा मुंबई और बेंगलुरु में भी ऐसी ही सेवाएं शुरू की जाएंगी।

आर्चर एविएशन के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एडम गोल्डस्टीन ने कहा कि अमेरिकी नियामक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) के साथ चर्चा चल रही है और उसके विमानों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एक बार यह लागू हो जाने पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से प्रमाणन के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी को 2026 में भारत में उड़ान शुरू करने की उम्मीद है और परिचालन के लिए 200 'मिडनाइट' विमान रखने का लक्ष्य है। कार में 27 किमी की दूरी तय करने में लगभग 90 मिनट लगेंगे।

हवाई टैक्सी। फाइल

डीयू में पीजी के लिए दाखिले की दौड़ 25 से शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ **पीजी के 82 विषयों में 13,500 सीटों के लिए किए जा सकते हैं आवेदन**

▶ **बीटेक में 120-120 सीटों पर जेईई मेन के स्कोर से होंगे प्रवेश**

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर (पीजी) में प्रवेश के लिए दाखिले की दौड़ 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। डीयू 82 विषयों में प्रवेश के लिए सामान्य सीट आवंटन प्रणाली (सीएसएएस) पोर्टल की शुरुआत करेगा। सीयूईटी परीक्षा देने वाले छात्र पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। इसके साथ ही पिछले साल शुरू किए गए बीटेक और पांच वर्षीय विधि कार्यक्रम के प्रवेश भी शुरू हो जाएंगे। बीटेक में प्रवेश जेईई मेन के अंकों और विधि कार्यक्रम में प्रवेश क्लेट के अंकों के आधार पर होंगे।

कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि डीयू स्नातकोत्तर में इस वर्ष 82 विषयों को छात्र प्रवेश के लिए चुन सकते हैं। पिछले वर्ष 77 विषयों को चुना जा सकता था। इस वर्ष एमए हिंदू स्टडीज, एमए चाइनीज, एमए कोरियन, मास्टर्स - पब्लिक हेल्थ और मास्टर्स- फाइन आर्ट के कोर्स इसमें जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि पीजी प्रवेश के लिए आवेदन 25 मई तक किए जा सकेंगे। इसके बाद प्रवेश का दूसरा चरण शुरू होगा। डीयू की डीन एडमिशन प्रो. हनीत गांधी ने 2024-25 के लिए दाखिलों पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष स्नातकोत्तर के लिए (एनसीवेब सहित) कुल 13,500 सीटों पर प्रवेश लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीयूईटी परीक्षा के स्कोर एनटीए की ओर से विश्वविद्यालय को सीधे मिल जाएंगे। छात्रों को सीएसएएस पोर्टल पर 250 रुपये शुल्क देकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। जिन छात्रों ने कालेज में प्रवेश ले लिया होगा और वे प्रवेश वापस लेंगे, तो एक हजार रुपये फीस अदा कर वे प्रवेश वापस ले सकेंगे। उनकी जमा की गई फीस वापस कर दी जएगी। छात्रों को पोर्टल पर कालेज और कोर्स के विकल्प भरने होंगे। जितने वे कालेज व कोर्स के विकल्प भरेंगे, उतना उनके लिए प्रवेश आसान होगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष बीटेक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग की शुरुआत की गई है। तीनों ब्रांच में 120-120 सीटों पर प्रवेश दिए जा रहे हैं। जईई मेन के स्कोर के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी के लिए प्रत्येक में 60-60 सीटों पर दाखिले किए जाएंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय। फाइल

मई के मध्य तक शुरू होंगे स्नातक के आवेदन

कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि स्नातक में प्रवेश के लिए सीएसएएस पोर्टल की शुरुआत मई के मध्य तक की जाएगी। पीएचडी में प्रवेश को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रवेश प्रक्रिया पुरानी तरह से होगी। यूजीसी की ओर से नेट के जरिये प्रवेश की बात की गई है। अकादमिक परिषद की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीयूईटी से प्रवेश में डीयू की ओर से पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है।

सांस्कृतिक अभियान के जरिए दस सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

▶ **एक मई को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में शुरू होगा अभियान**

▶ **नुक्कड़ नाटक एवं हिंदी-अंग्रेजी व प्रादेशिक भाषाओं में भी होंगे कार्यक्रम**

लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए भाजपा एक मई से सांस्कृतिक अभियान शुरू करेगा। जिसमें नुक्कड़ नाटकों के साथ ही कठपुतली और जादूगर शो, कवि गोष्ठी, म्यूजिक बैंड के माध्यम से जनता को नरेन्द्र मोदी सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार एवं कुशासन पर इसके माध्यम से प्रहार किया जाएगा।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को सांस्कृतिक अभियान से जुड़े कलाकारों की प्रस्तुति देखी। इसके बाद प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाले विभिन्न राज्यों के लोगों का ध्यान रखते हुए नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रम हिंदी के साथ अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषाओं में आयोजित होंगे। यह अभियान एक मई को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में प्रारंभ होगा।

जनता को अपनी उपलब्धि गिनाने व जागरूक करने के साथ वोट करने की अपील के लिए शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में नुक्कड़ नाटक का आडिशन देते कलाकार। चंद्र प्रकाश मिश्र

कलाकारों की 163 टीमें तैयार, आठ हजार नुक्कड़ नाटक-कार्यक्रम होंगे: नुक्कड़ नाटक समिति के सदस्य अनुज शर्मा ने कहा कलाकारों की 163 टीमें तैयार की गई हैं। एक से 23 मई आठ हजार नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रम होंगे।

हिंदू नववर्ष उत्सव में पांच हजार से अधिक संत-महात्मा पहुंचेंगे: पुजारी प्रकोष्ठ के संयोजक करनैल सिंह ने बताया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में 21 अप्रैल को हिंदू नववर्ष उत्सव मनाया जाएगा। जिसमें पांच हजार से अधिक संत-महात्मा शामिल होंगे। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा। भजन गायक हंसराज रघुवंशी अपनी प्रस्तुति देंगे।

अश्विनी को वक्फ बोर्ड प्रशासक पद से हटाने को दायर की याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रधान सचिव (गृह) अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक पद से हटाने की मांग की गई है और उन पर वक्फ बोर्ड के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने 30 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिका में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड का प्रशासक उस धार्मिक समिति का अध्यक्ष भी है जिसने कई वक्फ संपत्तियों को हटाने और ध्वस्त करने की सिफारिश की है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि किसी संगठन में प्रशासक की नियुक्ति संगठन के कल्याण और बेहतरी के लिए की जाती है। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक वक्फ संपत्तियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। सेक्युलर फ्रंट आफ लायर्स द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि रक्षा करने के बजाय, वह वक्फ संपत्तियों को नष्ट करने के लिए बैठे हैं।

सिंघु फ्लाईओवर से हटाए अवरोधक, हरियाणा का रास्ता खुलने की उम्मीद

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली

▶ **शुक्रवार देर शाम तक फ्लाईओवर की दो लेन से हटाए गए अवरोधक**

▶ **फ्लाईओवर को खुलने में अभी लग सकता है दो दिनों का समय**

किसानों के दिल्ली कूच के एलान के बाद सिंघु बार्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। 66वें दिन बुधवार सुबह से मुख्य मार्ग (फ्लाईओवर) खोलने का काम जारी है। फिलहाल, चार-चार लेन वाले मुख्य मार्ग की केवल दो-दो लेन ही दोनों तरफ खुलेंगी।

शुक्रवार देर शाम तक दिल्ली से हरियाणा की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग से सीमेंट के बैरिकेड्स समेत तमाम तरह के अवरोधक हटा लिए गए हैं। केवल दो लेयर में दिल्ली पुलिस के लोहे के बैरिकेड्स ही लगे हैं। पुलिस सूत्रों की मानें तो आलाधिकारियों के आदेश मिलते ही दिल्ली से हरियाणा जाने वाली दो लेन खोल दी जाएंगी, वहीं हरियाणा से दिल्ली की ओर आने वाले मुख्य मार्ग से अभी बैरिकेड्स हटाने का काम शुरू नहीं हो सका है। बाहरी-उत्तरी जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि काम काफी तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि सबसे पहले दिल्ली से हरियाणा की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग की दो लेन जल्द ही वाहन चालकों के लिए खोल दी जाएंगी। रास्ता खोलने के लिए लगातार कई क्रेन व अर्थ मूवर्स मशीनें काम कर रही हैं। हालांकि हाइवे पर सीमेंट व कंक्रीट से जाम किए गए बैरिकेड्स तोड़ने में समय लग रहा है। जर्सी बैरियर के बीच कंक्रीट व सीमेंट के घोल से बनाई गई दीवारें तोड़ने में कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सिंघु बार्डर स्थित फ्लाईओवर पर सड़क से दो लेन से अवरोध हटाए गए। जागरण

पीड़ित को मुआवजा देकर अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दो पक्षों के बीच समझौते के आधार पर हत्या के प्रयास की प्राथमिकी को रद करने से इन्कार करते हुए कहा कि आपराधिक कानून समाज के भीतर व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करने का प्रयास करता है और किसी अपराध को मुआवजे के भुगतान से खत्म नहीं किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने आरोपित व्यक्तियों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) जैसा गंभीर अपराध दोहराया न जाए और समझौता अधिक अपराध को बढ़ावा न दे। याचिकाकर्ताओं ने गुण-दोष के आधार पर आरोपों को स्वीकार किए बिना, 2019 में दर्ज की गई प्राथमिकी को इस आधार पर रद्द करने की मांग की, कि मामला उनके और पीड़ित के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, जिसे मुआवजा दिया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट की टीम ने कोचिंग सेंटर का लिया जायजा

मुखर्जी नजर

विशेष टीम ने 18 से अधिक कोचिंग सेंटर का दौरा किया और जानकारी हासिल की, सेंटर संचालक व छात्र-छात्राओं से भी बात की

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट की विशेष टीम ने शुक्रवार को मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया। दिल्ली दमकल सेवा के अधिकारियों के साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की टीम ने मुखर्जी नगर में चल रहे 18 से अधिक कोचिंग सेंटर का दौरा किया और जानकारी हासिल की। टीम क्षेत्र में चल रहे कोचिंग सेंटर की संख्या के अलावा स्थिति रिपोर्ट के बारे में हाई कोर्ट को अवगत कराएगी।

शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की टीम दिल्ली दमकल विभाग के अधिकारियों के साथ मुखर्जी नगर पहुंची। टीम ने बत्रा कांप्लेक्स के पास चल रहे कोचिंग सेंटर की जांच शुरू की। विशेष टीम ने कोचिंग सेंटर की फोटोग्राफी की और सेंटर संचालक व छात्र-छात्राओं से भी बात की। दोपहर बाद टीम ने जीटीबी नगर स्थित कोचिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया। टीम के वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया जा रहा है। अब तक 18 से अधिक कोचिंग सेंटर का दौरा किया जा चुका है। निरीक्षण के बाद पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी। इससे पहले कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है।

जीटीबी नगर स्थित कोचिंग सेटर में निरीक्षण के लिए जाती दिल्ली हाईकोर्ट से गठित अधिवक्ताओं व दिल्ली दमकल सेवा की टीम। जागरण

हाई कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने को कहा

पिछले साल 15 जून को कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वत : संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कराया था। पांच अप्रैल की सुनवाई के दौरान एमसीडी ने कोर्ट को अवगत कराया था कि नियमों का पालन न करने के कारण छह कोचिंग सेंटर को सील किया गया है और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी ने बताया कि 21 सेंटर अपने आप बंद हो गए और 20 से ज्यादा को सील करने के नोटिस दिए गए हैं। न्याय मित्र व अधिवक्ता गौतम नारायण ने कहा कि कुछ सेंटर ने अपना संचालन बंद कर दिया है। हो सकता है कि उनके स्थान पर नए खुल गए हों। इस पर हाई कोर्ट की पीठ ने संबंधित क्षेत्र के सत्यापन का स्वतंत्र अभ्यास करने व कोचिंग सेंटर के बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा।

बीते पांच अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान न्याय मित्र गौतम नारायण के नेतृत्व में स्वतंत्र निरीक्षण टीम के गठन करने के निर्देश के साथ और क्षेत्र में चल रहे कोचिंग सेंटर की कुल संख्या के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था। टीम को यह भी जांचने का निर्देश दिया गया कि एकीकृत भवन उपनियम-2016 व दिल्ली मास्टर प्लान-2021 का कितने कोचिंग सेंटर अनुपालन कर रहे हैं।

****

कह कर रहेंगे माधव जोशी

1939 में नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक नामक दल का गठन किया था। स्वतंत्रता के पश्चात नेताजी के भाई शरतचंद्र बोस इस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता के तौर पर सक्रिय रहे।

अपनी लोकप्रियता और बजरंगबली के सहारे नवनीत राणा

ओमप्रकाश तिवारी ● जागरण

अमरावती: मुंबई महिला आरक्षण का हो या कोई और, राष्ट्रहित में प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखनेवाली 17वीं लोकसभा की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा इस बार महाराष्ट्र के अमरावती क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार हैं। 2019 में जब वह इसी सीट से चुनकर संसद में पहुंचीं तो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हंसकर पूछा था कि मेरी इतनी जबर्दस्त लहर में आप निर्दलीय कैसे चुनकर आ गईं ? इस बार उसी फायर ब्रांड निर्दलीय सांसद को भाजपा ने इस सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया, जहां से कभी वह लोस का चुनाव लड़ी ही नहीं। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

38 वर्षीय नवनीत की स्कूली शिक्षा मुंबई से हुई है। इसके बाद उन्होंने माडलिंग का कैरियर चुना। फिर दक्षिण भारत की कई फिल्मों में अभिनय कर खुद को सिने जगत में स्थापित किया। अमरावती से निर्दलीय विधायक रवि राणा से विवाह करने के बाद राजनीति उन्हें भी भा गई और वह 2014 का लोस चुनाव अमरावती से राकांपा के टिकट पर लड़ गईं, लेकिन तब उन्हें शिवसेना प्रत्याशी आनंदराव अडसुल से पराजित होना पड़ा। 2019 में इसी सीट से राकांपा का ही समर्थन लेकर जब निर्दलीय लड़ीं तो उन्होंने अडसुल को करीब 37000 मतों से पराजित कर दिया।

पहली बार संसद में पहुंचने के बाद ही वह समझ गईं कि भविष्य राष्ट्रवाद का है। यही कारण है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के समर्थन से चुनकर आने के बावजूद उन्होंने भाजपा की भाषा बोलनी शुरू कर दी। यहां तक कि महाराष्ट्र में चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा कर दी। वह वहां हनुमान चालीसा पढ़ तो नहीं पाईं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार जरूर होना पड़ा। इस घटना ने उनकी छवि एक प्रखर हिंदूवादी की बना दी, लेकिन उनकी यह हनुमानभक्ति स्टंट मात्र नहीं थी। वह अपने चुनाव क्षेत्र से लेकर अपनी हवाई यात्राओं तक में हनुमान चालीसा का पाठ करती देखी जाती हैं। उनके घर में जगह-जगह हनुमानजी की मूर्तियां सम्मान पा रही हैं। वह और उनके पति अमरावती के बाहरी क्षेत्र में 22 मीटर ऊंची एक हनुमान मूर्ति बनवा रहे हैं। अगले वर्ष तक इसके तैयार हो जाने की संभावना है, लेकिन राजनीति के मैदान में कई और चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। मूलरूप से यह सीट कांग्रेस के वर्चस्व वाली रही है।

चर्चित सीट अमरावती

- पिछली बार एकमात्र निर्दलीय सांसद चुनी गई थीं नवनीत
- भाजपा ने पहली बार इस सीट पर उतारा है अपना प्रत्याशी

लोकप्रियता के साथ यह पहलू है उनके पक्ष में

नवनीत के पक्ष में एक बात यह जाती है कि वह अमरावती में खासी लोकप्रिय हैं। कोई भी उत्सव या त्योहार हो, वह खुद लोगों के बीच जाकर सक्रिय भाग लेती हैं। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा अमरावती के हिंदुओं में अंदर-अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। वह है राजस्थान में हुए कन्हैयालाल की हत्या जैसा ही उमेश कोल्हे की हत्या का मामला। शिवसेना नेता नानकराम नेभनानी कहते हैं कि लोग इस निर्मम हत्याकांड को भूले नहीं हैं।

अनुसूचित जाति : मिल रहा किस्मत का साथ

नवनीत राणा को किस्मत का साथ भी मिल रहा है। दरअसल, नामांकन से पहले जब यह सवाल खड़ा हो रहा था, उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया। कोर्ट ने उनके अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र को सही करार दिया। इससे पहले उनके इस प्रमाण-पत्र को बांबे हाई कोर्ट खारिज कर चुका था।

1952 से 1984 तक यहां से लगातार कांग्रेस का ही सांसद चुना जाता रहा है। शुरुआती तीन चुनाव तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कृषिमंत्री रहे पंजाबराव देशमुख ही जीते। 1991 का चुनाव इसी सीट से प्रतिभाताई पाटिल जीतीं, जो बाद में देश की राष्ट्रपति भी बनीं। 1996 से इस सीट पर शिवसेना का प्रभाव बढ़ने लगा। तीन चुनाव यहां से शिवसेना नेता अनंत गुढे जीते। उसके बाद 2009 और 2014 का चुनाव शिवसेना के ही आनंदराव अडसुल जीत चुके हैं। शिवसेना में विभाजन के बाद अडसुल उद्धव ठाकरे के साथ छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में आ गए थे, लेकिन जब भाजपा ने यहां से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर दांव लगाने की सोची तो सीट समझौते में यह सीट इस बार भाजपा के पास आ गई। इससे अडसुल की नाराजगी स्वाभाविक थी। इस लोस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली छह में से तीन विस सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होना भी राणा के लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने लोस का टिकट भी अपने कांग्रेस के ही एक विधायक बलवंत वानखड़े को ही दिया है।

बलवंत वानखड़े

राह में रोड़े भी बहुत: इसके अलावा जिले के एक और दबंग विधायक बच्चू कडू भी राणा का जमकर विरोध कर रहे हैं। उनकी प्रहार जनशक्ति पार्टी के दो विधायक हैं। उन्होंने शिवसेना (उद्धव गुट) के एक नेता दिनेश बूब को अपनी पार्टी का टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। बाकी, इस सीट के अंतर्गत आने वाले छह विधायकों में से सिर्फ एक उनके पति रवि राणा ही उनके पक्ष में हैं। इसके अलावा स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं की भी नवनीत राणा की उम्मीदवारी को लेकर बहुत खुश नहीं हैं। वह उन्हें 'बाहरी' उम्मीदवार मान रहे हैं। स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास प्रदेश भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। इतना ही नहीं, शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल को मनाने खुद नवनीत राणा उनके घर जा चुकी हैं।

अतीत के आईने से

...जब भ्रष्टाचार बन गया सबसे बड़ा मुद्दा

1989 के लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं है कि अन्य मुद्दों की चर्चा नहीं हुई या जाति, धार्मिक आधार पर गोलबंदी और क्षेत्रीयता के सवाल नहीं उभरे, लेकिन इन सब पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुआई में जारी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम भारी पड़ी। अप्रैल 1987 में निकला बोफोर्स का जिन्न दो वर्ष बाद मई 1989 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी विकराल रूप में था। यह बाद में भी वर्षों तक गांधी परिवार और कांग्रेस का पीछा करता रहा।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी पर यह मुद्दा बहुत भारी पड़ा। बोफोर्स तोपों की दलाली के मुद्दे ने राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि को नष्ट कर दिया। मामला सामने आने से सिर्फ चार वर्ष पहले वर्ष 1984 में उन्होंने लोकसभा के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। तब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 414 सीटों पर विजय पाई थी, लेकिन वर्ष 1989 में यह सत्ता से बाहर हो गई। तब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 197 सीटें मिलीं। जनता दल 143, भाजपा 85 और वाम मोर्चा 45 सीटों पर जीता। केंद्र में अगली सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनता दल की बनी, जिसे भाजपा और वाम मोर्चा व अन्य दलों ने बाहर से समर्थन दिया था।

महासमर से जुड़ी खबरों और सामग्री को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

चुनावी कानाफूसी

... तो इसलिए बाबूजी की बिटिया ने साधा मौन

सहृदय राजनीतिकों में पहली पांत वाले बाबूजी (जगजीवन राम) की बराबरी बिरादरी का कोई दूसरा नेता आज तक न्हीं कर सका। सासाराम से वह कई बार सांसद रहे। पुत्री मीरा कुमार को राजनीति विरासत में मिली और उन्होंने उसे संभाला भी। सौम्य स्वभाव और सरल हृदय की हैं। इस बार भी कांग्रेस उन्हें सासाराम के मैदान में उतारने वाली थी, लेकिन चुनावी राजनीति से उन्होंने स्वतः संन्यास लेने की घोषणा कर दी। दबे स्वर में बढ़ती उम्र को कारण बताया गया और दूसरों को अवसर देने की इच्छा। दूसरों में पार्टी के विधायक मुरारी गौतम पहली पसंद थे, जो भाजपा की राह हो लिए। दूसरे दावेदार बिटिया को सुहा न्हीं रहे। इसका असली कारण काराकाट है, जिसे बिटिया अपने पुत्र अंशुल अविजीत के लिए चाहती थी। काराकाट को राजद ने अपने पास रख लिया। अंशुल को पटना साहिब का भरोसा दिया गया, जहां उनसे प्रबल कई दावेदार उठ खड़े हुए हैं। बताते हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस इकाई के एक दिग्गज ही पुराने दिग्गजों की चूलें हिलाने में लगे हैं। अब बिटिया ने मौन साध लिया है।

कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती

लोकसभा चुनाव: केरल में पार्टी के वोटबैंक पर निगाह टिकाए हुए हैं सीपीएम और भाजपा

नीलू रंजन ● जागरण

तिरुअनंतपुरम: पिछले लोकसभा चुनाव में केरल में लगभग क्लीन स्वीप करने वाली कांग्रेस को इस बार सीपीएम व भाजपा दोनों तरफ से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दोनों की कांग्रेस के वोटबैंक पर नजर है। सीपीएम जहां उसके मुस्लिम वोटबैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है, वहीं भाजपा ईसाई मतदाताओं को साधने में जुटी है। दोतरफा चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस संभल-संभल कर कदम बढ़ा रही है। 2019 में राज्य में कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ 19 सीटें जीतने में सफल रही थी। सत्तारूढ़ सीपीएम के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी। लोस की 20 सीटों वाले केरल में भाजपा अभी तक खाता नहीं खोल पाई है।

केरल में मुस्लिम 28 प्रतिशत और ईसाई लगभग 18 प्रतिशत हैं। जाहिर है केरल की राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित करने में इनकी अहम भूमिका है। ईसाई वोटबैंक मुख्यरूप से कांग्रेस के पास है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में मुस्लिम वोटबैंक भी काफी हद तक जुड़ जाता है। 2019 में कांग्रेस को मिली सफलता इन्हीं दोनों वोटबैंक के एक साथ आने का परिणाम था, लेकिन दो साल बाद ही विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पी. विजयन के नेतृत्व में सीपीएम मुस्लिम वोटबैंक में सेंध लगाने में सफल रही। इस बार सीपीएम की कोशिश मुस्लिम मतों का बड़ा हिस्सा हथियाने की है। यही कारण है कि सीपीएम मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस से कहीं ज्यादा आक्रामक दिख रही है। सीपीएम सीएए और गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले का खुलकर विरोध कर रही है। सीपीएम के सभी बड़े नेता चुनावी सभाओं में इन्हें उठा रहे हैं और इन मुद्दों पर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं।

दूसरी तरफ भाजपा ईसाई समुदाय का दिल जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईसाई धर्मगुरुओं से मुलाकात और ईसाई समुदाय के साथ उनके उत्सवों में शामिल होने से शुरू हुआ सिलसिला अब घर-घर जाकर समुदाय के लोगों से मिलने तक पहुंच गया है। केरल में भाजपा की इन कोशिशों का असर भी दिख रहा है। पिछले साल मार्च में थलास्सेरी के रोमन कैथोलिक चर्च के आर्क बिशप मार जोसेफ पलम्पलानी ने साफ कर दिया था कि भाजपा ईसाई समुदाय के लिए अछूत नहीं है और उन्होंने ईसाई वोटों को रबर के समर्थन मूल्य से जोड़ दिया था। केरल में मुस्लिम कट्टरवाद को ईसाई समुदाय अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले से लेकर रूस में हुए इस्लामिक इस्टेट खुरासान प्रांत के आतंकी हमलों के खिलाफ मोदी सरकार की प्रतिक्रिया ईसाई समुदाय की भावनाओं के अनुरूप है, जबकि सीपीएम और कांग्रेस का रुख उल्टा रहा है। लव जिहाद पर आधारित फिल्म 'द केरल स्टोरी' भाजपा के लिए ईसाई वोटबैंक को लुभाने का नया जरिया बन गया है। वैसे कांग्रेस व सीपीएम इसे प्रोपेगंडा फिल्म बताकर लव जिहाद जैसी किसी समस्या को सिरे से खारिज कर रही है, पर कई ईसाई संगठनों द्वारा इसे प्रदर्शित करने से साफ है, उनके लिए यह अहम मुद्दा है। इसके पहले इस महीने के शुरू में दूरदर्शन पर यह फिल्म दिखाई गई थी, जिसका कांग्रेस-सीपीएम ने विरोध करते हुए भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया था।

19 सीटें कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ जीतने में सफल रही थी राज्य में 2019 के लोकसभा चुनाव में

1 सीट ही सत्तारूढ़ सीपीएम के खाते में आई थी पिछले चुनाव में, भाजपा को खाता खोलने में भी नहीं मिली थी सफलता

कांग्रेस उठा रही मणिपुर हिंसा का मुद्दा

'द केरल स्टोरी' की काट के लिए कांग्रेस मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठा रही है और मैतेयी व कूकी समुदाय के बीच नस्ली हिंसा के बजाय इसे ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा के रूप में पेश कर रही है। ईसाई से जुड़े कुछ संगठन मणिपुर हिंसा पर आधारित डाक्यूमेंट्री को भी प्रदर्शित कर रहे हैं।

ईसाई समुदाय को नहीं नाराज करना चाहती कांग्रेस

कांग्रेस ईसाई समुदाय को नाराज किये बगैर मुस्लिम वोटबैंक को साधने की कोशिश में है। यही कारण है कि वायनाड में राहुल गांधी के नामांकन के दौरान कांग्रेस ने अपने सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा नहीं फहराने का फैसला किया। इसकी वजह से मुसलमानों में होने वाली नाराजगी को देखते हुए उसने अपना झंडा भी नहीं लगाया। वायनाड में 45 % मुस्लिम, 13 %ईसाई और 42 % हिंदू आबादी है।

35 वर्ष में भाजपा ने तय की दो से तीन सौ पार सीटों की यात्रा

भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 2024 में अपने लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा है और जनता के बीच इसको संदेश के रूप में भी प्रचारित कर रही है। राजग के लिए उसने 400 पार का लक्ष्य तय किया है। 1984 वह वर्ष है, जब केवल चार वर्ष पहले गठित भाजपा ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़कर मात्र दो सीटें जीती थीं। इस चुनाव में कांग्रेस ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए 414 सीटों पर विजय पाई थी। वर्ष 1984 से 2019 के लोस चुनाव तक की अपनी 35 वर्ष की चुनावी यात्रा में भाजपा 300 लोस सीटों का आंकड़ा पार करने में सफल रही है। पिछले लोस चुनाव में भाजपा ने 303 सीटें प्राप्त की थीं। जबकि कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई। बहुमत की बात करें तो भी वर्ष 1984 के बाद भाजपा ही ऐसी पार्टी है, जिसने दो बार अकेले दम पर जरूरी 272 का आंकड़ा पार किया है। 2014 में उसने 282 सीटें जीती थीं।

6 बार कांग्रेस ने पार किया है 300 सीटों का आंकड़ा। 1952 में 364, 1957 में 371, 1962 में 361, 1971 में 368, 1980 में 353 और 1984 में 414 सीटें

इसलिए कांग्रेस को मिला था बड़ा जनादेश
1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 414 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। यह लोकसभा चुनाव के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। यह चुनाव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस को सहानुभूति के रूप में यह जनादेश मिला था।

गोरखालैंड-ग्रेटर कूचबिहार का मुद्दा गौण

भारतीय बसंत कुमार ● जागरण

दार्जिलिंग : तीस्ता नदी में कुछ दिन पूर्व आई आपदा के निशान अभी शेष हैं। पहाड़ पर जाने वाली सड़कों पर जगह-जगह निर्माण के साथ ही सिक्किम को रेल लाइन से जोड़ने का काम तेज गति से चल रहा है। सुरंग के वह मुहाने अब दिखने लगे हैं, जिस रास्ते साल-दो साल में ट्रेन गुजरेगी। चुनावी झंडे-पोस्टर के साथ भारत निर्वाचन आयोग के मतदान की अपील वाले पोस्टर भी पहाड़ पर जगह-जगह टंगे हैं। मैदान से पहाड़ तक नेपाली में बैनर टंगे हैं। सुभाष घीसिंग के बाद गोरखालैंड आंदोलन के तीन बड़े चेहरे में विनय तामांग, अनित थापा और बिमल गुरुंग में कोई भी इस चुनाव में उम्मीदवार तो नहीं हैं, लेकिन तीनों मैदान में डटे हैं। तीनों की तीन राहें हैं। इस चुनाव में अगर कुछ खोया-खोया सा है तो वह है गोरखालैंड, ग्रेटर कूचबिहार या फिर कामतापुर राज्य का मुद्दा है।

यह अलग बात है कि भाजपा के ही एक विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा उर्फ बीपी बजगाईं ने दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी राजू बिष्ट के खिलाफ नामांकन किया है और अलग राज्य के स्वर को अलापा है। समग्रता में उत्तर बंगाल में गोरखालैंड, कामतापुर राज्य और ग्रेटर कूचबिहार का मुद्दा साढ़े तीन दशक बाद चुनाव में गौण है। इस मुद्दे पर मतदाता से लेकर नेता तक मौन हैं।

कभी सुभाष घीसिंग की अगुआई का आंदोलन अब राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही स्तर पर नेपथ्य में चला गया है। आखिरी बार 2017 में जिस प्रकार का 104 दिनों का अशांत आंदोलन चला, उसके हासिल में केवल अराजकता, हिंसा और उपद्रव होने से अब स्थानीय लोग भी इस मुद्दे को गौण मानकर मौन हैं। अपने नेता सुभाष घीसिंग से अलग होकर बिमल गुरुंग ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा गठित किया था। उस समय विनय तामांग और अनित थापा जैसे नेता बिमल गुरुंग के साथ थे। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा बनाकर अनित थापा ने अपनी राजनीतिक धारा अलग कर ली है। तृणमूल को समर्थन देकर और ममता बनर्जी का समर्थन हासिल कर थापा ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का चुनाव जीत लिया। बिमल गुरुंग से अलग हुए विनय तामांग कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता हो गए। बिमल गुरुंग सुभाष घीसिंग से जिस विनय तामांग और अनित थापा को लेकर मजबूती से अलग हुए थे और 2017 का बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया। विनय के अलग होने के बारे में यह धारणा बनी कि ममता के असर से संगठन में फूट पड़ी। 2017 में ही तामांग को गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) का अध्यक्ष बना दिया गया। इधर, बिमल गुरुंग पर सरकार ने सख्ती की। वह मुकदमों से घिरे और भूमिगत रहे। इस समय भाजपा के लिए पसीना बहा रहे बिमल तीन वर्षों तक भूमिगत रहने के बाद 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन पर वापस हुए तब इनका झुकाव तृणमूल की ओर हुआ। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता ने इनकी क्षमता का आकलन किया, लेकिन बाद में ममता ने बिमल से ज्यादा महत्व अनित थापा को दिया। जीटीए चुनाव में अनित थापा के बाजी मारने और निकाय चुनाव में भी बिमल के प्रभावी नहीं होने से तृणमूल में इनकी पैठ नहीं बनी। बिमल इन दिनों फिर से भाजपा संग हैं। भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट का समर्थन मांग रहे हैं। अनित थापा तृणमूल के गोपाल लामा के लिए डटे हैं।

देश की तरक्की के लिए शांति जरूरी- बिमल: बिमल से सीधी बात होती है। यह पूछने पर कि पहली बार आपके संकल्प पत्र में गोरखालैंड का मुद्दा क्यों गायब है? बोलते हैं कि पिछले चुनावों तक में संकल्प-पत्र में यह मुद्दा था। बार-बार रखने मात्र से कुछ हुआ नहीं। उन्हें भाजपा नेताओं पर भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकेत किया है कि इस क्षेत्र का सम्यक विकास होगा। बिमल जोड़ते हैं कि उनका मकसद उनकी जाति के लोगों की खुशहाली और विकास है। यह पूछे जाने पर कि सबसे लंबे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले तीनों नेताओं की राह अलग हो गई और नेतृत्व का बिखराव हो गया, अब कोई आंदोलन खड़ा होना मुश्किल है। बिमल आरोप अनित थापा और विनय तामांग पर मढ़ते हैं। कहते हैं कि आंदोलन के बाद पांच हजार युवाओं का घर तबाह होने लगा। मुकदमों और अन्य कारणों से उनकी जाति के युवा संकट में घिरे थे। ममता सरकार ने दमन किया। हमने इन्हीं युवाओं का भविष्य देखकर ममता से बातचीत का रास्ता निकाला। उम्मीद है कि केंद्र सरकार कोई राह निकालेगी और फिर से नए आंदोलन की जरूरत नहीं रह जाएगी। बिमल का मानना है कि देश की तरक्की और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यहां की शांति बहुत जरूरी है।

ग्राउंड रिपोर्ट दार्जिलिंग

- गोरखालैंड आंदोलन के तीनों नेताओं की हुईं तीन राहें
- बिमल गुरुंग, अनित थापा और विनय तमांग तीन दलों में

बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाली रेल लाइन का कार्य इन दिनों प्रगति पर है ● जागरण

पहाड़ के लोग आंदोलन नहीं, शांति चाहते : शेंगडोमा

दार्जिलिंग में अपर काट रोड के मतदाता मानबहादुर व अनुशैना थापा रानीवन गांव में रहते हैं। दोनों का मानना है कि गोरखालैंड आंदोलन जनता की लड़ाई थी, पर अब नेताओं से भरोसा उठ गया। अपरइच्छे गांव की शेंगडोमा कहती हैं कि पहाड़ के लोग आंदोलन नहीं, शांति चाहते हैं। ग्रेटर कूचबिहार को एजेंडा बनाने वाले भाजपा के ही राज्यसभा सदस्य अनंत महाराज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संदेश के बाद असंतुष्ट होकर मौन हैं। कामतापुरी भाषा अकादमी में भी सदस्य लगातार त्याग-पत्र दे रहे हैं।

पार्टी लाइन से अलग हुए तो हटा ली गई केंद्रीय सुरक्षा

अब अंत में बात उस विधायक की जो दार्जिलिंग में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में है। कार्सियांग के भाजपा विधायक बीपी बजगाई कहते हैं कि जेपी नड्डा से कोलकाता में स्पष्ट बात की। उन्होंने गोरखालैंड के मुद्दे पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमारा मकसद भी अपनी जाति की पहचान है। हमने खतरा मोल लिया है। जो केंद्रीय सुरक्षा मुझे दी गई थी पार्टी लाइन से अलग होने पर वह वापस कर ली गई। फिर भी एजेंडे पर मैं कायम हूं। बिमल गुरुंग इसे पर्सनल एजेंडा और असरहीन मानते हैं।

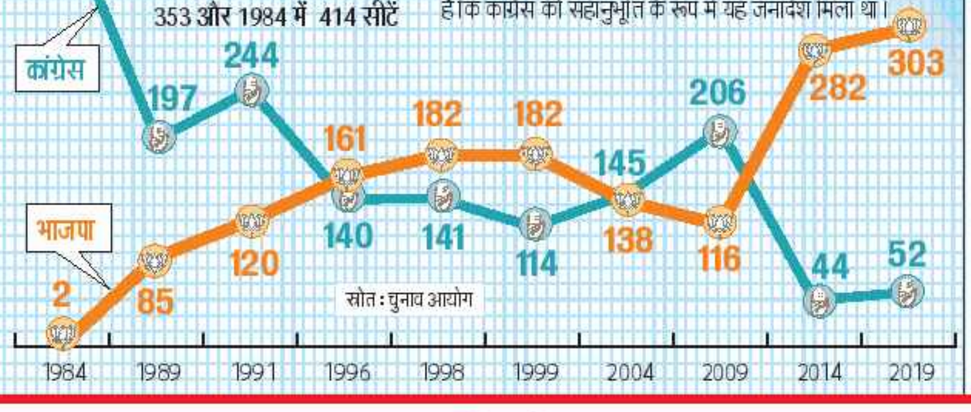

भारत में लोकतंत्र के उत्सव में चीनी मूल के नागरिक भी भागीदार

राजीव कुमार झा ● जागरण

कोलकाता : चीन में भले ही कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में नागरिकों का मताधिकार का अधिकार बेहद सीमित हो, लेकिन भारत में रहने वाले चीनी मूल के नागरिक खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि वे यहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। उन्हें यहां न सिर्फ सभी नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, बल्कि वोट देने व सरकार चुनने तक का अधिकार मिला हुआ है। हम बात कर रहे हैं बंगाल की राजधानी कोलकाता में कई पीढ़ियों से रह रहे चीनी मूल के लोगों की, जिनमें आम भारतीयों की तरह ही इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उत्सुकता है।

कोलकाता के टेंगरा इलाके में स्थित चाइना टाउन, जहां सबसे ज्यादा चीनी मूल के लोग रहते हैं, वहां की निवासी 70 वर्षीय मोनिका लियू कहतीं हैं- भले ही हमारी जड़ें चीन में रही हों, लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि अब भारतीय नागरिक के तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाती हूं। हम लोग भले यहां अल्पसंख्यक हैं, लेकिन सरकार चुनने में मेरी भी भूमिका रहती है। इससे गर्व महसूस होता है। भारत का लोकतंत्र और मजबूत होना चाहिए। चीन में भी लोकतंत्र होता तो अच्छा होता। यह जानकर बहुत खराब लगता है कि जिस देश में हमारी जड़ें हैं, वहां के लोगों को सरकार चुनने का अधिकार नहीं है। लियू महिला उद्यमी हैं और यहां वह कई रेस्तरां की मालकिन हैं, जिसमें मशहूर बीजिंग रेस्तरां भी है। उनकी तीन पीढ़ियां यहीं रहती आई हैं।

मुंबई के बाद कोलकाता में रहते हैं सबसे ज्यादा चीनी: मुंबई के बाद कोलकाता में सबसे ज्यादा चीनी मूल के लोग रहते हैं। लियू बताती हैं कि पहले कोलकाता में चीनी मूल के 50 हजार से ज्यादा लोग थे। इनमें चाइना टाउन के अलावा मध्य कोलकाता के टेरिटी बाजार में उनकी सबसे बड़ी आबादी थी। चाइना टाउन में 20 हजार से अधिक चीनी मूल के लोग रहते थे, पर अब यह संख्या बमुश्किल 2,000 रह गई है। पिछले कुछ दशक में ज्यादातर लोग कनाडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया व अन्य देशों में चले गए हैं। ज्यादातर लोग चमड़ा उद्योग से जुड़े थे। वर्ष 2000 के आसपास प्रदूषण पैदा करने वाले सैकड़ों उद्योगों को बंद कर कोलकाता से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया तो आजीविका के नुकसान से इन लोगों विदेश का रुख किया। अब ज्यादातर बुजुर्ग और स्थापित उद्यमी ही यहां रहते हैं। ये लोग द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद रोजगार की तलाश में आए थे और यहीं के होकर रह गए।

कोलकाता के चाइना टाउन में स्थित बीजिंग रेस्तरां ● जागरण

इनकी जुबान पर भी है पीएम मोदी का नाम

यह पूछे जाने पर कि लोकसभा चुनाव में चीनी मूल के लोगों का क्या मुद्दा होगा, इस पर ज्यादातर विकास को ही प्रमुख मुद्दा बताते हैं। **मोनिका लियू** सहित कई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी तारीफ की। लियू ने कहा- मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि मोदी अगर 10- 15 वर्ष पहले आ गए होते तो आज देश का नक्शा ही बदल गया होता।

ये भी वोटर

चीन में लोकतंत्र न्हीं है। चीन और भारत में बहुत फर्क है। चीन में जनता सरकार से डरती है। भारत में जनता से सरकार डरती है। गर्व होता है मैं भारत का नागरिक हूं। मेरी कई पीढ़ियों ने यहां जिंदगी बिताई है।

– **हेनदुई**, रेस्तरां संचालक, चाइना टाउन

पीएम मोदी एक मजबूत नेता हैं। पूरी दुनिया में उनका नाम है। वह देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। चीन में लोगों को आजादी न्हीं है, लेकिन भारत में बहुत आजादी है। चुनाव में वोट मैं विकास पर ही करूंगी।

– **मार्गरेट**, चाइना टाउन निवासी

अनेक उद्योग बंद होने से हमारे बहुत सारे लोग यहां से चले गए। सरकार को यहां कई पीढ़ियों से रह रहे चीनी मूल के नागरिकों के रोजगार व व्यवसाय की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

– **यू सिन लिआऊ**, चाइना टाउन निवासी

****

1000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं द्रमुक और अन्नाद्रमुक ने कोयंबटूर में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष एवं कोयंबटूर से पार्टी प्रत्याशी के अन्नामलाई ने यह आरोप लगाया।

लोकतंत्र के रंग

लोकसभा चुनाव- 2024 के पहले चरण में नये शादी-शुदा जोड़ों, पहली बार के युवा वोटरों, विश्व की सबसे छोटी महिला, दिव्यांगों, महिलाओं व बुजुर्गों में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। कुछ खास पलों की तस्वीरें :

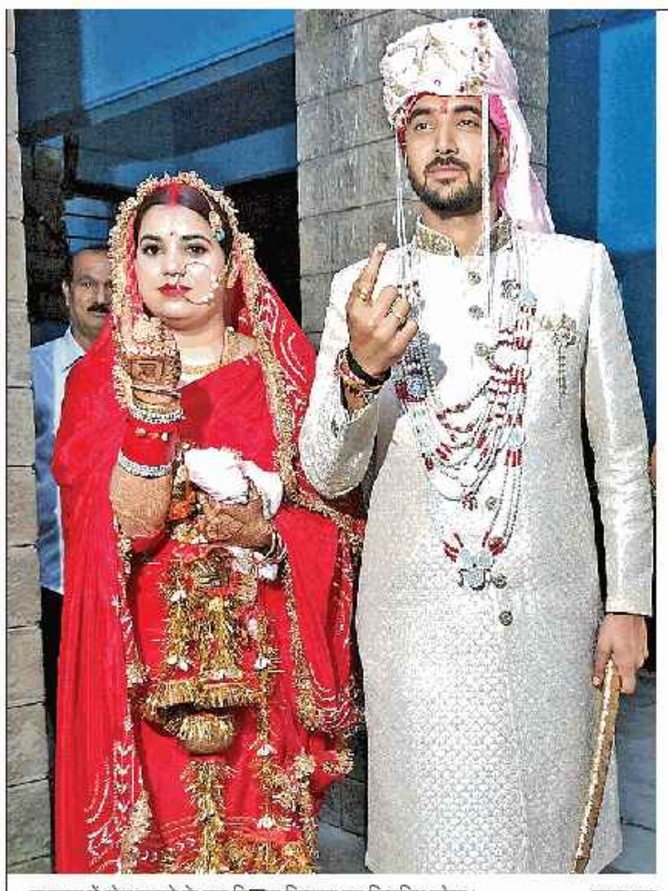

उधमपुर में वोट डालने के बाद निशान दिखाता नव विवाहित जोड़ा। एएनआइ

दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति किशनजी आम्गे (62.8 सेंटीमीटर) ने नागपुर में मतदान किया। भीड़ से बचने के लिए उनके परिजन उन्हें गोद में लिए हुए थे। आम्गे ने बताया कि उन्होंने दूसरी बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। इस मौके पर वह बहुत खुश थीं। एएनआइ

प्रथम चरण में कालिया वोर में वोट डालने के बाद प्रसन्नमुद्रा में बुजुर्ग महिला। प्रेट्र

मणिपुर में वोट डालने के बाद अंगुली पर निशान दिखातीं फर्स्ट टाइम वोटर। एएनआइ

अरुणाचल में प्रथम चरण के लिए मतदान को जाती महिला।

नागपुर में शुक्रवार प्रथम चरण में पत्नी कंचन के साथ वोट डालने के बाद स्याही का निशान दिखाते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नागपुर लोकसभा सीट से ही गडकरी भाजपा प्रत्याशी हैं। एएनआइ

मतदान का फर्ज : मेघालय में वोट डालने जातीं दिव्यांग बुजुर्ग महिला। एएनआइ

तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वोट डालने के बाद अंगुली पर निशान दिखाते सद्गुरु जग्गी वासुदेव। प्रेट्र

छिंदवाड़ा में वोट डालने के बाद अंगुली पर लगी स्याही दिखाते कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ।

वोट की 'तीर्थयात्रा' पर सत्तू-प्याज लेकर 40 किलोमीटर चले पैदल

जंगल और पहाड़ों की शृंखला लांघकर पहुंचे गया के डुमरिया प्रखंड के कोकणा गांव के मतदाता

एक दिन के लिए मजदूरी छोड़ दी, लकड़ी चुनने जंगल भी नहीं गए, तपती दोपहरी और तेज लू से लड़ते वोट देकर लौटे घर

मनीष कुमार ● जागरण

औरंगाबाद : प्रथम चरण के मतदान में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में उन जगहों पर लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का उत्साह शुक्रवार को चरम पर था, जहां कभी नक्सली दहशत के कारण निकलते नहीं थे। मतदान के प्रति समर्पण भाव ऐसा कि 20 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच गए। अब लौटने में फिर 20 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर तय करना है।

गया जिले के डुमरिया प्रखंड की छकरबंधा पंचायत के कोकणा गांव के मतदाताओं का केंद्र बहुत दूर था। यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा है, सो मतदान केंद्र भी दूर है। मोबाइल में देखने पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस बता रहा था। इस भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप में मतदाता पांव पैदल चले आ रहे हैं। अनबरन सलैया प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्र है। दोपहर चढ़ चुकी है। करीब एक बज रहा है।

नंदकेश्वर सिंह भोक्ता, सीताराम सिंह भोक्ता, महेंद्र सिंह भोक्ता, नरेश सिंह भोक्ता, शैलेंद्र सिंह भोक्ता, संजय सिंह भोक्ता सहित और भी मतदाताओं ने बताया कि वे लोग अपने गांव से जंगल-पहाड़ लांघकर वोट देने पहुंचे हैं। पोटली में सत्तू और प्याज बांधकर लाए हैं। मतदान के बाद यहीं खाएंगे और गांव लौट जाएंगे। राह दुर्गम है, इसलिए शाम होने से पहले घर लौटना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार के महत्व को भला इन जैसे लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है? यूं कहें कि वे मतदान की तीर्थयात्रा पर निकले थे। उनके मन में कुछ आकांक्षाएं भी हैं कि गांव तक पहुंचने का रास्ता आसान हो और मतदान केंद्र उनकी पंचायत में भी बने। इस आकांक्षा के साथ वोट के लिए आए हैं। चूंकि वोट पर्व है, इसलिए जंगल में न तो लकड़ी चुनने गए और न ही मजदूरी की। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मतदान था। ये लोग दस बजे घर से निकले थे। इसी गांव के भागवत सिंह भोक्ता, जोगेश्वर सिंह भोक्ता, सुकुल सिंह भोक्ता ने बताया कि वे लोग सुबह छह बजे ही निकल गए। धूप कम थी, दो घंटे में पहुंच गए। अब वोट देकर लौट रहे हैं।

गया जिला के डुमरिया प्रखंड के छकरबंधा पंचायत के कोकणा गांव से 20 किमी पैदल चल कर मतदान केंद्र अनरबन सलैया पहुंचे मतदाता। जागरण

मतदान केंद्र पर पंचायत के वार्ड सदस्य गोपालडेरा गांव निवासी राजेंद्र भुइयां ने बताया कि उनलोगों का गांव, प्रखंड व थाना पहाड़ व जंगल के पार औरंगाबाद जिले की तरफ है। कोकणा गांव से मतदान केंद्र लगभग 20 किमी दूर है। इस मतदान केंद्र से गोपालडेरा, आजाद बिगहा, बरवाडीह, महतरी गांव के वोटर जुड़े हैं।

यहां तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने के कारण कम ही मतदाता वोट देने पहुंचे हैं। बूथ पर तैनात मतदान पदाधिकारी बंशीधर त्रिवेदी ने बताया कि 26.46 प्रतिशत मतदान हुआ। कुल 903 वोटर हैं। 239 वोटरों ने मत का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल मुस्तैद दिखे।

पहली बार अंडमान की शोम्पेन जनजाति के लोगों ने किया मतदान

पोर्ट ब्लेयर, प्रेट्र : अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शोम्पेन जनजाति के सात सदस्यों ने इस केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

शोम्पेन जनजाति के सदस्यों ने न सिर्फ 'शोम्पेन हट' नामक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया बल्कि चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए एक कटआउट पर सेल्फी भी ली जिस पर लिखा था, 'मतदान जरूर करें।' जनजाति के लोगों की 'माथियास' (एक निकोबारी आदिवासी युवा) के रूप में जाने जाने वाले दुभाषिये ने उनकी भाषा में मदद की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने बताया कि इन लोगों को पहले एक प्रशिक्षक के जरिये ईवीएम और वीवीपेट का प्रशिक्षण दिया गया था। यह देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने जंगल से बाहर आकर पहली बार मतदान किया। उन्होंने बताया कि 98 शोम्पेन मतदाताओं में से पहली बार इन सात ने मतदान किया है। 2011 की जनगणना में इस जनजाति के 229 लोग थे।

शोम्पेन आदिवासी समुदाय का एक मतदाता अंडमान और निकोबार द्वीप में अपना वोट डालने के बाद फोटो खिंचवाते हुए। एएनआइ

मतदान का किया बहिष्कार

बुनियादी सुविधाओं, आधारभूत ढांचे और विकास कार्यों के अभाव के कारण बिहार के औरंगाबाद जिले में नेहुटा गांव और तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले के उरालिपट्टी के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया।

'मूक गांव' ने की वोटिंग

जम्मू-कश्मीर में बड़ी मूक-बधिर आबादी के कारण 'मूक गांव' के रूप में जाने जाने वाले धडकाही के निवासियों ने भी मतदान किया। उन्हें उम्मीद है कि अब गांव को सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी।

बस्तर के 56 गांवों में भी पहली बार मतदान

छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के 56 गांवों में लोगों ने पहली बार मतदान किया। उनके लिए मतदान केंद्र उनके गांवों में ही बनाए गए थे।

अरुणाचल में मतदान केंद्र पर सिर्फ एक मतदाता

अरुणाचल प्रदेश के चीन से सटे अन्जा जिले में मालोगाम मतदान केंद्र पर सिर्फ एक महिला मतदाता सोकेला तयांग थी, लिहाजा उसके मतदान करने से वहां शत प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। 44 वर्षीय तयांग के लिए चुनाव कर्मचारियों ने दुर्गम इलाके में 40 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र स्थापित किया था।

भारत-बांग्लादेश सीमा पार कर 2,500 मतदाताओं ने किया मतदान

त्रिपुरा में वोट डालने के लिए लगभग 2,500 मतदाताओं ने शुक्रवार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी को पार किया। दरअसल, ऐतिहासिक कारणों से त्रिपुरा में बड़ी संख्या में मतदाताओं को कांटेदार बाड़ के उस पार रहना पड़ा है। जो लोग अब मतदान की उम्र के हो चुके हैं, वे त्रिपुरा की मतदाता सूची में शामिल हैं। लिहाजा उनकी सुविधा के लिए सुबह ही सीमा पर गेट खोल दिए गए थे।

राजनीतिक हलचल

कर्नाटक में भाजपा के दो पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल

बेंगलुरु : कर्नाटक में भाजपा के दो पूर्व विधायक मलकाया गुत्तेदार और शारदा मोहन शेट्टी शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। कलबुर्गी जिले के अफजलपुर से छह बार विधायक रह चुके गुत्तेदार पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। गुत्तेदार अपने भाई नितिन वैंकैया गुत्तेदार को भाजपा में शामिल किए जाने से नाराज चल रहे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के एमवाई पाटिल विजयी हुए और नितिन दूसरे एवं गुत्तेदार तीसरे स्थान पर रहे। (प्रेट्र)

आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू, पुरंदेश्वरी ने नामांकनपत्र भरा

अमरावती : तेदेपा प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश भाजपा प्रमुख डी पुरंदेश्वरी, कड़पा से वाईएसआरसीपी के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी एवं अन्य ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपने नामांकनपत्र दाखिल किए। चंद्रबाबू एवं उनकी पत्नी की संपति में पांच वर्ष के दौरान 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नामांकनपत्र के साथ चुनाव आयोग को सौंपे गए शपथपत्र के अनुसार, चंद्रबाबू और उनकी पत्नी एन भुवनेश्वरी के पास 810.42 करोड़ रुपये की संपति है। (प्रेट्र)

नासिक लोकसभा सीट से दावेदारी वापस लेंगे भुजबल

मुंबई : राकांपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने नासिक लोकसभा सीट से टिकट नहीं मांगने का फैसला लिया है ताकि सहयोगी शिवसेना के साथ गतिरोध खत्म हो सके। उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र से निवर्तमान सांसद हेमंत गोडसे, सीएम एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना से आते हैं। राकांपा प्रमुख अजित पवार ने यहां से दावा किया था। (प्रेट्र)

पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पुणे में घर से मतदान किया

पुणे : पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने वोट फ्राम होम सुविधा का लाभ लेते हुए घर से ही मतदान किया। उनके सहायक ने शुक्रवार को बताया कि 90 वर्ष की उम्र और अस्वस्थ होने के कारण पूर्व राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया। (प्रेट्र)

बस्तर के मतदान में मोदी, महतारी और विकास की रही हिस्सेदारी

सतीश चंद्र श्रीवास्तव ● नईदुनिया

रायपुर : छत्तीसगढ़ में पारा आज (शुक्रवार) गर्म रहा। राजनीतिक भी और मौसमी भी। तापमान अगर 44 डिग्री से ऊपर गया तो बस्तर में 67 प्रतिशत से अधिक मतदान ने भी अबतक की सारी सीमा लांघ दी। लोकतंत्र के उत्सव में उत्साह और उमंग दिखा। सबसे पहले वोट डालने की होड़ दिखी। मुश्किल रास्तों को पार कर मतदान केंद्र पहुंचने की चाह दिखी। युवा मन की संभावनाएं दिखीं। महिला वंदन का सम्मान दिखा। विचारधारा का संग्राम दिखा। नक्सलियों के कारण बदनाम बस्तर ने शुक्रवार को विकास के लिए वोट डाला। बदलाव के लिए मतदान किया। मन में विकसित बस्तर का उफान लिए युवा वोटर दुर्गम क्षेत्रों से अपने बुजुर्ग स्वजन के साथ पहुंचे। 10-12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रैक्टर का वाहन के रूप में भी प्रयोग किया। चुनौती है कि सरपट सड़क, पीने के लिए साफ पानी, बिजली और मकान जैसी मौलिक सुविधाएं मिलें। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था का विकास हो। यही कारण है कि मतदान बहिष्कार की नक्सली धमिकयों के बीच मतदान प्रतिशत में उछाल आया है। यहां उल्लेखनीय है कि दृढ़ संकल्प के साथ सुकमा जिला स्थित पूवर्ती गांव में 33 मतदाताओं ने लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति डाली। चर्चा इसलिए आवश्यक है कि तीन दशक के बाद यहां मतदान हुआ है। यह 27 से अधिक हमलों में शामिल कुख्यात नक्सली हिडमा का गांव है। वर्ष 2021 में हिडमा के क्षेत्र में ही सीआरपीएफ के 22 जवान बलिदान हुए थे। बटालियन कमांडर देवा सहित उसके गांव के 100 से अधिक लोग नक्सली हैं।

युवा वोटर दुर्गम क्षेत्रों से बुजुर्ग स्वजन के साथ पहुंचे

सुकमा। रवड़ीपारा व पोंगाभेज्जी गांव के ग्रामीण गांव से 12 किमी दूर मतदान केंद्र मांझीपारा में ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे। यह नक्सल प्रभावित है उसके बावजूद जोखिम उठाकर मतदान करने ग्रामीण पहुंचे।

बस्तर वह संसदीय क्षेत्र है जहां 1980 के चुनाव में अगर 37 प्रतिशत मतदान हुआ था तो 1991 में नक्सलियों के प्रभाव के कारण मतदान प्रतिशत गिरकर 27 रह गया था। यहां वोटरों की अंगुलियां काट दी गई थीं। यही कारण है कि 2024 के चुनाव में भी बनांचल के सुदूर गांवों के मतदाताओं की अंगुलियों पर स्याही नहीं लगाई गईं। लेकिन बस्तर बदल रहा है।

बुजुर्ग महिला के घर पर मतदान में हस्तक्षेप न रोकने पर अधिकारी निलंबित

कन्नूर, प्रेट्र : केरल में चुनाव के दौरान 92 वर्षीय एक महिला के घर पर मतदान प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप रोकने में कथित रूप से विफल रहने के कारण चार मतदान अधिकारियों को सेवा से निलंबित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने 92 वर्षीय देवी के लोकतांत्रिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 18 अप्रैल को उनके आवास पर स्थापित मतदान केंद्र पर उनके मतदान में कथित रूप से हस्तक्षेप के लिए गणेशन नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ जांच की भी सिफारिश की है। कन्नूर जिले का कल्लियासेरी विधानसभा क्षेत्र कासरगोड लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। एक आधिकारी की ओर से कहा गया है कि जब देवी के घर पर मतदान हुआ, तो यह देखा गया कि बाहरी हस्तक्षेप के कारण गुप्त मतदान की प्रकृति पर असर पड़ा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गणेशन सीपीआइ (एम) का कार्यकर्ता था, जबकि भाजपा ने आरोप लगाया कि यह चुनाव में विघ्न डालने का प्रयास था। वाम दल ने आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ईवीएम में मामूली गड़बड़ियों की खबरें

प्रथम पृष्ठ से आगे

कई स्थानों पर पारंपरिक पोशाकों में नवविवाहित जोड़ों और व्हीलचेयर व स्ट्रेचर पर दिव्यांग जनों, बुजुर्गों व बीमार लोगों को भी मतदान करते देखा गया। तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और असम में कुछ बूथों पर ईवीएम में मामूली गड़बड़ियों की खबरें मिलीं हैं जिन्हें जल्द ही ठीक कर लिया गया। इस कारण कुछ जगह मतदान देर से शुरू हुआ। पूर्वी नगालैंड के छह जिलों में लोग मतदान करने नहीं निकले क्योंकि आदिवासी संगठनों के शीर्ष निकाय ने अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया था। बंगाल के कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में संघर्ष हो गया। दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध क्रमशः 80 और 39 शिकायतें दर्ज कराई हैं। मणिपुर में थांगजू विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों और अज्ञात व्यक्तियों के बीच विवाद हो गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक आइईडी ब्लास्ट में एक सुरक्षा अधिकारी घायल हो गया। अरुणाचल प्रदेश में बामेंग सीट में एक मतदान केंद्र के पास दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। राज्य में तीन मतदान केंद्रों पर ईवीएम क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं भी सामने आई हैं।

इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों पर मतदान : तमिलनाडु, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और लक्षद्वीप।

आज पता चलेगा वास्तविक मतदान प्रतिशत : चुनाव आयोग के अनुसार, 62.37 प्रतिशत मतदान के आंकड़े अनुमानित हैं। जब सभी मतदान केंद्रों से रिपोर्ट मिल जाएंगी तो मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। दरअसल, कई संसदीय क्षेत्रों में मतदान शाम छह बजे तक निर्धारित था और मतदाता आखिरी समय तक मतदान के लिए पहुंच रहे थे। ऐसे मतदाताओं को मतदान की अनुमति प्रदान की गई है। इसलिए फार्म-17ए की जांच के बाद ही मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े शनिवार को ही पता चल सकेंगे।

देश में राजग के लिए रिकार्ड संख्या में मतदान कर रहे लोग : पीएम

जेएनएन, नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान के बाद भाजपा उत्साहित है। मतदान समाप्त होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें बेहतरीन फीडबैक मिल रहा है। इससे स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकार्ड संख्या में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को वोट दे रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, पहला चरण, शानदार! आज मतदान करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद।

आज के मतदान से स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकार्ड संख्या में राजग के लिए मतदान कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान की पाली लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान के पहले चरण में भाजपा के पक्ष में बंपर वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव में देश की जनता ने भाजपा को 303 सीटें दी थीं, इस बार 400 पार का लक्ष्य है। गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा, भाजपा की सीटों का ग्राफ भी उतना ऊपर जाएगा।

- **पहले चरण में भाजपा के पक्ष में हुई बंपर वोटिंग : अमित शाह**
- **लोगों ने मजबूत सरकार के लिए किया है मतदान : सुधांशु त्रिवेदी**

भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लोगों ने मजबूत सरकार के लिए मतदान किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल अभी भी अमेठी से नामांकन दाखिल करने का साहस नहीं जुटा पाए हैं। तमिलनाडु के स्पष्ट संदर्भ में, जहां सभी 39 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ, उन्होंने कहा कि उन राज्यों में भाजपा की सीटों में बड़ा इजाफा होगा जहां यह अपेक्षाकृत मजबूत नहीं है। कहा कि भाजपा पिछली बार से अधिक सीटें और बड़े अंतर से जीतेगी।

मप्र में बोले मोदी- आतंक का सप्लायर आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के दमोह में शुक्रवार को चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हमारा एक पड़ोसी आतंक का सप्लायर था, आज वह आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। इस समय दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं, ऐसी स्थिति में भारत की रक्षा करने वाली मजबूत सरकार चाहिए, यह काम पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार ही कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि आइएनडीआइ ने पूरी ताकत लगा दी कि देश में राफेल जैसे लड़ाकू विमान देश में न आएं ताकि वायुसेना सशक्त न हो। इनकी सरकार होती तो यह भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान को भी उड़ने नहीं देते। भाजपा सरकार सेना को आत्मनिर्भर बना रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की खेप आज ही (शुक्रवार को) फिलीपींस भेजी गई। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या का जो अंसारी परिवार दो पीढ़ियों से राम मंदिर और हिंदुओं के खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ रहा था, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने वोटबैंक की खातिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया।

अब भी आपातकाल वाली मानसिकता में है कांग्रेस : पीएम मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के वर्धा में भी थे। समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार पीएम ने कहा कि कांग्रेस आज भी संविधान की अवमानना और आपातकाल वाली मानसिकता से बाहर नहीं आ सकी है। इनके पास विकास की नीति नहीं है।

सपा मुखिया की बेटी ने मां के लिए मांगे वोट

लोकतंत्र के चुनावी समर में परिवारवाद का मुद्दा खूब मुखर है। परंतु सपा इससे बेफिक्र दिखती है। शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव परिवार की तीसरी पीढ़ी के नए सदस्य के रूप में सपा मुखिया अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव ने अपनी मां डिंपल यादव के लिए जनसंपर्क किया। पहली बार माइक थामा और वोट देने की अपील की। चुनाव में बीते एक माह में अदिति अपनी मां के प्रचार अभियानों में कई बार नजर आई थीं, परंतु मंच और संबोधन से दूरी बनाए रखी। अब उनके संबोधन को राजनीति में पहला कदम माना जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट को सपा का गढ़ कहा जाता है। मुलायम सिंह के निधन के बाद वर्ष 2022 में हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने विरासत संभाली थी। दोबारा मैदान में उतरीं डिंपल कई माह से प्रचार में अकेले ही जुटी हैं। अदिति भी कई बार सभाओं में नजर आई थीं। वह जनता के बीच में बैठी रहीं। मंच पर नहीं चढ़ी। जागरण

****

5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी गुजरात के गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 के आम चुनाव में। 2024 में गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में सात मई को मतदान होगा।

दस साल गड्ढे भरने में लगे, अब तैयार होगा 'विकसित भारत' : शाह

चुनावी रण ▶ गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से भरा नामांकन

कहा, अटल-आडवाणी की सीट का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात

राज्य ब्यूरो, जागरण ● गांधीनगर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद शाह ने कहा, पिछली यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए गड्ढे भरने में 10 साल लग गए। अगले पांच साल का उपयोग 'विकसित भारत' के लिए मजबूत आधार तैयार करने में किया जाएगा।

उन्होंने कहा, जिस गांधीनगर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी कर चुके हैं और पीएम मोदी जिस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं उस क्षेत्र से चुनाव लड़ना मेरे लिए यह गौरव का विषय है। मैं इस क्षेत्र से 30 साल से जुड़ा हूं। यहीं से बूथ कार्यकर्ता से लेकर विधायक, सांसद बना। केंद्रीय मंत्री पद तक पहुंचा। पार्टी अध्यक्ष भी रहा। आपके प्यार की बदौलत मैं साधारण बूथ कार्यकर्ता से अब संसद सदस्य बन गया हूं। जब भी मैंने गांधीनगर के लोगों से वोट मांगा, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। केंद्रीय मंत्री शाह ने 'विजय मुहूर्त' में दोपहर 12.39 बजे गांधीनगर के कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी एमके दवे को भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र सौंपा। शाह के साथ उनकी पत्नी सोनल शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की भी मौजूदगी रही। नामांकन के बाद पत्रकार वार्ता में शाह ने कहा कि यह चुनाव नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है ताकि वह 2047 तक भारत को विकसित देश बना सकें। मोदीजी ने 2047 तक भारत को विकसित देश और सभी क्षेत्रों में नंबर एक देश बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए अगले पांच साल महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि पिछले 10 साल पिछली यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए गड्ढों को भरने में चले गए। आगामी पांच साल विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने के लिए देश की जनता का समर्थन चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार की मदद से गांधीनगर क्षेत्र में पांच साल में 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य कराया गया है।

गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। एएनआइ

नामांकन से एक दिन पहले किया था रोडशो

नामांकन से एक दिन पहले शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्रों में विजय शंखनाद रोडशो किया। भीषण गर्मी के बावजूद शाह के रोडशो में जनसैलाब उमड़ा।

सीआर पाटिल ने नवसारी से भरा नामांकन

नवसारी से भाजपा प्रत्याशी एवं गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल, जामनगर से भाजपा प्रत्याशी पूनम माडम और राजकोट से भाजपा उम्मीदवार परशोत्तम रुपाला के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी परेश धनाणी ने नामांकन दाखिल किया।

आरक्षण नीति में कभी छेड़छाड़ नहीं करेगी मोदी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि नरेन्द्र मोदी सरकार आरक्षण नीति में कभी छेड़छाड़ नहीं करेगी। किसी और भी ऐसा नहीं करने देगी। शाह ने यह भी कहा कि सरकार देश से नक्सलवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी।

उन्होंने एक समाचार चैनल से साक्षात्कार में कहा, हम आरक्षण की नीति को कभी नहीं छूएंगे और न ही किसी और को ऐसा करने देंगे। गृहमंत्री ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि सरकार संविधान में संशोधन करने की योजना बना रही है। कहा, अगर हमें संविधान बदलना था तो हम इसे पहले ही कर सकते थे। हमने दस साल तक संसद में बहुमत का दुरुपयोग नहीं किया है। बहुमत का दुरुपयोग करने की आदत कांग्रेस की है, हमारी नहीं। शाह ने कहा कि भाजपा की प्रतिबद्धताओं में कोई बदलाव नहीं आया है। महिला आरक्षण अधिनियम और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) मोदी सरकार लेकर आई। उन्होंने कहा, मैंने पूरे देश की यात्रा की है, हर कोई तीसरी बार पीएम मोदी के लिए वोट करने का इंतजार कर रहा है। कहा कि भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने बार-बार नक्सलियों से हिंसा छोड़ने को कहा है। 90 दिनों में, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है।

▶ कहा- देश से नक्सलवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी सरकार

▶ संविधान में संशोधन की अटकलों पर कहा- नहीं करते बहुमत का दुरुपयोग

मजबूत सरकार चुनने के लिए करें मतदान : शाह

गृहमंत्री शाह ने लोगों से मजबूत सरकार चुनने की अपील की। शाह ने कहा कि यह मतदान भारत के उज्ज्वल भविष्य को आकार देने के लिए है। शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं मेरे बहनों-भाइयों से अपील करता हूं कि भारत को पूरे विश्व में मान-सम्मान दिलाने वाली, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाली, गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने वाली, देश को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और तुष्टिकरण से मुक्त करने का दृढ़ संकल्प दिखाने वाली मजबूत सरकार चुनने के लिए ऐतिहासिक संख्या में मतदान करें। उन्होंने लोगों से ऐसी सरकार चुनने की अपील की जिसने न केवल विकास को गति दी है बल्कि सीमाओं पर अचूक सुरक्षा सुनिश्चित की है, हर गरीब को स्वास्थ्य, आवास, बिजली और गैस सुविधाएं दी हैं। उन्होंने कहा, मैं इस चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं क्योंकि आपके हर वोट में सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की ताकत है। पहली बार के मतदाताओं से भी अपील की।

ओबीसी, एससी और एसटी के सबसे बड़े पक्षधर हैं पीएम मोदी : शाह

जागरण संवाददाता, जयपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राजस्थान की पाली कहा कि लोग मोदी को लाने के लिए बेताब हैं। उन्होंने लोगों से सोच-समझकर मतदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के मामले में लटका कर रखा। यहां तक कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण इसलिए नहीं किया, क्योंकि वह वोट बैंक से डरते हैं। मोदी ने एक झटके में मंदिर का निर्माण करवा दिया। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 हटाने का काम मोदी सरकार ने किया है। शाह पाली संसदीय क्षेत्र के भोपालगढ़ में भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने भाजपा को 303 सीटें दी थीं, इस बार मोदी जी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है।' अमित शाह ने देर शाम उदयपुर शहर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी), जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के सबसे बड़े पक्षधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। मोदी ने ओबीसी और पिछड़ों को सम्मान देने साथ ही ओबीसी को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया और ओबीसी आयोग बनाया है। कांग्रेस ने काका कालेकर और मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मोदी ने ही इन पर अमल किया। उन्होंने कहा, वर्तमान में 37 प्रतिशत सांसद और 27 मंत्री ओबीसी के हैं। वहीं खुद पीएम ओबीसी वर्ग के हैं।

चुनावी हलचल

18 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए छिंदवाड़ा के महापौर ने नकुल नाथ के लिए मांगा समर्थन

नईदुनिया, छिंदवाड़ा

▶ मतदान के दिन वीडियो जारी कर कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की

▶ विक्रम अहके बोले- भाजपा में घुटन महसूस करने लगा था

छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक उठापटक का दौर मतदान के दिन भी जारी रहा। 18 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए महापौर विक्रम अहके ने अप्रत्याशित रूप से मतदान के दिन शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी करके कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने वीडियो में कहा कि कुछ दिन पहले मैंने किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन किया, उसी दिन से मुझे घुटन महसूस हो रही थी। लग रहा था कि उस इंसान (पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ) के साथ गलत कर रहे हो, जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया और यहां के लोगों के दुख-दर्द में मदद की। अहके की कांग्रेस में वापसी के सवाल पर छिंदवाड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने कहा कि हमारे पास ज्वाइनिंग की सूचना नहीं है, वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इस वीडियो की जानकारी नहीं है। अभी इस वीडियो को लेकर विक्रम अहके का पक्ष सामने नहीं आया है। बता दें कि एक अप्रैल को महापौर विक्रम अहके कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। अहके कमल नाथ के खास माने जाते थे। उन्हें महापौर का टिकट दिलवाने में कमल नाथ की अहम भूमिका थी। ऐसे में उनका लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ना कमल नाथ के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था।

नकुल नाथ। फाइल विक्रम अहाके।

कांग्रेस और वाम दल जैसी पार्टियां वैचारिक रूप से दिवालिया : नड्डा

वायनाड, प्रेट्र: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए में कांग्रेस और वाम दल जैसी पार्टियां 'वैचारिक रूप से दिवालिया' हो गई हैं। उन्होंने भाजपा का विरोध करने के लिए दिल्ली में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए दिल्ली के बाहर एक-दूसरे के साथ अपनी भयंकर चुनावी लड़ाई को जारी रखा है।

अपने उम्मीदवार के सुरेंद्रन के लिए सुल्तान बाथेरी में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग द्वारा आयोजित रोड शो के इतर भाजपा प्रमुख ने वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एलडीएफ के भाकपा के एनी राजा के बीच चुनावी लड़ाई का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भाकपा महासचिव डी. राजा की पत्नी (एनी राजा) एलडीएफ उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि, दिल्ली में डी. राजा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच बैठे हैं, वे वैचारिक रूप से दिवालिया हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वायनाड में पार्टी प्रत्याशी सुरेंदन के समर्थन में एक रोड शो किया। एएनआइ

आपका वोट भ्रष्टाचार, परिवारवाद के खिलाफ

कोझिकोड, एएनआइ: भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने पहले चरण के मतदान के बीच दावा किया कि हरेक वोट भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वह मानते हैं कि इससे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सुदृढ़ होगा।

राजनाथ ने साधा निशाना, कहा-कांग्रेस पुराने ढर्रे की पार्टी, प्रासंगिकता खोने लगी है

हैदराबाद, प्रेट्र: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को पुराने ढर्रे पर चलने वाली पार्टी करार देते हुए कहा है कि यह पार्टी भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। लेकिन भाजपा सत्ता का सिंहासन हासिल करने के लिए नहीं बल्कि देश को मजबूत बनाने के लिए राजनीति कर रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने अपनी किताब में लिखा था कि यूपीए के शासनकाल में उन पर देश की अर्थव्यवस्था की अच्छी तस्वीर दिखाने का दबाव था।

केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का नामांकन के दौरान एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से पुराने ढर्रे पर चलने वाली पार्टी बन चुकी है और भारतीय राजनीति से अपनी प्रासंगिकता खो रही है। यह पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर गई है। भाजपा जाति-भेद और धर्म के लिए नहीं बल्कि न्याय और मानवता के लिए राजनीति करती है। कांग्रेस और बीआरएस पर तंज करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल के जनता से किए वादे नहीं निभाए गए। बीआरएस तेलंगाना के गठन का श्रेय खुद लेती है जबकि इस राज्य को बनाने के लिए यहां के कई लोगों ने बलिदान दिया। कांग्रेस नेताओं पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेन्द्र मोदी सरकार के दौरान भाजपा के किसी भी नेता पर ऐसे आरोप नहीं लगे। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के सात साल बाद भारत विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाली पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। राम मंदिर, अनुच्छेद 370, तीन तलाक का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा ने हर वादा निभाया है।

▶ केंद्रीय मंत्री बोले-भाजपा देश को मजबूत बनाने को राजनीति कर रही

▶ कहा-2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोल्लम, मवेलिककारा व पथानामथिट्टा में सभाएं की।

मोदी को तीसरी बार पीएम का पद संभालते हुए देखना चाहते हैं बीरबल के वंशज

नईदुनिया, सीधी

अकबर के सलाहकार रहे बीरबल के 14वें वंशज गंगाराम दुबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकासवादी सोच से प्रभावित हैं। देश की तरक्की, आत्मनिर्भर भारत, गांव में खुशहाली देख वे मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। गंगाराम दुबे पेशे से कृषक हैं। वह कहते हैं कि आज देश के साथ गांव का हर व्यक्ति खुश है। आए दिन आतंकी घटना को अंजाम देने वाला पाकिस्तान भारत को आंख उठाकर नहीं देख सकता है। देश में किसी चीज की कमी नहीं है। गांव में शादी-विवाह कराने के साथ कथा करने वाले गंगाराम ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर हिंदू के सपने को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग के लिए विकास किया गया है। गांव में सड़क, बिजली और पानी की समस्या खत्म हो गई है। स्कूल और शौचालय के साथ स्वच्छता हर एक व्यक्ति का मिशन बन गया है। गंगाराम दुबे ने बताया कि जब बुंदेलखंड के अधिकतर हिस्से में चंदेल राजवंश का शासन था तो हमारे पूर्वज बनारस से मध्य प्रदेश आए और सीधी जिले के घोघरा गांव में बस गए। घोघरा मंदिर के पुजारी शत्रुघ्न तिवारी कहते हैं कि बीरबल घोघरा देवी की पूजा करते थे। इनके पूर्वज भी मंदिर में देवी माता की पूजा करते रहे हैं।

370 हटा भाजपा ने आतंकवाद के ताबूत में ठोकी अंतिम कील : योगी

जागरण टीम, मेरठ

▶ यूपी के मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर और बागपत में जनसभा को किया संबोधित

▶ कहा, कांग्रेस, सपा व बसपा ने आराध्य के आधार पर किया था सवाल

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकी है। दंगाई और माफिया अब राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल गए हैं। वह शुक्रवार को बुलंदशहर और बागपत लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि अब आतंकी देश में विस्फोट नहीं करते। यदि देश में आतंकी घुसे तो उन्हें ठिकाने लगा दिया जाएगा।

पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को भी ठीक कर दिया जाएगा। देश में आतंकवाद का समाधान और नक्सलवाद की समस्या को समाप्त कर दिया गया है। बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में सीएम ने कहा कि देश में सिर्फ एक ही भाव है। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे।

योगी आदित्यनाथ।

कांग्रेस, सपा-बसपा हमारे आराध्य के आधार पर ही सवाल खड़ा कर कहते थे, राम है ही नहीं। अब कहते हैं राम हम सबके हैं। कांग्रेस, सपा-बसपा ने असुरक्षा व बेरोजगारी का माहौल दिया। इनको एक-एक वोट के लिए तरसा देना। देश में सारी समस्या कांग्रेस ने दी थी।

बागपत लोकसभा लोकसभा सीट से रालोद प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के समर्थन में आयोजित सभा में योगी ने कहा कि भाजपा सरकार में यूपी का जंगलराज खत्म हुआ है। आज यदि किसी बेटी या व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ होता है तो अपराधी का राम-नाम सत्य होता है।

राहुल गांधी बोले, हर वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा

नई दिल्ली, एएनआइ: लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में वोट डाले गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रत्येक वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि याद रखें, आपका एक-एक वोट आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने वाला है। उन्होंने कहा कि नफरत को हराएं और हर कोने में मुहब्बत की दुकान खोलें। राहुल ने लोगों को कांग्रेस की प्रमुख गारंटी का एक ग्राफिक भी साझा किया, जिसमें अप्रेंटिसशिप का अधिकार, एमएसपी की कानूनी गारंटी और राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना शामिल है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सावधानी से मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अपना वोट सावधानी से डालें। एक ऐसा भविष्य जहां न्याय और समान अवसरों का नया युग इंतजार कर रहा है।

राहुल गांधी। फाइल

भाजपा, कांग्रेस एवं उनके सहयोगी दलों ने देश को लूटा : मायावती

नईदुनिया, रीवा

▶ मप्र के रीवा में बसपा सुप्रीमो ने किया चुनावी सभा को संबोधित

▶ कहा - भाजपा ने पदोन्नति में आरक्षण को बनाया प्रभावहीन

कांग्रेस, भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों को ठगने का काम किया है, उन्होंने देश को लूटा, इसीलिए बहुजन समाजवादी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है। यह बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को रीवा के एसएएफ ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से केंद्र सहित अधिकतर प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उनके कार्यकाल में गरीब, मजदूर, आदिवासी और मुस्लिम परेशान होते रहे। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है और यह पार्टी भी केवल धन्नासेठों के लिए काम कर रही है। भाजपा के लोग हिंदुत्व, जातिवाद एवं धर्म की संकीर्ण मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। भाजपा शासन काल में पूंजीवाद का उदय हुआ है। भाजपा ने एसटी-एससी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावहीन बनाया है। मायावती ने कहा कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों एवं ईवीएम में गड़बड़ी न की जाए तो बदलाव की लहर दिख रही है।

मायावती। नईदुनिया

इसलिए घोषणा पत्र नहीं जारी करती बसपा: मायावती ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र के साथ प्रचार में लगे हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद उसे भुला दिया जाता है। इसीलिए बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव के पहले कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। हमारी पार्टी कहने में कम, करने में ज्यादा विश्वास रखती है। सत्ता में आने के बाद काम करके दिखाएंगे।

किडनी देने पर संदेह है तो केंद्र अपनी एजेंसी से जांच करा ले : रोहिणी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना

▶ लालू प्रसाद की बेटी व जदयू प्रत्याशी ने भाजपा को दी चुनौती

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी और लोकसभा चुनाव में सारण से पार्टी उम्मीदवार डा. रोहिणी आचार्य ने कहा है कि अगर भाजपा को संदेह है कि मैंने अपने पिता को किडनी नहीं दी है तो वह किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच करा ले। अगर मैं गलत साबित हुई तो राजनीति छोड़ दूंगी। जांच में प्रमाणित हो जाए कि मैंने ही किडनी दी है तो भाजपा के नेता मेरा पैर छूकर माफी मांगें। उन्होंने भाजपा पर गलतबयानी का आरोप लगाया।

शुक्रवार को छपरा में रोहिणी ने कहा कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है। उनसे पूछा गया कि कुछ लोग संदेह कर रहे हैं कि आपने अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी नहीं दी है। रोहिणी ने कहा कि यह आरोप भाजपा के लोग लगा रहे हैं। मैं भाजपा नेताओं और खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनौती देती हूं कि वे इस आरोप की जांच करा लें। प्रधानमंत्री मंच से जांच के परिणाम की घोषणा करें। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सभा में लोजपा (रा) के अध्यक्ष चिराग पासवान की मां के प्रति अपशब्द कहे जाने की घटना की रोहिणी ने आलोचना की। हम भी चिराग को अपना भाई और उनकी मां को अपनी मां मानते हैं। भीड़ में किसी ने चिराग की मां के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, यह गलत है। लेकिन चिराग को भी दूसरे की मां-बहनों का सम्मान करना चाहिए। भाजपा के नेता मेरे लिए अपशब्द बोल रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। महिला पहलवानों के साथ खराब व्यवहार हुआ, लेकिन चिराग ने कभी कोई आलोचना नहीं की।

रोहिणी आचार्य

कांग्रेसियों की तरह जेल जाने से नहीं डरते वामपंथी : विजयन

कोझिकोड, प्रेट्र: केरल में आइएनडीआइए में शामिल कांग्रेस और माकपा के बीच शुक्रवार को जमकर वाकयुद्ध हुआ। गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर निशाना साधते हुए कहा था कि आखिर केंद्रीय एजेंसियों ने उनसे पूछताछ या उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कोझिकोड में चुनावी सभा में शुक्रवार को इसके जवाब में कहा कि वह कांग्रेस नेताओं की तरह जेल जाने से नहीं डरते हैं।

विजयन ने पूर्व मुख्यमंत्री और माकपा नेता वीएस अच्युतानंदन द्वारा राहुल को 'अमुल बेबी' कहे जाने की बात को दोहरा दिया जिससे कांग्रेस भड़क उठी। इसको लेकर कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने मुख्यमंत्री की आलोचना की और उनसे अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की।

राज्य में विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल ने गुरुवार को आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि आखिर वामपंथी नेता उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं जबकि वह तो भाजपा के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनसे ईडी ने 55 घंटे पूछताछ की, उनकी लोकसभा सदस्यता और उनका आधिकारिक आवास छीन लिया गया और वर्तमान में दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

▶ केरल के मुख्यमंत्री ने राहुल को कहा 'अमूल बेबी', कांग्रेस नाराज

पिनराई विजयन। फाइल

विजयन ने इसके जवाब में कहा कि राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान अधिकांश वामपंथी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। वह भी जेल में थे। हमने बहुत ज्यादा पूछताछ और जेल का सामना किया है। हम जेल से नहीं डरते हैं।

भाजपा-आरएसएस से जुड़े लोगों ने की थी अंग्रेजों की नौकरी : खरगे

जागरण टीम, कटिहार

▶ किशनगंज व कटिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावी सभा को किया संबोधित

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भाजपा आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। वह देश में लोकतंत्र व संविधान को खत्म करना चाहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह के बारे में कहा कि यह रंगा-बिल्ला की जोड़ी है। पिछले 10 वर्षों में मोदी ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने उक्त बातें शुक्रवार को बिहार के कटिहार में कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर व किशनगंज में कांग्रेस प्रत्याशी डा. जावेद आजाद के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहीं। कहा कि डबल इंजन की सरकार कभी टूटती है तो कभी जुड़ती है। इससे दुर्घटना की आशंका रहती है। नीतीश कुमार डेंजर मैन हैं।

भविष्य में नीतीश को साथ लेने से उन्होंने तेजस्वी को भी सतर्क किया है। कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। भाजपा व आरएसएस से जुड़े लोगों ने अंग्रेजों की नौकरी ही की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया। महागठबंधन की सरकार बनने पर 40 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। प्रत्येक महिला के खाते में हर साल एक लाख रुपये दिए जाएंगे। यह चुनाव लोकतंत्र एवं संविधान को बचाने के लिए है। कोई धर्म के नाम पर तो कोई जाति के नाम आपको भड़काने के लिए तैयार बैठा है। कांग्रेस ने राष्ट्र का नवनिर्माण किया, रोजगार दिए।

बिहार के कटिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। जागरण

****

200 से ज्यादा लोगों ने दावा किया कि उनके नाम मतदाता सूची से गायब थे तमिलनाडु की तिरुवल्लूर संसदीय क्षेत्र में । ये लोग उथुक्कोट्टई के रहने वाले थे। इसके अलावा भी दक्षिण के कई संसदीय क्षेत्र से इस तरह की खबरें आई हैं।

ममता बोलीं, चुनाव के बाद मैं करूंगी आइएनडीआइए का नेतृत्व

टीएमसी सुप्रीमो ने कांग्रेस व माकपा का भाजपा के साथ गुप्त समझौते का लगाया आरोप

मुस्लिम प्रवासी कामगारों से कहा- वोट नहीं देने पर भाजपा छीन लेगी नागरिकता

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि आइएनडीआइए को मैंने बनाया। उन्होंने यहां तक कहा कि आने वाले दिनों (चुनाव बाद) में मैं विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए का नेतृत्व करूंगी। टीएमसी सुप्रीमो ने ममता ने मुर्शिदाबाद के हरिहरपाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में कांग्रेस और माकपा का भाजपा के साथ गुप्त समझौता है। दोनों भाजपा के एजेंट हैं। इसलिए मैं यहां अकेले चुनाव लड़ रही हूं। कांग्रेस व माकपा पर जोरदार हमला बोलते हुए दावा किया कि दोनों दल बंगाल में आइएनडीआइए के घटक नहीं हैं। आइएनडीआइए यहां नहीं, दिल्ली में है।

ममता ने कहा, कुछ लोग कहते हैं, हम आइएनडीआइए हैं, हमें वोट दें। आइएनडीआइए यहां का नहीं, दिल्ली का है। इसे मैंने बनाया है। उन्होंने मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र के लोगों से अपील की कि अगर आप भाजपा को हराना चाहते हो तो किसी कीमत पर कांग्रेस-माकपा को एक वोट न दें। यदि वोट दिया तो यह भाजपा की मदद करना होगा।

मुस्लिम समुदाय को दिया एनआरसी व सीएए का ह्वाला : मुख्यमंत्री ने इस दौरान रमजान व ईद के लिए घर आए मुस्लिम समुदाय के प्रवासी कामगारों से अपील की कि वे मतदान के बाद ही प्रदेश से बाहर जाएं। उन्होंने दावा किया कि यदि आप वोट नहीं डालेंगे, तो आपका नाम आधार सूची से हटा दिया जाएगा और एनआरसी व सीएए की सूची में डाल दिया जाएगा। भाजपा आपकी नागरिकता छीन लेगी। ममता ने यह भी दोहराया कि मैं यहां सीएए-एनआरसी व यूसीसी लागू नहीं होने दूंगी। यदि वे यूसीसी लाते हैं तो आप अपनी पहचान खो देंगे।

चुनाव आयोग पर भी निशाना : ममता ने चुनाव में राज्य पुलिस के बजाय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) पर जोर देने पर निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधा। सवाल किया कि आप राज्य पुलिस को पूरी तरह से त्यागकर चुनाव कैसे करा सकते हैं? क्या यह मताधिकार की स्वंतत्रता को बाधित करने की एक चाल है। ममता ने भाजपा को आगे बताने वाले ओपिनियन पोल को भी फर्जी करार दिया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को देश में 200 सीटें भी नहीं मिलेंगी।

मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को चुनावी रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान और अबु ताहर खान का परिचय कराती बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। प्रेट्र

हिंसा पर बोलीं, हथियार लेकर शोभायात्रा क्यों निकाल रहे थे?

मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर भी ममता ने फिर भाजपा पर निशाना साधते हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाया। ममता ने पूछा कि आप हथियार (तलवारें) लेकर शोभायात्रा क्यों निकाल रहे थे? ममता ने भाजपा का नाम लिए बगैर यह भी कहा कि आपको मस्जिद पर हमला करने का अधिकार किसने दिया? यह भी कहा- मुस्लिम को देखकर ही एनआइए को उनके घर में घुसाने का अधिकार किसने दिया?

इस समय मोदी मैजिक चल रहा है

उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य डा. दिनेश शर्मा इन दिनों उस महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी का दायित्व निभा रहे हैं, जहां शिवसेना और राकांपा जैसे दलों में विभाजन एवं मराठा आंदोलन के बाद के दौर में राजनीतिक समीकरण समझना राज्य के राजनीतिक दिग्गजों के लिए भी आसान नहीं रहा है। शर्मा प्रत्येक चरण के चुनाव के लिए योजनाबद्ध तरीके से पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। जहां कोई समस्या आ रही है, प्रदेश भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर उसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत है दैनिक जागरण के मुंबई ब्यूरो प्रमुख ओमप्रकाश तिवारी से डा. दिनेश शर्मा की संक्षिप्त बातचीत :

साक्षात्कार

● महाराष्ट्र में भाजपा साढ़े तीन दशक से गठबंधन की राजनीति करती आ रही है। भाजपा अपने पहले गठबंधन में ज्यादा सहज थी, या अब के गठबंधन में ?

-भाजपा तो पहले भी सहज थी, अब भी सहज है। सहज होने का कारण यह है कि भाजपा ने अपनी नीति, नीयत और नेतृत्व को नहीं बदला है। इसके कारण, भाजपा की जो विचारधारा थी, वह स्थिर है। नेतृत्व जो मोदी जी का था, वह स्थिर है। अब जिन लोगों ने अपने अहंकार के कारण अपनी नीति बदली, अपना चोला बदला। राम और सनातन को छोड़ दिया। जिन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करनेवाली, उन्हें दो-दो बार हरानेवाली कांग्रेस को अपना लिया है। तो निश्चित रूप से जनता ऐसे लोगों को उत्तर देगी।

● महाराष्ट्र में भाजपा का भी अपने गठबंधन के कुछ साथियों के साथ पेंच फंसा हुआ था?

- नहीं, नहीं। भाजपा की महायुति के सारे नट-बोल्ट बिल्कुल कसे हुए हैं। मजबूत हैं। इसलिए हमारे यहां पेंच नहीं फंसता। क्योंकि स्क्रू जब ढीला ही नहीं है, तो पेंच फंसने का सवाल ही कहां उठता है। ये सब तो महाविकास आघाड़ी में होता है। हमारे यहां सीट की शेयरिंग नहीं होती। विचारधारा की शेयरिंग होती है। हमारे यहां विवाद नहीं होता, संवाद होता है।

● अंग्रेजी की एक कहावत है – टू इस कंपेनियन, थ्री इस क्राउड (दो लोग साथी होते हैं, तीन लोग भीड़ बन जाते हैं)। महायुति में यह स्थिति तो नहीं है ?

- यह स्थिति तो वहां होती है, जहां अनिर्णय की स्थिती होती है। यहां अनिर्णय की कोई स्थिति है ही नहीं। हम एक आदर्श गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा में खिचड़ी नहीं पक रही है। खिचड़ी वाले लोग महाविकास आघाड़ी में हैं (यह कहते हुए दिनेश शर्मा मुंबई उत्तर-पश्चिम से मविआ के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर पर भी प्रहार करते दिखाई देते हैं, जिनपर कोविड महामारी के दौरान खिचड़ी घोटाले का आरोप लग रहा है)। वहां तो गली-गली में शोर है। आगे आप समझ ही सकते हैं.....

● इस गठबंधन में भाजपा बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए कैसे सहयोग कर रही है अपने दोनों कनिष्ठ भागीदारों को ?

बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए सब कुछ वह संभाल रहा है। राकांपा लड़ रही है, तो भी आपको लगेगा कि यहां भाजपा लड़ रही है। शिवसेना (शिंदे) लड़ रही है, तो भी आपको लगेगा कि भाजपा लड़ रही है। जैसे बारामती में भाजपा पूरी ताकत राकांपा के साथ लगा रही है। रामटेक में प्रत्याशी शिवसेना (शिंदे) का है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां भी अपनी सभा की।

● आरोप लग रहे हैं कि भाजपा बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए अपने छोटे भाइयों पर दबाव बनाकर अधिक सीटें झटकने का प्रयास कर रही है।

-नहीं, नहीं। यहां पर न दबाव है। न प्रभाव है। न दुराव है। यहां तो बस समभाव है। ये समभाव है एक-दूसरे को मजबूत करने का। दिन में चार बार हमारे नेता भी मिलते हैं, और कार्यकर्ता भी मिलते हैं।

● मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के कारण मराठा समुदाय में महायुति को लेकर कुछ असंतोष है। उसे दूर करने का क्या प्रयास चल रहा है ?

-मराठा भारत की शान है। मराठा अस्मिता को कायम रखना भाजपा का दृढ़ निश्चय है। कांग्रेस इतने दिन सत्ता में रही। उद्धव ठाकरे भी रहे सत्ता में। वो तो मराठा समाज को कुछ नहीं दे पाए। उसे जो भी दिया है, भाजपा सरकार ने ही दिया है। आगे भी चाहे मराठा हो, या महाराष्ट्र के अन्य जाति-धर्म के लोगों के हित में, भाजपा उचित कदम उठाएगी। इसलिए मराठा हो, या कोई अन्य पक्ष हो, सब भाजपा के साथ हैं।

● उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ओमप्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी जैसे नेताओं को साथ लेकर भाजपा ने अनेक जाति-वर्गों को खुद से जोड़ा है, वैसा प्रयास महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिखाई देता ? धनगर छिटकते दिखाई दे रहे हैं।

- यहां भी किया गया है ऐसा प्रयास। छोटे-मोटे 24 दल हमारे साथ हैं। यहां धनगर, बंजारा, मराठा, कुनबी, उत्तरभारतीय सब हमारे साथ हैं।

● महाराष्ट्र के ज्यादातर बड़े नगरों में बहुत बड़ी संख्या उत्तरभारतीयों की रहती है। इनमें से ज्यादातर भाजपा के ही मतदाता है। लेकिन इस वर्ग को शिकायत रहती है, कि भाजपा इन्हें टिकट नहीं देती।

- ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मुझ जैसे उत्तर भारतीय को भाजपा ने महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी बनाया है। उत्तर प्रदेश से लड़नेवाले व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र भाजपा में संजय उपाध्याय, अमरजीत मिश्र को संगठन में जिम्मेदारियां दी गई हैं। विद्या ठाकुर लगातार भाजपा के ही टिकट पर विधायक चुनी जाती हैं। भाजपा ने ही राजहंस सिंह को विधान परिषद में भेजा है। उत्तर मुंबई से टिकट पाए पीयुष गोयल भी तो हिंदीभाषी ही हैं। इसलिए ये आरोप गलत हैं।

● अभी तक भाजपा के नेता महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 45 से अधिक जीतने की बात कर रहे थे। आप पहले नेता हैं, जिनके मुंह से पूरी 48 सीटें जीतने की बात निकल रही है। कैसे ?

- मैं ऐसी बात नहीं करता, यदि मैं विदर्भ घूमकर न आया होता। पहले मुझे लग रहा था कि एक-दो सीटों पर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पीएम दो रैलियों के बाद परिस्थिति बदल गई है। अनुमान से ढाई से तीन गुना लोग आए सभा में। मोदी मैजिक चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है।

जनप्रतिनिधियों के दलबदल पर रोक लगाना चाहती है तृणमूल

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के दलबदल करने पर रोक लगाना चाहती है। तृणमूल के चुनावी घोषणापत्र में कहा गया है कि केंद्र में बनने वाली अगली सरकार में पार्टी का प्रतिनिधित्व होने पर इस बाबत कदम उठाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों का दलबदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। दूसरी तरफ विरोधी दलों ने तृणमूल पर तंज कसते हुए कहा है कि दलबदल कराने में जो पार्टी सबसे आगे है, वही इस तरह की बातें कर रही है। भाजपा के राज्य सभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि यह सबसे बड़ा मजाक है।

'370' का मुद्दा उठाया पर वापस लाने का वादा नहीं

राज्य ब्यूरो, जागरण ● श्रीनगर

घोषणापत्र

अनुच्छेद-370 के निरस्तीकरण के विरोध को केंद्र में रखते हुए पीडीपी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। घोषणापत्र में महबूबा 370 हटाने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का वादा तो करती हैं पर कहीं भी उसे वापस लाने का वादा नहीं करतीं। इस घोषणापत्र को महबूबा मुफ्ती और पीडीपी के 370 पर नरम पड़ते रुख का सुबूत माना जा रहा है। यहां बता दें कि यह वही महबूबा हैं, जिन्होंने चेताया था कि अगर अनुच्छेद-370 को छेड़ा गया तो कश्मीर में कोई तिरंगा थामने वाला नहीं मिलेगा।

इस घोषणापत्र में कश्मीर मसले के समाधान के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत और सुलह का भी राग अलापा गया है। हालांकि इसमें कहीं पाकिस्तान के नाम का उल्लेख नहीं है। घोषणापत्र जारी करते हुए महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि अनुच्छेद-370 के निरस्तीकरण ने कश्मीर मसले को और जटिल बनाया है। यहां लोगों को अपनी आवाज नहीं उठाने दी जा रही, यहां लोगों को दबाकर दिखाया जा रहा है कि सबकुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि हम संसद में जाकर जम्मू-कश्मीर के लोगों को आवाज उठाएंगे। महबूबा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने अनुच्छेद-370 के निरस्तीकरण को कबूल नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 के बाद यहां हमारे सभी संसाधन, खनिज, जमीनें और नौकरियां दूसरे राज्यों के लोगों को दी जा रही हैं। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि यह चुनाव बिजली, पानी और सड़क जैसे विकास संबंधी मुद्दों के बारे में नहीं है। घोषणापत्र में गुज्जर-बक्करवाल समुदाय का जिक्र करते इन्हें जमीन से बेदखल किए जाने का दावा करते हुए मुद्दा बनाया गया है।

पीडीपी नेता ने कश्मीरियों के हक की आवाज को उठाने का किया वादा, हल खोजने की वकालत पर पाक का जिक्र नहीं

महबूबा मुफ्ती। फाइल

'नामांकन रद करने के खिलाफ सुनवाई शुरू की तो अराजकता फैल जाएगी'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यदि उसने नामांकन पत्र खारिज करने के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर दिया, तो अराजकता फैल जाएगी। इस टिप्पणी के साथ ही शीर्ष अदालत ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। यह व्यक्ति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उसका नामांकन पत्र रद कर दिया गया।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ ने कहा कि नामांकन पत्र खारिज कर दिए जाने का समाधान चुनाव याचिका दायर करने में है, न कि शिकायत के साथ सुप्रीम कोर्ट आने में। अगर हम नामांकन पत्रों की अस्वीकृति के खिलाफ संविधान के तहत अनुच्छेद 32 (यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार का हक देता है) के तहत याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर देंगे तो अराजकता फैल जाएगी। हालांकि, पीठ ने जवाहर कुमार झा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अलख आलोक श्रीवास्तव को उचित कानूनी उपाय खोजने की अनुमति दे दी। जवाहर कुमार झा बिहार की बांका सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन, रिटर्निंग आफिसर ने उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान सीजेआइ ने कहा, अगर हम नोटिस जारी करते हैं और मामले की सुनवाई करते हैं, तो भी यह चुनाव के बाद तक चलता रहेगा। आपको चुनाव कानून के अनुशासन का पालन करना होगा। हम नामांकन पत्र खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

- शीर्ष अदालत ने कहा, मुद्दे का समाधान चुनाव याचिका दायर करने में है
- रिटर्निंग आफिसर ने खारिज कर दिया था निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन

चुनाव जागरूकता यात्रा पर तीन दिन में फैसला लेने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- शीर्ष अदालत ने समक्ष अथारिटी को दिया आदेश
- चुनाव के दौरान धारा 144 लागू रहने को चुनौती पर कोर्ट करेगा विचार
- याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह अजीब स्थिति है

चुनाव के दौरान समान रूप से धारा 144 (सीआरपीसी) लागू किए जाने को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए विचार का मन बनाया है। इसके साथ ही शुक्रवार को कोर्ट ने यह भी अंतरिम आदेश दिया कि अगर कोई चुनाव के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से जागरूकता यात्रा या सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने के लिए आवेदन करता है तो सक्षम अथारिटी ऐसे आवेदनों पर तीन दिन में निर्णय लेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने चुनाव के दौरान समान रूप से धारा 144 लागू रहने का मुद्दा उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने पर किसी भी जगह पांच व्यक्तियों से ज्यादा के एकत्र होने पर रोक रहती है। समान्य तौर पर यह धारा किसी क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका पर लागू की जाती है। लेकिन चुनाव के दौरान भी यह समान रूप से लागू रहती है। समाजसेवी अरुणा राय और निखिल डे ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान समान रूप से धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू किए जाने को चुनौती दी है, जिसके चलते जनसभा, यात्रा निकालने, धरना व लोगों के एकत्र होने पर रोक रहती है। शुक्रवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यहां बहुत ही अजीब स्थिति है। हर चुनाव में धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू रहती है। इससे न तो कोई सार्वजनिक बैठक हो सकती है, न ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली जा सकती है। उन्होंने राजस्थान के बाड़मेर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 16 मार्च को निषेधाज्ञा लगाई गई और वह छह जून तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति शिक्षित करने के लिए यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। इस पर सुनवाई कर रही पीठ ने आश्चर्य जताया और कहा कि यह कैसे हो सकता है।

कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि याचिकाकर्ता चुनाव के संबंध में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए लोकतंत्र यात्रा निकालना चाहते थे और इसके लिए जनसभाएं करना चाहते थे, लेकिन संबंधित अथारिटी ने उनके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया।

सरक्षित है आपका वोट, मताधिकार का उपयोग करें : मुख्य चुनाव आयुक्त

नई दिल्ली, प्रेट्र: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम से जुड़ी आशंकाओं को खारिज करते हुए शुक्रवार को लोगों को आश्वासन दिया कि उनका वोट सुरक्षित है। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में मताधिकार का उपयोग करने की अपील की।

उन्होंने ईवीएम पर संदेह संबंधी सवालों के जवाब में कहा, यह अब कोई मुद्दा नहीं है। यह शत प्रतिशत सुरक्षित है। इसे कोर्ट में भी उठाया गया। हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कई सुरक्षा उपाय हैं। यह किसी भी बात पर संदेह करने का नहीं, मतदान का आनंद लेने का समय है। आपका वोट सुरक्षित है। आप जिसे वोट देंगे वह वैसा ही दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बेहतर मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का काफी हद तक उपयोग किया है।

आयोग ने उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जहां पारंपरिक रूप से कम मतदान होता रहा है। राजीव कुमार ने कहा, लोगों तक पहुंचने के लिए कई मशहूर हस्तियों को शामिल किया गया। कई संगठनों ने हमारे साथ काम किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग मतदान के लिए निकलेंगे। हमारी अपील है कि कृपया लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल हों। यह आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका गौरव है। राजीव कुमार, साथी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू के साथ चुनाव आयोग मुख्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष से चुनाव प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी कर रहे थे। जिन राज्यों में मतदान चल रहा था।

- मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम से जुड़ी आशंकाओं को किया खारिज
- कहा- यह संदेह करने का नहीं, मतदान का आनंद लेने का है समय

राजीव कुमार। फाइल

केंद्रीय मंत्री रुपाला का विरोध कर दुविधा में राजपूत समाज

शत्रुघ्न शर्मा ● जागरण

अहमदाबाद: राजकोट सीट से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला के बयान के विरोध को लेकर राजपूत समाज दुविधा में फंसा नजर आ रहा है। कई प्रतिष्ठित राजपूत व पूर्व राजपरिवार रूपाला के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं आंदोलन की अगुआई कर रही राजपूत संकलन समिति की प्रमाणिकता पर राजपूत समाज के कई लोग सवाल उठाने लगे हैं।

करणी सेना की महिला मोर्चा अध्यक्ष पद्मिनी बा ने राजपूत समाज की संस्थाओं की संकलन समिति के नेताओं की मंशा पर ही सवाल उठाया है। राजपूत समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित जामनगर के पूर्व राजपरिवार के जाम साहब शत्रुशल्य सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा ने हिंदू समाज व संस्कृति की रक्षा के लिए कई कार्य किए हैं इसलिए रुपाला की माफी के बाद समाज को बड़ा मन रखते हुए इस विवाद को अब समाप्त कर देना चाहिए। राजकोट के पूर्व राजपरिवार के सदस्य मांधाता सिंह ने भी राजपूत समाज से अपील की थी कि इस आंदोलन को लंबा नहीं खींचना चाहिए। पूर्व विधायक जयराज सिंह जाडेजा, राज्य सभा सदस्य केसरीदेव सिंह झाला जैसे नेता पहले ही भाजपा के पक्ष में हैं। 14 अप्रैल को राजकोट के रतनपुर गांव में राजपूत अस्मिता महासम्मेलन में विभिन्न संस्थाओं के नेताओं ने भाजपा से परषोत्तम रुपाला का टिकट रद करने की मांग रखी लेकिन 16 अप्रैल को रूपाला ने करीब एक दर्जन राजपूत नेताओं की मौजूदगी में सभा व रोडशो का आयोजन कर पर्चा दाखिल किया। शुक्रवार को राजपूत नेताओं के अल्टीमेटम का आखिरी दिन था। संकलन समिति से जुड़े 92 राजपूत संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी।

- इस समिति की प्रमाणिकता पर सवाल उठा रहे राजपूत समाज के कई लोग

परशोत्तम रुपाला। फाइल

भाजपा सीधे किसानों को मनाएगी, संगठनों के नेताओं को नहीं

कैलाश नाथ ● जागरण

चंडीगढ़: कृषि मुद्दों को लेकर विरोध का सामना कर रही भाजपा अब सिर्फ किसानों को मनाएगी। वह किसान संगठनों के नेताओं से बात नहीं करेगी। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) से गठबंधन टूटने के बाद राज्य में पहली बार अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही भाजपा अभी तक नौ उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है।

भाजपा को हर सीट पर किसान संगठनों के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा प्रत्याशी जहां पर भी जा रहे हैं, किसान नेता काली झंडियां लेकर वहां पहुंच जा रहे हैं। इससे प्रत्याशियों के चेहरे पर शिकन तो है, लेकिन पार्टी ने अब इन्हीं परिस्थितियों में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इसका मुख्य कारण विरोध के कारण आम लोगों से भाजपा को मिल रही सहानुभूति भी है। पार्टी को लगता है कि किसान संगठनों के नेता राजनीति कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि खनौरी और शंभू बार्डर पर 13 फरवरी से बैठे किसान संगठनों को इस बार वह समर्थन नहीं मिला, जोकि 2020 में तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ मिला था। उस समय पूरा राज्य किसानों के साथ खड़ा था, जबकि इस बार मात्र दो संगठन ही अपनी मांगों को लेकर सामने आए। इन संगठनों को संयुक्त किसान मोर्चा का भी समर्थन नहीं मिला। वहीं, किसान संगठनों के विरोध के बीच भाजपा ने 'पीड़ित कार्ड' खेलने का निर्णय लिया है। चूंकि, किसान संगठन केवल भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। इस कारण शहर और गांव का भी एक वर्ग भाजपा से सहानुभूति रखने लगा है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि राज्य का किसान कभी भी भाजपा का मतदाता नहीं था। गठबंधन में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व शिअद ही करता था। वहीं, सूत्र बताते हैं कि किसान संगठनों के विरोध के कारण गांव-गांव में एक वर्ग छिटक कर भाजपा के प्रति सहानुभूति भी रखता है। वहीं, शहरी मतदाताओं में भी भाजपा के पक्ष में एकजुटता होने के पार्टी को संकेत मिल रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का कहना है कि किसानों की जो मांगें हैं, उनमें एक नहीं, बल्कि कई क्षेत्र जुड़े हुए हैं। ये ऐसी मांगें नहीं हैं, जिन्हें एक व्यक्ति पूरा कर दे। इसको लेकर किसानों के साथ बातचीत की जाएगी।

पार्टियों की रणनीति

- भाजपा प्रत्याशी जहां भी जा रहे, काली झंडियां लेकर पहुंच रहे किसान संगठन
- विरोध से मिल रही लोगों की सहानुभूति, इन्हीं परिस्थितियों में चुनाव लड़ेगी पार्टी

चुनावी रंग को चटख कर रहे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित मीम

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनावी माहौल में इंटरनेट पर मीम की भरमार है। यह चुनावी रंग को चटख कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां प्रचार के साथ ही एक दूसरे पर हमला बोलने, जबकि चुनाव आयोग वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए इनका प्रयोग कर रहा है। मीम के साथ ही स्लोगन, पोस्टर, फिल्मी डायलाग का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इंस्टाग्राम हो या एक्स सभी जगह इनकी बाढ़ सी आ गई है।

चुनाव आयोग ने लोगों को मतदान केंद्र तक लाने और खासकर पहली बार मतदान करने वालों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के कई पोस्ट किए हैं। इनमें फिल्मों के डायलाग के साथ ही कई अन्य आकर्षित करने वाले स्लोगन शामिल हैं। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हम मतदान को लेकर उत्साहित हैं, क्या आप भी तैयार हैं। आयोग की ओर से फिल्म ये जवानी है दीवानी के एक दृश्य पर आधारित मीम का इस्तेमाल किया गया, जिसकी टैगलाइन थी मतदान से पहले पहली बार मतदाताओं का उत्साह। साथ ही लोगों से जुड़ने के लिए स्थानीय भाषा में स्लोगन का भी प्रयोग किया गया। जैसे अमार वोट, अमार दायित्वो। राजस्थान में मतदाताओं को दिखाने वाली तस्वीरों के साथ एक्स पर ''पधारो म्हारे पोलिंग बूथ'' जैसी पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया। वहीं, राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले और प्रचार के लिए इसका प्रयोग किया है। भाजपा के सोशल मीडिया फीड पर मुख्य रूप से तस्वीरें और नारे हावी रहे हैं। जैसे मोदी की गारंटी और विकास भी, विरासत भी। वहीं, कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें भाजपा पर व्यंग्यात्मक टैगलाइन, बेरोजगारी बहुत है, बाकी सब ठीक है, के साथ कटाक्ष किया गया।

- आयोग ने युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए किए कई पोस्ट
- स्थानीय भाषा में स्लोगन के साथ ही फिल्मी डायलाग का भी प्रयोग

****

1.65 करोड़ लोग जुड़े हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से वित्त वर्ष 2023-24 में। पिछले साल से तुलना करें तो यह तकरीबन 19 प्रतिशत अधिक है।

ममता सरकार को भ्रष्टाचार के एक और मामले में लगा झटका

हाई कोर्ट ने जीटीए शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआइ जांच का आदेश बरकरार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने दिया था निर्देश
- 500 से अधिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता के आरोप

ममता सरकार को भ्रष्टाचार के एक और मामले में झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के अधीन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआइ जांच के एकल पीठ के निर्देश को बहाल रखा। जीटीए बंगाल के दार्जिलिंग व कलिम्पोंग जिलों के लिए अर्धस्वायत्त परिषद है। इसके अधीन स्कूलों में 500 से अधिक शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इससे पहले राशन घोटाले में भी ममता सरकार को हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। बता दें, इस मामले कुछ दिन पहले राज्य स्कूल शिक्षा विभाग की शिकायत के आधार पर विधाननगर उत्तर थाने में सात के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय, जीटीए के पूर्व चेयरमैन विनय तमांग, तृणमूल छात्र परिषद के नेता त्रिनांकुर भट्टाचार्य समेत अन्य टीएमसी नेताओं के नाम शामिल हैं।

न्यायमूर्ति हरीश टंडन व मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, फिलहाल मामले की जांच सीबीआइ ही करेगी। हालांकि,पुलिस मूल जांच जारी रख सकती है। न्यायमूर्ति बिस्वजीत बोस की एकल पीठ ने मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। केंद्रीय एजेंसी को इस संबंध में 25 अप्रैल को अदालत में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। राज्य ने उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च पीठ का रुख किया था।

राज्य की ओर से महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा, राज्य ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एफआइआर दर्ज की है। जांच के लिए कोर्ट से वक्त मांगा गया, पर जस्टिस बोस ने समय नहीं दिया। याचिकाकर्ता के वकील विकासरंजन भट्टाचार्य ने कहा, राज्य ने भ्रष्टाचार के आरोपों को कोई महत्व नहीं दिया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई।

एनआइए जांच की मांग वाली अर्जी दायर करने की अनुमति

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभायात्रा पर हुए हमले की एनआइए जांच की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद(विहिप) को जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। आगामी मंगलवार को मामले पर सुनवाई होगी। बता दें, मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में बुधवार को रामनवमी की शोभायात्रा पर उपद्रवियों द्वारा बम फेंकने से 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस दौरान कई घरों व दुकानों में आगजनी व लूटपाट भी की गई थी। इस घटना को लेकर विहिप ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित कराया।

रामनवमी हिंसा का मामला

वहीं, दूसरी ओर हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने जिले के शक्तिपुर व बेलडांगा के थाना प्रभारी को हटाने का निर्देश दिया है। बंगाल विस में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर रामनवमी हिंसा की एनआइए से जांच कराने की मांग की है। ज्ञात हो,पिछले वर्ष उत्तर दिनाजपुर के दालखोला, हावड़ा के शिवपुर,हुगली के रिसड़ा व श्रीरामपुर में रामनवमी की शोभायात्राओं पर हमला हुआ था, जिनमें अनेक लोग जख्मी हुए थे। एनआइए इन घटनाओं की जांच कर रही है।

वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी होंगे अगले नौसेना प्रमुख

नई दिल्ली, एएनआइ: सरकार ने वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वह 30 अप्रैल को पदभार संभालेंगे। वर्तमान में वाइस एडमिरल त्रिपाठी नौसेना के उपप्रमुख हैं। इससे पहले वह पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। करीब 40 वर्ष के अपने लंबे करियर में वह कई महत्वपूर्ण अभियानों से जुड़े रहे हैं। सैनिक स्कूल, रीवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला के पूर्व छात्र दिनेश त्रिपाठी एक जुलाई, 1985 को नौसेना में शामिल हुए थे। संचार एवं इलेक्ट्रानिक युद्ध विशेषज्ञ त्रिपाठी ने सिग्नल कम्युनिकेशन आफिसर एंड इलेक्ट्रानिक वारफेयर आफिसर के रूप में नौसेना के अग्रिम युद्धपोतों पर काम किया है। बाद में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर आइएनएस मुंबई के कार्यकारी अधिकारी एवं प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में सेवाएं दीं। उन्होंने आइएनएस विनाश, किर्च और त्रिशूल की कमान भी संभाली है। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी पत्नी शशि त्रिपाठी एक कलाकार और होम मेकर हैं। उनका पुत्र वकील है।

दिनेश त्रिपाठी

नलिन प्रभात एनएसजी के प्रमुख नियुक्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारी नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नलिन वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नलिन प्रभात को 31 अगस्त, 2028 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए एनएसजी महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एनएसजी की स्थापना 1984 में की गई थी। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी) में विशेष निदेशक के रूप में सपना तिवारी की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। ओडिशा कैडर के 1992 बैच की आइपीएस अधिकारी तिवारी वर्तमान में आइबी में अतिरिक्त निदेशक हैं।

नलिन प्रभात।

शिकायतकर्ताओं को भी पक्षकार बनाएं रामदेव : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु रामदेव से अपनी याचिका में उन शिकायतकर्ताओं को भी पक्षकार बनाने को कहा, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए हैं।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने कहा कि रामदेव को राहत हासिल करने के लिए शिकायतकर्ताओं को भी पक्षकार बनाने की जरूरत है। रामदेव ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञात हो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पटना और रायपुर केंद्र ने 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी कि रामदेव की टिप्पणियों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा : पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को झटका देते हुए कोर्ट ने एक अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा कि योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क लेने पर संस्थान को सेवा कर का भुगतान करना होगा। जस्टिस अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ के पांच अक्टूबर, 2023 के फैसले में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया।

लव जिहाद पर कर्नाटक में सियासत गरमाई

- कांग्रेस पार्षद पिता बोले-ये लव जिहाद, सिद्दरमैया सरकार बोली-आपसी विवाद
- दुखी पिता की अपील-तेजी से फैल रहा लव जिहाद, बेटियों को बचाकर रखें

कर्नाटक के हुबली में लिंगायत समुदाय के कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा हिरेमठ की हत्या के विरोध में शुक्रवार को युवाओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रेट्र

हुबली, आइएएनएस : कर्नाटक के हुबली में लिंगायत समुदाय के एक कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा हिरेमठ की उसके कालेज परिसर में दिनदहाड़े नौ बार चाकू मारकर हत्या से पूरे शहर में लोगों का गुस्सा उफान पर है। भाजपा के विरोध-प्रदर्शनों का दौर चल पड़ा है। 24 वर्षीय नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ ने इस नृशंस हत्या के लिए राज्य में तेजी से बढ़ते लव-जिहाद को जिम्मेदार ठहराया। दुखी पिता ने सभी माताओं से अपील की है कि वह अपनी कालेज जाने वाली बेटियों का खास ख्याल रखें। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुखिया सिद्दरमैया ने पूरे प्रकरण को आपसी विवाद का नाम देते हुए इसमें लव-जिहाद होने से साफ इन्कार कर दिया।

कालेज के पूर्व मित्र और सहपाठी फैयाज खोंडुनायक ने गुरुवार को नेहा के शादी करने से इन्कार करने पर सरेआम उसकी जान ले ली और पुलिस ने उस मुस्लिम युवक को एक घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कर्नाटक में सिद्दरमैया शासित कांग्रेस सरकार की ओर से हरेक स्तर पर इस हत्या को आपसी विवाद के कारण ही माना जा रहा है। वह इसे लव-जिहाद मानने को कतई तैयार नहीं। बीबीबी कालेज से कंप्यूटर एप्लीकेशन के परास्नातक के प्रथम वर्ष की छात्रा नेहा हिरेमठ लिंगायत समुदाय से है। उसका अंतिम संस्कार शुक्रवार को उसके माता-पिता ने किया। इस प्रकरण पर कांग्रेस के रुख से क्षुब्ध कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ ने मीडिया से कहा कि लव-जिहाद की ही तर्ज पर यह हत्या की गई है। हम देख रहे हैं कि इसतरह की घटनाएं क्रूरता के चरम के साथ बढ़ती जा रही हैं। हमारी मांग है कि अब कोई भी लड़की इस पीड़ा से नहीं गुजरनी चाहिए। हमारा मानना है कि लव-जिहाद तेजी से फैल रहा है। उन्होंने सभी माताओं से अपील की कि वह अपनी बेटियों को कालेज भेजें, तो वह भी उन्हें छोड़ने साथ जाएं और देखें कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा।

हत्या के विरोध में भाजपा ने प्रदेश में बंद के आयोजन का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री और धारवाड़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रह्लाद जोशी ने इस घटना के पीछे लव-जिहाद होने का संदेह जताया। भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने हृदयविदारक घटना पर कहा कि हुबली में पहले कभी दिनदहाड़े ऐसी घटना नहीं हुई। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाइ विजयेंद्र ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण के लिए जांच को सुस्त करने का आरोप लगाया है। महिला सुरक्षा की गारंटी देने वाली कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। जबकि इस मामले को आपसी विवाद बताकर मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने कहा कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि भाजपा राज्य में कानून-व्यवस्था नहीं होना बताकर राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है। 26 अप्रैल और सात मई को मतदान से पहले भाजपा चाहती है कि उसे इस प्रकरण का पूरा लाभ मिले। प्रदेश के गृह मंत्री जी.परमेश्वर ने सांप्रदायिक एंगल को झुठलाते हुए इसे लव-जिहाद मानने से इन्कार कर दिया।

केंद्र सरकार ने दिया नेस्ले के शिशु उत्पाद सेरेलेक की जांच का आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने खाद्य संरक्षा नियामक एफएसएसएआइ को नेस्ले के भारत में बेचे जाने वाले शिशु उत्पाद सेरेलेक के अवयवों (कंपोजिशन) की जांच का आदेश दिया है। स्विटजरलैंड के गैरसरकारी संगठन पब्लिक आइ और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क की पड़ताल के मुताबिक, नेस्ले के भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों समेत कम विकसित दक्षिण एशियाई देशों में बेचे जाने वाले शिशु उत्पादों में यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक चीनी होती है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में सचिव और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की प्रमुख निधि खरे ने बताया, 'हमने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को पत्र लिखकर नेस्ले के शिशु उत्पाद संबंधी रिपोर्ट पर संज्ञान लेने को कहा है।' पत्र में खरे ने लिखा है कि विभिन्न खबरों के जरिये उपभोक्त मामलों के विभाग को भारत में नेस्ले कंपनी के तौर-तरीकों के बारे में पता चला है, खासकर नेस्ले के उत्पाद सेरेलेक के बारे में। खबरों के मुताबिक स्विटजरलैंड के संगठन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें नेस्ले के भारत में उत्पादन के तौर-तरीकों को रेखांकित किया गया है।

'रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में बेचे जाने वाले नेस्ले के शिशु उत्पाद सेरेलेक में प्रति सर्विंग 2.7 ग्राम चीनी है, जबकि जर्मनी, स्विटजरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों में इससे परहेज किया जाता है।' उन्होंने कहा,शिशु उत्पादों में चीनी की अधिक मात्रा हमारे देश में बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर संभावित प्रभावों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करती है। लिहाजा एफएसएसएआइ को भारत में बेचे जाने वाले सेरेलेक के कंपोजिशन के संबंध में नेस्ले के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। उसे मामले की जांच करऔर तथ्यों को सामने लाना चाहिए।

ज्ञात हो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी एफएसएसएआइ को नोटिस जारी किया है। गुरुवार को नेस्ले इंडिया ने कहा था कि उसने अनुपालन के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं किया है और गत पांच वर्षों में भारत में विभिन्न शिशु खाद्य उत्पादों में अतिरिक्त चीनी को 30 प्रतिशत तक घटाया है।

- केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने एफएसएसएआइ को दिया आदेश
- सेरेलेक में ज्यादा मात्रा में चीनी होने की बात आई है सामने

नेस्ले के शेयरों में गिरावट जारी

नेस्ले इंडिया के शेयरों में शुक्रवार को भी गिरावट जारी रही। बीएसई में उसका शेयर 1.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,437.10 रुपये पर बंद हुआ। गुरुवार को नेस्ले इंडिया के शेयर में तीन प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई थी। दो दिनों में कंपनी का बाजार पूंजीकरण भी 10,610.55 करोड़ रुपये घटकर 2,34,974.74 करोड़ रुपये रह गया है।

सीएए के नियमों को चुनौती देने वाली अर्जी पर केंद्र व असम से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगा है। इस नियम का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया संचालित व विनियमित करना है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाइ चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला की पीठ ने गुवाहाटी निवासी याचिकाकर्ता हिरेन गोहेन के वकील की दलीलों को सुना। शीर्ष अदालत ने नई याचिका को इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ संबद्ध (टैग) करने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि असम में बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के आने से भारी जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो गया है। कभी बहुसंख्यक रहे मूलनिवासी आज अल्पसंख्यक हो गए हैं।

याचिका में कहा गया कि यह कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। न तो यह हिंदू-मुस्लिम या स्वदेशी लोगों बनाम बंगाली अप्रवासी का मुद्दा है। यह विदेशी घुसपैठियों का मुद्दा है, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, जो असम के मूल लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका को संबंधित लंबित मामलों के साथ टैग करने का निर्देश

हाल ही में पीठ ने सीएए नियमों के संचालन पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए केंद्र से उन आवेदनों पर जवाब देने को कहा, जिनमें शीर्ष अदालत द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक उनके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध के लिए सरकार के पास जाएं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : ओटीटी प्लेटफार्मों पर आपत्तिजनक दृश्य दिखाने पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मामले में सरकार से संपर्क करने को कहा। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश वकील ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि ओवर-द-टाप (ओटीटी) प्लेटफार्म अनुचित दृश्य दिखाए जा रहे हैं। पीठ ने कहा, सेंसर बोर्ड के पास जाएं। आप आप दर्शक संबंधी नियंत्रण पर कुछ दिशानिर्देश चाहते हैं तो सरकार से अनुरोध करें। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे पर सरकार से संपर्क करने की छूट के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को सरकार से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी। कहा कि यदि ऐसा कोई अनुरोध दिया जाता है, तो उस पर संबंधित कानूनों के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।

बैंक से धोखाधड़ी करने पर पूर्व मैनेजर पर 15.06 करोड़ जुर्माना, सात साल की जेल

नई दिल्ली, प्रेट्र: सीबीआइ की विशेष अदालत ने बैंक से धोखाधड़ी करने वाली इंडियन ओवरसीज बैंक की पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पर 15.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसे विशेष अदालत द्वारा लगाया गए अब तक के सबसे बड़े जुर्मानों में से एक बताया जा रहा है। बैंक से 2.14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में उसे सात साल जेल की सजा सुनाई गई है।

गांधीनगर की विशेष अदालत ने बैंक की पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक प्रीति विजय सहजवानी को आपराधिक विश्वासघात, जाली दस्तावेज को वास्तविक दस्तावेज के रूप में उपयोग करने और बैंक को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता बैंक को मिलेगी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के 23 गवाहों से पूछताछ की गई और 158 दस्तावेज को गवाहों के माध्यम से साबित किया गया।

- सीबीआइ की विशेष अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक की पूर्व कर्मी को दोषी करार देते हुए सुनाई सजा
- अहमदाबाद में तैनाती के दौरान प्रीति सहजवानी ने बैंक को पहुंचाया 2.14 करोड़ रुपये का नुकसान

देश छोड़कर फरार हो गई थीं प्रीति सहजवानी

सीबीआइ ने बैंक की शिकायत पर 29 अक्टूबर, 2001 को मामले की जांच अपने हाथ में ली और 15 अक्टूबर, 2003 को आरोपपत्र दायर किया था। प्रीति सहजवानी देश छोड़कर भाग गई और 2012 तक फरार थी। सीबीआइ ने उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस जारी करवाया, जिससे सीबीआइ को कनाडा में उसका पता लगाने में मदद मिली। कनाडा के आव्रजन अधिकारियों ने उसे हिरासत में लेकर 11 जनवरी 2012 को भारत प्रत्यर्पित कर दिया।

अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा, प्रीति ने अहमदाबाद में इंडियन ओवरसीज बैंक की वस्त्रपुर शाखा की वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में जमाकर्ता या पावर आफ अटार्नी धारक के किसी भी मंजूरी पत्र के बिना दो खातों की फारेन करेंसी नान रेसिडेंस (एफसीएनआर) जमाराशि को दो फर्जी खातों में जमा करवा दिया था। साथ ही जमाकर्ताओं की बिना सरेंडर की गई जमा रसीदों का दुरुपयोग कर फर्जी खातों में लगभग 1.40 करोड़ रुपये की राशि का कर्ज स्वीकृत किया था।

फर्जीवाड़ा कर राशि, तारीख, मैच्योरिटी का मूल्य आदि में बदलाव किया था। सीबीआइ के प्रवक्ता ने कहा, प्रीति ने 27 जुलाई, 2001 तक ब्याज समेत करीब दो करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया।

शाहजहां शेख के खिलाफ शिकायत करने ईडी दफ्तर पहुंचे संदेशखाली के निवासी

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली के निवासी शुक्रवार को क्षेत्र के निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां के खिलाफ अपनी शिकायतों को लेकर कोलकाता के ईडी कार्यालय पहुंचे। शाहजहां पर लोगों की जमीन हड़पने व महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सीबीआइ जांच शुरू हुई है।

संदेशखाली के पीड़ित दस्तावेज के साथ ईडी कार्यालय में उपस्थित हुए। ईडी ने नोटिस देकर व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कराने के लिए लोगों से आग्रह किया था। ऐसे में जांच अधिकारियों ने सुबूतों के साथ इन सभी शिकायतों को स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट के आदेश पर शिकायतें प्राप्त करने के लिए सीबीआइ ने पहले ही एक पोर्टल खोल रखा है। वहां कोई भी शिकायत कर सकता है। गौरतलब है कि शाहजहां का नाम पहले से ही राशन भ्रष्टाचार में शामिल है। वह फिलहाल जेल में है।

सतपुड़ा की पहाड़ी पर इतिहास, आस्था और प्रकृति दर्शन का अद्भुत संगम

यात्रा

संदीप परोहा ● जागरण

मप्र के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण, यहीं पुरातत्व विभाग ने खोजीं पांडवकालीन गुफाएं

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित असीरगढ़ किले के भीतर भ्रमण करते पर्यटक ● जईदुनिया

बुरहानपुर : भवन निर्माण में वास्तुकला के साथ इंजीनियरिंग का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है और नित नई तकनीकें सामने आ रही हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हम इस कला में सदियों पहले से आधुनिकता और चकित करने वाले कौशल का प्रदर्शन करते रहे हैं। देश में स्थित कई किले, महल, भवन इसका जीवंत उदाहरण हैं और इन्हीं में से एक है असीरगढ़ का किला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित यह किला करीब पांच सदी पुराना है और यहां की यात्रा मात्र इतिहास से साक्षात्कार नहीं कराती है बल्कि प्रकृति दर्शन के साथ उस समय की समृद्ध इंजीनियरिंग और सोच से भी भेंट कराती है।

किले की अभेद्य संरचना: बुरहानपुर आज देश में केला उत्पादन और हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है। अतीत में यह क्षेत्र दक्षिण का द्वार कहा जाता था और इसकी वजह था असीरगढ़ का अजेय दुर्ग। इतिहासकारों के अनुसार अभेद्य संरचना के कारण इस किले को जीतना असंभव था। इतिहासकारों के अनुसार किले को आसा अहीर नामक राजा ने 15वीं सदी में बनवाया था जिस पर बाद में मुगलों ने कब्जा कर लिया। वर्ष 1760 से 1819 तक यह मराठों के कब्जे में रहा और वर्ष 1904 से अंग्रेजों ने इसे जेल के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया था। समुद्र तल से करीब 250 फीट की ऊंचाई पर सतपुड़ा की पहाड़ी के शिखर पर तीन किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस किले का भ्रमण एक अलग ही अनुभव है। किले के प्रारंभ में बड़ा प्रवेश द्वार और चारों ओर तोप के गोले से भी नहीं टूटने वाली पत्थरों की दीवार है। इसमें मुगलों व अंग्रेजों के जमाने का बारूदखाना, बंदीगृह, अस्तबल, टकसाल, फांसी घर, न्यायालय, विश्राम गृह, तालाब और सेना के ठहरने के स्थान हैं।

शिव मंदिर और पांडवकालीन धरोहर: इतिहास के जानकार मेजर डा. एमके गुप्ता व होशंग हवलदार के अनुसार, किले के पूर्व में स्थित शिव मंदिर अतिप्राचीन है। मान्यता है कि यहां हर सुबह गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शिव का पूजन करने आते हैं। कुछ वर्ष पूर्व पुरातत्व विभाग द्वारा किले के भीतर शिव मंदिर के सामने स्थित कुएं की सफाई के दौरान यहां पांडवकालीन गुफाएं मिली थीं। इन गुफाओं में सात द्वार भी हैं जो किले की तलहटी की ओर खुलते हैं। इन पर अब भी शोध-अध्ययन जारी है। इस स्थान पर नीचे एक भूमिगत भवन भी है। जर्जर होने के कारण पर्यटकों के लिए बंद कर है।

सुंदर झरने और वनसंपदा: असीरगढ़ केवल इतिहास में दर्ज महत्व की वजह से ही चर्चित नहीं है। यहां प्राकृतिक सौंदर्य भी अप्रतिम है। किले के आसपास मौजूद वनसंपदा और वन्य प्राणी पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पक्षियों का कलरव और हरियाली में आत्मिक शांति का अनुभव होता है। यहां के सुंदर झरने मन मोहते हैं।

विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

यूनेस्को की विश्व धरोहर को भी निहारिए

जब असीरगढ़ किले की यात्रा पर आएं तो बुरहानपुर स्थित कुंडी भंडारा जल संरचना की यात्रा भी अवश्य करें। यह विश्व की अनूठी भूमिगत जल संरचना है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहरों की अस्थायी सूची में भी शामिल किया है। इसका निर्माण लगभग चार सदी पूर्व हुआ था। यहां जमीन से अस्सी फीट नीचे घुमावदार नहरें बनी हैं। आप इंदौर और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की यात्रा को इस पर्यटन पैकेज में शामिल कर इसे और समृद्ध कर सकते हैं।

इस तरह पहुंच सकते हैं

असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर इंदौर-इच्छापुर हाईवे के किनारे स्थित है। इटारसी-मुंबई रेलखंड पर चलने वाली यात्री ट्रेन से बुरहानपुर स्टेशन पर उतर कर किले तक पहुंचा जा सकता है। निकटतम इंदौर एयरपोर्ट यहां से करीब 182 किमी दूर है। वहां से सड़क मार्ग से खंडवा होते हुए बुरहानपुर पहुंचा जा सकता है। ठहरने के लिए बुरहानपुर में मप्र पर्यटन विकास निगम के के अलावा निजी होटल भी उपलब्ध हैं।

पोर्न में बच्चों का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक बच्चे का पोर्न देखना एक बार अपराध नहीं भी हो सकता है पर अश्लील फिल्मों में बच्चों का इस्तेमाल होना बहुत ही चिंताजनक विषय है। प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की खंडपीठ ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले फरीदाबाद के एनजीओ (जस्ट राइट्स फार चिल्ड्रेन एलायंस आफ फरीदाबाद) व दिल्ली के 'बचपन बचाओ आंदोलन' की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह गैर सरकारी संगठन बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए काम करते हैं। ज्ञात हो, मद्रास हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को अपने फैसले में कहा था कि पोक्सो एक्ट व सूचना तकनीकी कानून के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना या डाउनलोड करना जुर्म नहीं है। इसी आधार पर आरोपित को बरी कर दिया था।

दैनिक जागरण

सफलता कोई गंतव्य न होकर अनवरत चलने वाली यात्रा है

कांग्रेस के सहयोगी दल

लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण संपन्न हो गया, लेकिन विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए में खटपट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न केवल यह घोषणा की कि कांग्रेस और वामदल आइएनडीआइए के घटक नहीं हैं, बल्कि यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस एवं माकपा ने भाजपा से गुप्त समझौता कर रखा है। उनके इस आरोप पर यकीन करना कठिन है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह बंगाल की जनता को यही संदेश देना चाहती हैं कि अन्य भाजपा विरोधी दलों पर भरोसा करना ठीक नहीं। इस सबसे आइएनडीआइए एक ऐसे समय अपनी एकजुटता का संदेश देने में नाकाम है, जब अभी मतदान के छह चरण शेष हैं। ममता ने इसके पहले भी आइएनडीआइए को तब झटका दिया था, जब उन्होंने बंगाल में अपने बलबूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। आइएनडीआइए के साथ यही व्यवहार केरल में वाम दलों ने भी किया। उन्होंने न केवल वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, बल्कि उन्हें यह सलाह भी दी कि यदि वह भाजपा को हराना चाहते हैं तो उत्तर भारत में कहीं से चुनाव लड़ें। आइएनडीआइए के घटकों के बीच जम्मू-कश्मीर में भी कोई समझौता नहीं हो सका।

कांग्रेस का संकट यह है कि वह सहयोगी दलों के असहयोग भरे रवैये का ढंग से प्रतिरोध भी नहीं कर पा रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह जिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम यानी सहयोगी बताया करती थी, उन्हें हैदराबाद में समर्थन देने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस को बंगाल, केरल, जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों में भी अपने सहयोगी दलों की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। वह दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में उसके खिलाफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां उसे कोई सीट देने को तैयार नहीं हुए। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के पहले जनता दल-यू और राष्ट्रीय लोक दल के आइएनडीआइए से छिटकने से भी कांग्रेस को झटका लगा था। ध्यान रहे जद-यू नेता नीतीश कुमार ही आइएनडीआइए के सूत्रधार थे। आइएनडीआइए की एक समस्या यह भी है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के घोषणा पत्रों में कई मुद्दों पर आम राय नहीं दिख रही है। उलटे कुछ मुद्दों पर तो वे एक-दूसरे की आलोचना तक कर रहे हैं, जैसे माकपा ने सवाल किया है कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून पर चुप क्यों है? कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं कि क्या वह परमाणु हथियार खत्म करने और क्वाड से बाहर निकलने की माकपा की घोषणा से सहमत है? उसे इस पर भी मौन धारण करना पड़ा है कि क्या वह भाकपा की राज्यपाल पद खत्म करने की घोषणा का समर्थन करती है?

पुलिस की लापरवाही

गैंगस्टरों के विरुद्ध पंजाब पुलिस अभियान चला रही है, वहीं इस प्रदेश के तरनतारन में पुलिस की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आना हैरान करने वाला मामला है। गोइंदवाल साहिब जेल से सिविल अस्पताल लाए गए ए कैटेगरी के गैंगस्टर का फरार हो जाना गंभीर मामला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों को जब पता था कि गैंगस्टर के खिलाफ नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसने बैंक में लूट की कोशिश के दौरान एएसआइ को गोली मारी थी, तब सुरक्षा व्यवस्था में कोताही क्यों बरती गई। आखिर तीन पुलिस कर्मचारियों में से दो अस्पताल से घर क्यों चले गए। अस्पताल में जो कांस्टेबल उपस्थित था उसने अपनी ओर से घर जाने के लिए कहा या फिर दोनों पुलिस कर्मचारियों ने किसी अधिकारी से अनुमति ली थी, यह बात सामने आनी चाहिए। एक सवाल यह भी है कि अभी तक लापरवाह पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। इस तरह के मामलों से पुलिस की छवि पर असर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसी लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपित एक गैंगस्टर भी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति यदि होती रही तो स्वाभाविक है कि पुलिस के ऊपर से लोगों का भरोसा कम होगा। राज्य की कानून व्यवस्था के लिए भी इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं हैं। खास करके तब जब आए दिन गैंगस्टर फोन करके व्यापारियों से रंगदारी मांगते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। गैंगस्टर के फरार होने के मामले की गहन जांच होनी चाहिए और इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

जेल से अस्पताल लाए गए ए कैटेगरी के गैंगस्टर का पुलिस हिरासत से फरार हो जाना गंभीर मामला है

पश्चिम एशिया का खत्म न होने वाला टकराव

दिव्य कुमार सोती

इजरायल-ईरान की तनातनी धीरे-धीरे और उग्र रूप धारण कर विश्व के लिए संकट बन सकती है

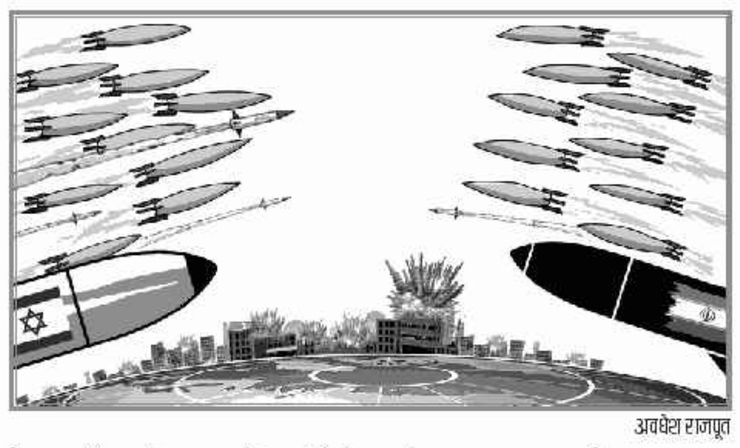

अवधेश राजपूत

इजरायल ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की तो है, लेकिन न तो वह कुछ खुलकर कह रहा और न ही ईरान आधिकारिक रूप से यह स्वीकारना चाहता है कि उसे इजरायल ने निशाना बनाया। इजरायल-ईरान में टकराव की जड़ में हमास द्वारा इजरायल पर गत 7 अक्टूबर को किया गया वह भीषण आतंकी हमला है, जिसमें एक हजार से अधिक इजरायली और अन्य देशों के लोग मारे गए थे। उसके बाद शुरू हुआ गाजा का संघर्ष इजरायल-ईरान युद्ध के कगार पर आकर खड़ा हो गया। यह आसानी से नहीं टलेगा। पिछले सप्ताह ईरान ने इजरायल पर करीब 185 ड्रोन और 150 क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, क्योंकि इजरायली सेना ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास में ईरानी जनरलों को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान सरकार, जो इजरायल को धरती से मिटाने की कसमें खाती है, के पास हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया के तीन बेटे मार गिराए, इसलिए ईरान बौखला गया। यदि वह इजरायल को निशाना न बनाता तो अपने समर्थकों के बीच साख गंवा देता।

सीरिया में ईरानी दूतावास पर बमबारी कर इजरायल ने जिन ईरानी जनरलों को आतंकी साजिश रचने का जिम्मेदार बताते हुए मारा, उन पर दूतावास के बाहर भी हमला किया जा सकता था, परंतु उन्हें दूतावास में ही निशाना बनाया गया। इजरायल अच्छे से जानता था कि ऐसा करना कूटनीतिक प्रोटोकाल और अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन होगा। फिर भी उसने संभवतः ऐसा इसलिए किया, क्योंकि 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद उसने ठान लिया था कि सही समय पर हमास की हरकत के लिए ईरान की जवाबदेही तय की जाएगी। ईरान दशकों से हमास और हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों के जरिये इजरायल पर हमले कराता आया है-ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तानी फौज लश्कर, जैश जैसे संगठनों के जरिये भारत पर आतंकी हमले कराती रही है। अभी तक इजरायल ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर ही जवाबी कार्रवाई करता था, न कि उनके नियंत्रक ईरान पर। हमास के आतंकी हमले के बाद इजरायल का विचार बदला। पूर्व इजरायली पीएम नफ्ताली बैनेट का कहना था कि हमसे यह गलती हुई कि हम आतंक रूपी आक्टोपस के पैरों यानी हमास, हिजबुल्ला से लड़ते रहे, परंतु उसके सिर यानी ईरान को कुचलने की कभी कोशिश नहीं की। सीरिया में अपने दूतावास पर इजरायली हमले के बाद ईरान के पास भी यह विकल्प था कि वह किसी और देश में उसके ठिकानों को निशाना बनाता, लेकिन ईरान के कट्टरपंथी शासक इजरायल को नक्शे से मिटाने के सपने अपने समर्थकों को दिखा रहे थे, इसलिए उनके पास उस पर सीधे हमले के अलावा और उपाय न था।

इजरायल पर ईरान के हमले ने उसके मिसाइल कार्यक्रम की कमजोरी ही उजागर की। इजरायल पर दागी गईं 150 मिसाइलों में से मात्र सात ही निशाने पर लगीं। हमले के समय इजरायल की सुरक्षा में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं एक साथ काम कर रही थीं। आधी से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को मार गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वे इजरायली सीमा में प्रवेश करने से पहले ही गिर गईं। जो सात मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंचीं, वे भी इजरायल के एक सैन्य हवाई अड्डे का मामूली नुकसान कर पाईं। इसके बाद भी इस हमले ने इजरायली जनता के सामने ईरानी खतरे को मूर्त रूप दे दिया और दोनों देशों के बीच प्रतिरोधक क्षमता का संतुलन भी गड़बड़ा दिया। यदि इजरायल इस हमले का जवाब न देता तो भविष्य के लिए संकेत जाता कि ईरान सीधे उस पर बमबारी कर सकता है और फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस समय पश्चिम एशिया में तनाव के चलते अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि की सेनाएं तैनात हैं और ईरानी हमले को विफल करने में उन्होंने इजरायल की पूरी सहायता की, परंतु यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए इजरायल के लिए ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर शक्ति संतुलन बहाल करना जरूरी था, ताकि भविष्य में ईरानी हमले नियमित न हो जाएं। खास बात यह है कि इजरायल ने ईरान पर हमला उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के जन्मदिन के मौके पर किया।

इजरायल के अंदर एक धड़ा है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि यदि वह परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो वह पाकिस्तान की तरह परमाणु युद्ध की धमकी की आड़ में इजरायल के विरुद्ध व्यापक आतंकी युद्ध चलाता रह सकता है। इस धड़े को सऊदी अरब समेत कई सुन्नी देशों का मौन समर्थन है। वे नहीं चाहते कि शिया देश ईरान के पास परमाणु बम हो। जार्डन की वायुसेना ने तो ईरानी हमले को विफल करने में इजरायल की मदद भी की। माना जाता है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ईरानी वैज्ञानिकों को निशाना बनाने के साथ अन्य विध्वंसक कार्रवाई करती आई हैं।

गत दिवस इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीधा निशाना तो नहीं बनाया, पर उन शहरों के सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की, जहां उसके परमाणु संयंत्र भी हैं। ईरानी सूत्र इस हमले को एक छोटा और विफल ड्रोन हमला बता रहे हैं, क्योंकि सच स्वीकारने पर ईरान को फिर से इजराइल पर मिसाइल हमले करने होंगे, जो पहले की तरह विफल कर दिए जाएंगे और उसकी कमजोरी की पोल पुनः खुल जाएगी। ईरान का व्यवहार बालाकोट में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान जैसा है। इजरायल ने शायद इसलिए ईरान पर हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि ऐसा करना रूसी वायुसेना को ईरान में आने का बहाना दे सकता था, जैसा सीरिया में देखा जा चुका है और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल का टकराव पहले ही यूक्रेन में अमेरिका समर्थित प्रतिरोध की धार कुंद कर रहा है। इन दोनों देशों का टकराव विश्व शांति को संकट में डालने वाला हो सकता है, जिसकी जद में ईरानी परमाणु कार्यक्रम भी आ सकता है। चूंकि यह साफ है कि पश्चिम एशिया में शांति के आसार नहीं, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप का खतरा

शशि शेखर वेम्पति

बाहरी संस्थाएं अन्य देशों में चुनावों को प्रभावित करने के बाद भारत पर भी नजर टेढ़ी किए हुए हैं

विदेशी मीडिया के निशाने पर भी हैं आम चुनाव। फाइल

पिछले कुछ हफ्तों में लोकसभा चुनाव से जुड़े विषय फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, अल-जजीरा, यूके गार्जियन और इकोनमिस्ट जैसे वैश्विक मीडिया संस्थान की कवरेज के केंद्र-बिंदु बन गए हैं। इन मीडिया संस्थानों की कवरेज और लेखों के स्वर एवं भाव लगभग एक जैसे हैं और इनकी वजह से भारतीय लोकतंत्र के कमजोर होने से लेकर उसके भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि वैश्विक मीडिया संस्थानों की कवरेज ने भारत में राजनीतिक मतभेदों को और बढ़ाने की कोशिश की है। उत्तर-दक्षिण विभाजन की कल्पना से लेकर न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसे स्वायत्त संवैधानिक निकायों की विश्वसनीयता को कम करने तक, ऐसी विदेशी कवरेज ने पहले वोट डाले जाने के पूर्व ही चुनावी नतीजों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने के प्रयास किए हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत परिष्कृत विदेशी हस्तक्षेप अभियानों का लक्ष्य बन गया है, जो इंटरनेट की व्यापक पहुंच और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की ताकत का लाभ उठा रहे हैं। इसमें भारत अकेला नहीं है। ऐसे कई विदेशी अभियानों ने दुनिया भर में चुनावी प्रक्रियाओं की पवित्रता को खतरे में डाल दिया है। उदाहरण के तौर पर कनाडा और आस्ट्रेलिया ने ऐसे अभियानों का सामना किया है, जिनके बारे में चीनी प्रभाव वाले फंडिंग अभियानों और प्रचार-प्रसार से जुड़े लगभग सिद्ध हो चुके मामले मौजूद हैं। माइक्रोसाफ्ट ने डीपफेक और एआइ के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के माध्यम से चीन की ओर से भारतीय चुनावों को लेकर खतरों के प्रति आगाह भी किया है। कनाडा में प्रवासी भारतीयों और राजनीतिक हस्तियों को प्रभावित करने के गुप्त प्रयासों की रिपोर्टों ने चिंता पैदा की है। इसी तरह, आस्ट्रेलिया अपनी राजनीतिक संप्रभुता पर विदेशी हस्तक्षेप के प्रभाव से जूझ रहा है, जिसके कारण महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए गए हैं तथा जासूसी और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ कानूनों को मजबूत बनाया गया है।

विभिन्न प्रमाणों से यह स्पष्ट हुआ है कि परोक्ष तरीके से भेजी जाने वाली चीनी फंडिंग ने भारतीय मीडिया प्रतिष्ठानों में अपना रास्ता बना लिया है, जो सूक्ष्मता से धारणाओं को बदलने के साथ ही जनता की राय को प्रभावित कर रहा है। न्यूजक्लिक को विदेशी फंडिंग और चीन से जुड़े व्यवसायियों के साथ उसके संबंध का हालिया मामला इसका उदाहरण है। इससे भी अधिक घातक तरीके से, इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों को फर्जी वीडियो एवं डीपफेक कंटेंट को प्रसारित करने का हथियार बनाया गया है, जिससे सच्चाई एवं मनगढ़ंत कहानियों के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं और पीएम मोदी तक ऐसे डीपफेक का शिकार हो गए हैं। वाट्सएप जैसे व्यक्तिगत मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिये गलत जानकारियों के प्रसार ने चुनावी प्रक्रिया में भरोसे को कम करते हुए मतदाताओं को गुमराह करने वाली रणनीति का पता लगाना कठिन बना दिया है।

भारतीय राजनीति पर ऐसी हरकतों के परिणाम दूरगामी होंगे। सूचना इकोसिस्टम में हेरफेर करने के अलावा विदेशी शक्तियां घरेलू तत्वों की पक्षपातपूर्ण राजनीतिक बयानबाजी का सहारा लेकर भारत में सामाजिक भेद को बढ़ा रही हैं। हताश राजनीतिक दल और नेता इस 'घातक' रणनीति का सहारा ले रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में उनकी अनावश्यक और अतिरंजित घोषणाओं का विदेशी शक्तियों द्वारा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने के उद्देश्य से दोहन किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के मूल सार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के नतीजे में विश्वास को खतरे में डाल रहा है। भारत की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीमा पार बैठे एजेंटों की ओर से प्रौद्योगिकी के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के जरिये उत्पन्न होने वाले खतरों को देखते हुए, यह तत्काल निर्णय लेने और कार्रवाई करने का समय है। सूचनाओं के प्रसार में व्याप्त कमजोरियों को दूर करने और चुनावी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है। भारत निर्वाचन आयोग को अन्य सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों के साथ मिलकर इन कमजोरियों को दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका के तहत फोकस अन्य बातों के बजाय मुख्यतः आदर्श आचार संहिता को लागू करने पर केंद्रित रहा है, जबकि इस प्रक्रिया में हो रहे विदेशी हस्तक्षेप पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल, चुनाव प्रक्रिया में हो रहे विदेशी हस्तक्षेप और इसके साथ ही गलत सूचनाओं से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अपने अभियानों से परे जाकर मतदाताओं को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि फर्जी खबरों, दुर्भावनापूर्ण वीडियो और डीपफेक मीडिया की सक्रिय रूप से पहचान की जा सके और उन्हें तत्काल हटाया जा सके। इसी तरह सरकार की फैक्ट्स चेक यूनिट्स को प्रभावकारी उपकरणों या साधनों और व्यापक क्षमता से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है, तभी चुनाव आयोग दृढ़ता के साथ इस दिशा में ठोस कदम उठा सकता है। वास्तव में, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य को अक्षुण्ण रखने के लिए हर हाल में जीतना ही होगा। यह हमारे लोकतंत्र के मजबूत आधार की रक्षा के लिए सतर्कता बरतने, एकता सुनिश्चित करने और सक्रिय उपायों का आह्वान करने का सही समय है। अब इस मोर्चे पर ठोस कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है।

(लेखक प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्य की महत्ता

इस समय संसार में असत्य और कपट का बोलबाला बढ़ रहा है। ऐसे में सत्य की महत्ता को समझना और भी आवश्यक हो गया है। गौतम बुद्ध ने इस संबंध में कहा है कि सत्य को छोड़कर जो असत्य बोलता है, धर्म का उल्लंघन करता है, परलोक की जिसे चिंता नहीं है, वह आदमी बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में संकोच नहीं, वह कोई भी अनर्थ कर सकता है। इसलिए कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न ही झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए।

सत्य को कितने भी पर्दों में क्यों न छुपाकर रख दिया जाए, एक न एक दिन वह प्रकट हो ही जाता है। हमारे मनीषियों ने यथार्थ ही कहा है कि 'मनसा वाचा कर्मणा' यानी मन, वचन और कर्म से सत्य बोलना चाहिए। जो विचार मन में हो वही वाणी में भी होने चाहिए और उसी के अनुरूप ही मनुष्य का व्यवहार भी होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन, वचन और कर्म से अलग रहने वाले पूर्णरूपेण सत्य का आचरण नहीं कर सकते। चूंकि सत्य सदैव कड़वा होता है तो सत्य बोलने वाले समाज में कुछ अलोकप्रिय भी हो जाते हैं।

गांधीजी ने कहा कि सत्य केवल शब्दों की सत्यता ही नहीं, विचारों की सत्यता भी है। हमारी अवधारणा का सापेक्षिक सत्य ही नहीं, बल्कि निरपेक्ष सत्य भी है, जो ईश्वर ही है। गांधीजी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं। हमारे अस्तित्व का एकमात्र औचित्य यही हो कि हमारी समस्त गतिविधि सत्य पर केंद्रित रहे। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। संभव है कि सत्य के बिना भी उसे सफलता मिल जाए, किंतु आंतरिक शांति एवं समग्र संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

एनीमिया से मुक्त होगा भारत!

गीता यादव

एक इंजेक्शन के सफल परीक्षण से देश को एनीमिया मुक्त बनाने की जगी उम्मीद

आयरन की कमी के कारण भारत का हर तीसरा बच्चा जन्म के समय कम वजन का होता है। लगभग 70 प्रतिशत भारतीय महिलाओं और बच्चों में आयरन, जिंक एवं कैल्शियम जैसे पौष्टिक तत्वों की गंभीर कमी पाई गई है। भारत में प्रसव के दौरान होने वाली 20 से 40 प्रतिशत मौतें एनीमिया के चलते होती हैं। पूरी दुनिया में इस कारण जितनी मौतें होती हैं, उनका आधा केवल भारत में होता है। एनीमिया से सबसे ज्यादा पीड़ित गर्भवती महिलाएं होती हैं। आयरन की कमी एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि अन्य स्थितियां जैसे विटामिन बी-12 और विटामिन-ए की कमी, पुराना सूजन, परजीवी संक्रमण और आनुवंशिक विकार आदि भी एनीमिया का कारण हो सकते हैं। देश में गर्भावस्था से जुड़ा एनीमिया स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, जो न केवल मां, बल्कि विकसित हो रहे भ्रूण दोनों पर बुरा असर डालता है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, जिसमें रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में ही एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति बनाई थी। इस अभियान का उद्देश्य पोषण अभियान, टेस्टिंग, डिजिटल तरीके और देखभाल के तरीकों का उपयोग करके एनीमिया का इलाज और सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिये जागरूकता बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने देश को 2047 तक एनीमिया से मुक्ति का लक्ष्य रखा है।

हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली के चिकित्सकों को इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के एक प्रोफेसर का कहना है कि गंभीर एनीमिया होने पर रोगी को रक्त चढ़ाना पड़ता है या गर्भवती महिलाओं को आयरन के पांच से छह इंजेक्शन देने पड़ते हैं। हर सप्ताह एक इंजेक्शन लगता है। लेकिन कई गर्भवती महिलाएं सभी इंजेक्शन नहीं ले पातीं। विदेश में फेरी कार्बोक्सी इसका माल्टोज (एफसीएम) इंजेक्शन किडनी व कैंसर मरीजों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। उसकी कीमत तीन से चार हजार रुपये है। यहां गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की बड़ी समस्या को ध्यान में रखकर उन पर इसका ट्रायल किया गया, जिसमें यह इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षित और असरदार पाया गया। इसके बाद मालिक्यूल में थोड़ा बदलाव करके जेनेरिक स्वदेशी इंजेक्शन तैयार कर लिया गया है। इसकी कीमत भी करीब तीन सौ रुपये है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2024 के निर्देश में शामिल कर लिया गया है। उम्मीद है कि छह माह में मध्यम से गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को यह निःशुल्क मिलने लगेगा। अब दूसरे अस्पतालों में भी गंभीर मरीजों पर इसका उपयोग किया जाएगा और एनीमिया मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

वंशवादी राजनीति पर लगे विराम

'लोकतंत्र पर ही सवाल है वंशवाद' शीर्षक से लिखे आलेख में राज कुमार सिंह ने वंशवादी राजनीति के दम पर उम्मीदवारी हासिल करने वाले नेताओं की विस्तारपूर्वक लंबी सूची प्रस्तुत की है। सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी राजनीति की काट क्या है? इस तरह की राजनीति से देशवासियों को छुटकारा कैसे मिले? जिस राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी, उसकी गिरफ्त में कमोबेश सभी पार्टियां कैसे आ गईं? दुखद है कि ऐसी राजनीति का विरोध करने वाले सबसे अधिक इसमें डूबे नजर आ रहे हैं। बस, भाजपा और अन्य पार्टियों में यह फर्क बचा है कि भाजपा किसी परिवार विशेष की पार्टी नहीं रह गई है, जबकि बाकी लगभग सभी परिवार की पार्टी बनकर रह गई हैं। मानो पार्टी न होकर कोई निजी कंपनी हो। ऐसे में अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है, नए लोगों में राजनीति के प्रति आकर्षण पैदा करना है, तब कुछ न कुछ उपाय तो ढूंढ़ने ही पड़ेंगे। क्या देशवासी यह उम्मीद करें कि वह अपने तीसरे कार्यकाल में इस बुराई का कोई उपयुक्त समाधान दे पाएंगे, क्योंकि देश की जनता को यह भान है कि प्रधानमंत्री में वह माद्दा है जो सामाजिक सुधार के जरिये राजनीति की दशा-दिशा में सुधार कर सकते हैं।

मुकेश कुमार मनन, पटना

वादों की परख करने वाले चुनाव

प्रो. निरंजन कुमार का आलेख 'वादों की परख करने वाले चुनाव' अत्यंत सटीक है। यह चुनाव अनेक प्रकार से अलग है। 18 से 35 वर्ष की आयु वाले 60 करोड़ युवा मतदाता हैं। चीन को छोड़कर इतनी तो किसी देश की जनसंख्या भी नहीं है। यही 60 करोड़ युवा चुनाव परिणाम में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। बेशक रोटी, कपड़ा, मकान आदि की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन कम अवश्य हुई हैं और चुनाव में बड़ा मुद्दा भी नहीं हैं। ये 60 करोड़ युवा अमेरीकी ड्रीम की तरह अपना एक विशिष्ट सपना संजोए हुए हैं। भारतीय ड्रीम में आर्थिक समृद्धि के अतिरिक्त विरासत, संस्कृति, धर्म को लेकर भी सजगता है। यही कारण है कि श्रीराम मंदिर उद्घाटन इतना बड़ा देशव्यापी मुद्दा बन गया। अधिकतर युवा समझ चुके हैं कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसीलिए युवा स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा प्राइवेट सेक्टर में अच्छे करियर के लिए प्रयासरत हैं। लाखों युवा तो रोजगार देने वाले बन चुके हैं। क्षेत्रीय दल आमतौर पर लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसलिए आम मतदाता के समक्ष दो ही प्रभावी विकल्प हैं, भाजपा वाला एनडीए तथा कांग्रेस व बचा-खुचा आइएनडीआइए। वोटर को इनके वादे पूरे करने का रिकार्ड मालूम है। वोटर इसे ध्यान में रखते हुए तथा आगे के लिए किए गए वादों को देखकर वोट डालेगा। मोदी सरकार की विकास उन्मुख राजनीति ने जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति को पीछे छोड़ दिया है। मोदी सरकार ने 2014 तथा 2019 में किए अधिकतर वादे पूरे किए हैं। मुश्किल वादे अनुच्छेद-370 की समाप्ति, तीन तलाक की समाप्ति, श्रीराम मंदिर निर्माण, आतंकवाद की समाप्ति व नक्सलवाद का उन्मूलन भी काफी हद तक पूरे किए हैं। संक्षेप में पिछले वादों की पूर्ति, उपलब्धियां तथा भविष्य के वादों को पूरा कर ही मतदान होगा।

सीपी बंसल, दिल्ली

हम अपनी सीमाओं को समझें

धर्म कुछ मर्यादाएं प्रस्तुत करता है। कुछ व्यक्ति उनका ठीक अर्थ नहीं समझकर, उनकी आलोचना कर बैठते हैं। ऐसा समझते हैं, मानो धर्म के माध्यम से हमें बंधनों में डाला जा रहा है, किंतु यह सत्य नहीं है। धर्म मर्यादा के रूप में कोई बंधन नहीं डालता है। वह तो व्यक्ति को अपनी सीमा का ज्ञान कराता है। यद्यपि विश्व में भोग्य पदार्थ अनंत है, किंतु मानव के पास उनके उपभोग की शक्ति सीमित है। अपनी सीमित शक्ति को पहचान उपभोग को मर्यादित करना बंधन नहीं है। अपितु उपभोग की यह एक रचनात्मक दृष्टि है। व्यक्ति अपनी सीमा को पहचाने बिना उपभोग की तरफ बढ़ता रहेगा तो उसे असफलता और पश्चताप ही प्राप्त होंगे।

कांतिलाल मांडोत नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

1129 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, जो भारत के सामरिक महत्व का क्षेत्र है।

आजकल

न्याय तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग

भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इसमें कई विसंगतियां व्याप्त हैं। हालांकि इन्हें दूर किए जाने का प्रयास किया जाता रहा है, फिर भी भारतीय न्याय प्रणाली में चयन प्रक्रिया अब भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। ऐसे में इसे पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जानी चाहिए, जहां कड़ी प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने वालों को पहले जिला न्यायालयों में नियुक्त किया जा सकता है और अंततः उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया जा सकता है

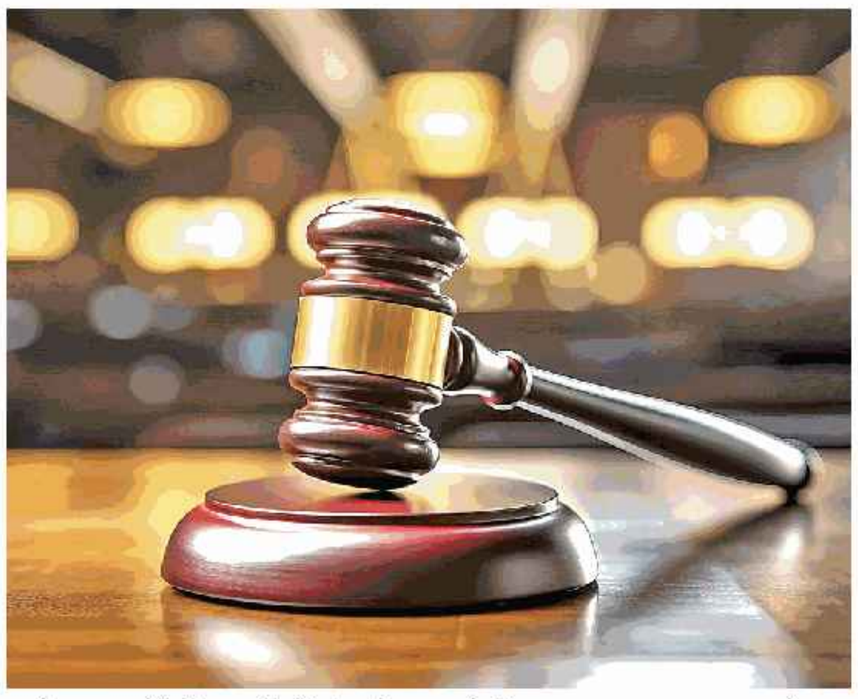

भारतीय न्याय प्रणाली में लंबे समय से विलंबित है सामयिक सुधार की प्रक्रिया। प्रतीकात्मक

सुभाषचंद्र अग्रवाल
आरटीआइ एक्टिविस्ट

भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है, जहां न्यायाधीश उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की संस्तुति करते हैं, जिस कारण विधायिका और न्यायपालिका के बीच निरंतर टकराव होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों एवं तबादलों की सिफारिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कलेजियम प्रणाली की भी कभी-कभी आलोचना की जाती है, क्योंकि कुछ विशिष्ट परिवारों का भारतीय न्यायपालिका में प्रभुत्व है। न्यायपालिका में नियुक्ति, विधायिका के राजनीतिक हाथों में सौंपना भी उचित नहीं होगा। लेकिन एक रास्ता है- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) और बार काउंसिल के नामित सदस्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ एक उच्च-शक्ति वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन हो, जिससे एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीय ऐसे उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का नेतृत्व कर सकते हैं, जिसकी सिफारिशें अंतिम होनी चाहिए। इन्हें औपचारिक समर्थन हेतु सीधे भारत के राष्ट्रपति को भेजी जानी चाहिए। साथ ही, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर बढ़ाकर 65 वर्ष की जानी चाहिए, ताकि केवल तीन अतिरिक्त वर्षों के लिए व्यवस्था में रहने के कारण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति की पैरवी की किसी भी संभावना से बचा जा सके। भविष्य में सुधार के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) की तर्ज पर भारतीय न्यायिक सेवा (आइजेएस) की स्थापना की जा सकती है, जहां कड़ी प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने वालों को पहले जिला न्यायालयों में नियुक्त किया जा सकता है और अंत में उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया जा सकता है।

गृह राज्य से बाहर नियुक्ति : स्थानीय रूप से नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पूर्व बार-सहयोगियों या स्थानीय संबंधों के माध्यम से प्रभावित करने की संभावनाओं को रोकने के लिए, सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनिवार्य रूप से उनके गृह-राज्यों से बाहर नियुक्त किया जाना चाहिए। न्यायपालिका में राजनीतिक पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सके। सेवानिवृत्ति के बाद भी यदि कोई न्यायाधीश राजनीति में शामिल होता है, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद के सभी लाभों से वंचित होना पड़ेगा। किसी भी न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के दो साल बाद कहीं भी सेवानिवृत्ति के बाद कोई नौकरी नहीं दी जानी चाहिए, जैसा कि पिछले शासनकाल के दौरान राज्यसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता ने सही वकालत की थी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीजेआइ के पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले पद पर रहने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय मिलना चाहिए। भारतीय प्रणाली विपरीत मामलों की गवाह है, न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह केवल 18 दिनों (25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991) के लिए सीजेआइ रहे, जबकि न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सात साल से अधिक (22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985) तक सीजेआइ रहे।

निष्पक्षता का सवाल : सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों के खिलाफ सभी शिकायतों की जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, महाभियोग के माध्यम से दागी न्यायाधीशों को हटाने की बोझिल और अव्यवहारिक प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। आयोग के निष्कर्षों और ऐसे दोषी पाए गए न्यायाधीशों के लिए सुझाए गए दंड को कार्रवाई के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए और ऐसे दागी न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद के सभी लाभों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यहां तक कि न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के पहले महाभियोग मामले से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने भी महाभियोग प्रक्रिया को अत्यधिक अव्यवहारिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम द्वारा महाभियोग की सिफारिश करने के निर्णय के बाद करदाताओं की गाढ़ी कमाई एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बिना काम के वेतन देने में बर्बाद हो गई। न्यायाधीश भी उसी समाज से चुने गए इंसान हैं, जिसमें ईमानदार और बेईमान दोनों तरह के लोग हैं। न्यायाधीशों की कुर्सियां किसी दैवीय सामग्री से नहीं बनी हैं जो न्यायाधीश के रूप में प्रवेश पाने वाले किसी अवांछनीय व्यक्ति को निष्पक्ष बना सकें।

पेंशन की व्यवस्था : सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान तय करते समय वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते वेतन आयोग द्वारा तय किए जाने चाहिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कोई असाधारण विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें वर्तमान में उनके और उनके जीवनसाथी के लिए आजीवन घरेलू मदद भी शामिल है। चूंकि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था लगभग समाप्त कर दी गई है, न्यायपालिका (और विधायिका में भी) के लिए भी यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक सभी न्यायाधीशों के लिए फाइल पर मामले से अलग होने का कारण दर्ज करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, किसी न्यायाधीश के समक्ष पीठ की स्थापना या ऐसे मामले को सूचीबद्ध करने पर ऐसी किसी भी अस्वीकृति के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए, ताकि सुनवाई को स्थगित करने की आवश्यकता के बिना सुनवाई के लिए एक नई पीठ गठित हो सके। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश ने एक बार एक मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था, जहां उन्होंने स्वयं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक की कुछ सामग्री को हटाने का आग्रह करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दायर रिट को स्वीकार करने के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को नोटिस जारी किया था। कई बार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को विशेष रूप से राजनेताओं के दबाव और प्रभाव के बारे में लिखा है। मुकरने का कारण बताना अनिवार्य बनाने से न्यायाधीशों पर दबाव और प्रभाव को रोका जा सकेगा।

निर्णय की सरल व्याख्या : कभी-कभी अदालतें सैकड़ों या हजारों पृष्ठों के बहुत लंबे फैसले सुनाती हैं जिन्हें व्यावहारिक रूप से स्वयं वादी भी नहीं पढ़ते हैं। इस तरह के लंबे अदालती फैसले पुस्तकालयों के लिए शो-पीस होते हैं और केवल शोधकर्ताओं एवं चुनिंदा वकीलों द्वारा ही पढ़े जाते हैं। ऐसे में भारत को उन देशों की प्रथा अपनानी चाहिए जहां अदालती फैसलों के पृष्ठों की संख्या पर एक सीमा है जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और ट्रायल कोर्टों के लिए अलग-अलग है। या फिर, 50 पृष्ठों से अधिक के प्रत्येक लंबे अदालती फैसले के साथ अनिवार्य रूप से 50 पृष्ठों की सीमा वाला एक सटीक संस्करण अनिवार्य रूप से जारी किया जा सकता है और निर्णय की तिथि पर ही वेबसाइट पर पोस्ट किया जा सकता है। सुनवाई पूरी होने के एक महीने के भीतर सभी फैसले घोषित किए जाने चाहिए। यदि कोई पीठ मामले की सुनवाई के लिए उच्च पीठ की सिफारिश करने का निर्णय लेती है, तो मामले को पहली बार सूचीबद्ध करने के एक महीने के भीतर पीठ को बड़ी पीठ की सिफारिश करनी चाहिए। (ईआरसी)

नए सिरे से निर्धारित हो अवकाश की व्यवस्था

हमारी न्याय वितरण प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी उदार पूर्व पक्षीय स्थगन आदेश हैं, जिसके बाद अदालतों में बार-बार स्थगन होता है, जो अदालतों में मामलों की लगातार बढ़ती बड़ी संख्या का मुख्य कारण है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय विलंबित की कहावत को सही ठहराया जा रहा है। न्याय अस्वीकृत, यह इस तथ्य के बावजूद है कि सुप्रीम कोर्ट की कई डिवीजन बेंचों ने देखा है और यह कड़वी वास्तविकता भी है कि कभी-कभी बार-बार स्थगन की मांग करने वाले पूर्व-पक्षीय स्थगन आदेश लेने वाले अंततः मामले हार जाते हैं। भारत में ब्रिटिश न्यायाधीशों को इस देश के भीषण गर्म मौसम से बचाने और उन्हें अपनी मातृभूमि इंग्लैंड का दौरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश शासकों द्वारा अदालतों में लंबी गर्मी की छुट्टियों की योजना बनाई गई थी। यह महंगी सुविधा दुर्भाग्य से आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आजाद भारत में जारी है, वह भी लंबे समय तक अदालती मामलों के लंबित रहने के साथ।

लंबी अदालती छुट्टियों को खत्म करने की विधि आयोग की लंबे समय से लंबित सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए। अदालतों को लंबी सर्दी और गर्मी की छुट्टियों के अलावा धार्मिक त्योहारों के लिए सप्ताह भर की छुट्टियों की व्यवस्था को खत्म कर छुट्टियों के लिए सामान्य सरकारी कैलेंडर अपनाना चाहिए। उच्च न्यायालयों के नामकरण को जारी रखने की पूरी प्रणाली भ्रमित करने वाली है, जहां कुछ उच्च न्यायालयों के नाम अभी भी उन शहरों के नाम पर हैं जहां ये स्थित हैं। बहुत समय पहले भारतीय शहरों बांबे, मद्रास, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्रमशः मुंबई, चेन्नई और प्रयागराज कर दिया गया है। लेकिन इन शहरों में स्थित उच्च न्यायालयों का नाम अभी भी आधिकारिक तौर पर इन शहरों के पुराने नामों पर ही चल रहे हैं। व्यवस्था यह होनी चाहिए कि शहरों के नाम बदलने के साथ ही उच्च न्यायालयों के नाम भी स्वतः परिवर्तित हो जाएं। सबसे अच्छा तो यह होगा कि सभी उच्च न्यायालयों के नाम शहरों के बजाय राज्यों के नाम पर रखकर ब्रिटिश विरासत को समाप्त किया जाए। प्रस्तावित कानून में यह सुविधा शामिल होनी चाहिए कि बिना किसी अलग कानून की आवश्यकता के राज्यों या फिर शहरों के नाम बदलने के साथ ही संबंधित उच्च न्यायालयों के नाम अपने आप ही बदले जा सकते हैं।

(सुभाषचंद्र अग्रवाल)

खरी-खरी

समाजवाद आ गया!

पूरन सरमा

देश में समाजवाद एक बार फिर से सिर उठा रहा है। पिछली सदी के आठवें दशक में केंद्र में रही सरकारों ने भरसक प्रयत्न किया था कि देश में समाजवाद आ जाए, परंतु पता नहीं कैसे नहीं आया। अब सरकारें तो किसी अच्छे काम के लिए प्रयत्न ही कर सकती हैं। कुछ समाजवाद की भी गलती है कि यह हमारे देश में जाने क्यों आना ही नहीं चाहता, जबकि हमारे यहां तो समाजवादी भी हैं और समाजवादी पार्टी भी। फिर भी नए सिरे से लाने के लिए लोग पुनः सचेष्ट हो गए हैं। मुझे लगता है कि यदि इसी तरह लगे रहे तो वह दिन दूर नहीं है, जब समाजवाद हर क्षेत्र में आ ही जाएगा। समाजवाद का अर्थ अब अमीर-गरीब की खाई को पाटना भर नहीं है, अपितु हर क्षेत्र में हर नागरिक को समान रूप से कार्य करने का अधिकार मिल जाए तो यह भी समाजवाद ही है।

इधर सांसद भी समाजवाद की ओर अग्रसर हो गए हैं, पहले केवल काम करने की रिश्वत सरकारी कर्मचारी ही लेता था, लेकिन अब सांसद, मंत्री और तमाम राजनेता इस ओर पूरी ईमानदारी से चेष्टा कर रहे हैं। यदि रिश्वत का सार्वजनिकीकरण हो जाता है तो यह समाजवाद ही है। सभी को रिश्वत लेने का अवसर हाथ लग जाए और उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो तो यह हमारे लिए समाजवाद के सन्निकट ले जाती है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की प्रासंगिकता बिलकुल नहीं रही है। जांच आयोगों का हश्र हमलोग पिछले कई दशकों से देख ही रहे हैं। रिश्वतखोर, घोटालेबाज तथा दलालों को समान दृष्टि से देखा जाना ही समाजवाद का पर्याय है।

युग बदला है तो समाजवाद के मायने भी बदल गए हैं। समाजवाद अब हर कोई लाने पर उतारू है। सरकार का किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है और सबको सभी की मेहनत का फल बराबरी से मिल रहा है। अब लोग कर्तव्यों को भूलकर अपने अधिकारों के प्रति इतने जागृत हो गए हैं कि समाजवाद की तरह का वातावरण सब ओर दिखाई देने लगा है। अब समाजवाद को कहीं से उधार लाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमारी सरकारें भी सबको समान अवसर देने का संकल्प कर चुकी हैं।

पोस्ट

कम्युनिस्टों को ऐसे ही भारत की जनता संदेह की दृष्टि से नहीं देखती। माकपा का घोषणा पत्र तो एक उदाहरण भर है, जिसमें देश के परमाणु हथियारों और सैन्य ठिकानों को खत्म करने की बात कही गई है।
सुशांत झा@jhasushant

मेरी समझ में इस चुनाव में कारोबारी तबका वैश्विक अवसरों के लिए वोट करेगा। मध्यवर्ग जीवन की सुरक्षा और अराजकता की आशंका को ध्यान में रखकर मतदान करेगा। हाशिए पर खड़ा समाज सत्ता से जीवन में समृद्धि की आस में वोट करेगा। ऐसे कम ही लोग हैं जो जाति के आधार पर वोट करेंगे। जबकि अल्पसंख्यकों का रुझान तो सार्वजनिक है।
सुमंत@sumantkabir

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो गई। दक्षिण कोरिया से लेकर इजरायल तक भारत जैसा कोई अनूठा लोकतंत्र नहीं। कम से कम विशाल लोकतंत्रों में तो ऐसा कोई भी नहीं है। यहां सत्ता का हस्तांतरण बहुत सुगम तरीके से होता आया है। तमाम आंतरिक कलह लोकतांत्रिक मुकाबले में समाहित हो जाती हैं और हम पहले की तुलना में और अधिक सुरक्षित होते जाते हैं।
हर्ष मधुसूदन@harshmadhusudan

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने से उत्तर भारत में कांग्रेस को लाभ मिलेगा?

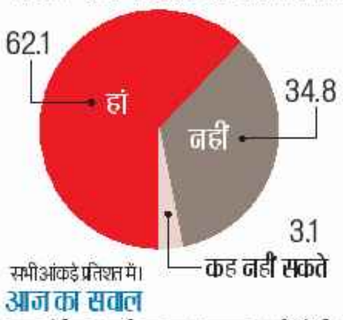

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या रोहित शर्मा का यह कहना सही है कि इंपैक्ट प्लेयर नियम से आलराउंडर खिलाड़ियों की महत्ता घटी है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

गरजे जाय विदेश में अब अपना ब्रह्मोस,
देखि पड़ोसी देश को आएगा कुछ होश।
आएगा कुछ होश रहे ना बस आयातक,
अब हम क्षमतावान कहे जाते निर्यातक।
यही वोट का मूल्य इसे यदि जनता सिरजे,
फिर तो शीश उठाय विश्व में भारत गरजे!
- ओमप्रकाश तिवारी

आलोक मिश्रा
स्थानीय संपादक, बिहार

बिहार डायरी

गर्मी भी नहीं पैदा कर पाई गर्मी

मौसम गर्मी का भी है और लोकसभा चुनाव का भी। ऊपर आसमान से अभी से ही आग बरसने लगी है। गर्म हवाओं के थपेड़े चलने लगे हैं। जिस समय यह डायरी लिखी जा रही है, उस समय पहले चरण के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। देश के 102 एवं बिहार के चार लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़ चुके हैं। देश के भविष्य की पटकथा लिखी जा रही है, लेकिन बिहार में मतदाताओं की सुस्ती पिछले चुनावों की तरह ही बनी हुई है। कुछ हद तक गर्मी ने तो कुछ स्वयं की उदासीनता ने उन्हें ठंडा कर रखा है। जबकि देश में कई राज्यों के मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। अभी भी समय है, अगर चेत जाएं तो तस्वीर बदल सकती है।

देश की राजनीति में बिहार की भूमिका को बताने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक रूप से बिहार बहुत जाग्रत है। देश की राजनीति में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन चुनाव में सौ प्रतिशत मतदान यहां के लिए अब तक सपना ही है। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। तमाम सार्वजनिक स्थानों से लेकर चौराहों और घरों तक में राजनीति की ही चर्चा होती है। हर व्यक्ति यहां राजनीतिक रूप से सजग है। जो थोड़ा भी सक्रिय है, उसकी पकड़ राजनीति में जरूर रहती है। लेकिन यह सब कुछ मतदान केंद्रों पर नहीं दिखता। आप बिहार में किसी से भी बात करेंगे तो वह किसी भी योजना में सौ कमियां बता सकता है। उसके सामने कई मुद्दे रहते हैं, जिनके प्रति वह सजग दिखता है, तमाम तर्क हर चौक-चौराहों पर रखता दिखता है। तमाम चुप्पी भी साधे रहते हैं। भीतर ही भीतर घुटते भी रहते हैं। पर वे अपने वोट की ताकत का उपयोग करने आते ही नहीं हैं। जबकि अब जमाना वो भी नहीं है कि वोट डालने से कोई रोक सके।

नवादा लोकसभा क्षेत्र के अकबरपुर मध्य विद्यालय में मतदान केंद्र पहुंचे गिनती के मतदाता। जागरण

वस्तुतः बिहार में पिछले चुनाव में देश के औसत मतदान प्रतिशत से दस प्रतिशत कम वोट पड़े। देश में 67 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ तो बिहार में 57 प्रतिशत पर ही टिक गया। बात वर्ष 1999 से शुरू करते हैं। उस समय 61 प्रतिशत से कुछ अधिक वोट पड़े थे। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे लोगों में तमाम विषयों को लेकर जागरुकता बढ़ती गई, वैसे वैसे वोट प्रतिशत कम होता गया। वर्ष 2004 में 56 प्रतिशत और 2009 में तो 44 प्रतिशत पर अटक गया। वर्ष 2014 में फिर से बढ़कर 56 प्रतिशत के थोड़ा ऊपर पहुंचा और 2019 में यह बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया। लेकिन इस बार जो माहौल है, उसके अनुसार दोपहर एक बजे तक की स्थिति ही दिल धड़काने लगी। देश के अन्य हिस्सों की तरह यहां की संख्या बढ़ती नजर नहीं आई। यहां जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़े हैं। जहां पिछली बार जमुई में 55, औरंगाबाद में 53 और 54 के बीच, गया में 56 एवं नवादा में लगभग 50 प्रतिशत वोट पड़े थे। वहीं इस बार भी एक बजे तक जमुई में सबसे अधिक 34 प्रतिशत वोट पड़े। जबकि औरंगाबाद में 29.5 प्रतिशत, गया में 30 प्रतिशत एवं नवादा में केवल 27 प्रतिशत वोट ही पड़े। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में यह प्रतिशत कहीं अधिक था। शाम छह बजे तक रफ्तार औसत ही रही।

बंगाल एक बजे तक आंकड़ा 50 प्रतिशत के पार पहुंच गया था और तीन बजे तक 67 प्रतिशत तक। जबकि बिहार में मतदान समाप्त होते-होते आंकड़ा पिछली बार से आगे नहीं बढ़ सका। बिहार निर्वाचन विभाग के अनुसार छह बजे तक औरंगाबाद में अनुमानित आंकड़ा 50 प्रतिशत तक पहुंचा, जबकि गया में 52, नवादा में 41.5 और जमुई में 50 प्रतिशत तक पहुंचा। पूरी संख्या आने पर भी इन क्षेत्रों में पिछली बार से कमजोर प्रदर्शन ही रहता दिखाई दे रहा है। ये चारों सीटें पिछली बार एनडीए के पास थीं। इस बार कम वोटिंग किसे प्रभावित करेगी और किसे लाभ पहुंचाएगी ये तो गणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वोटिंग की यह घटती रफ्तार चिंताजनक है। यह यहां की उदासीनता को तो दर्शाती ही है और देश में भी यहां के लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति सजगता पर भी सवाल खड़ा करती है। अभी पहले चरण का चुनाव ही हुआ है। छह चरण की 36 सीटों पर वोट पड़ना बाकी है। देखना है कि आगे लोग चेतते हैं और वोट देने निकलते हैं या इस बार भी राष्ट्रीय औसत से नीचे ही रहते हैं।

मंथन

शरारत से बाज नहीं आ रहा चीन

अरुणाचल प्रदेश की तरफ से चीन भारत को घेरने के प्रयास में रहता है। इस राज्य की भौगोलिक अवस्थिति और संसाधन जनित महत्ता को समझते हुए चीन के प्रति हमें सतर्क रहना होगा

लेफ्टिनेंट जनरल एम. के. दास
पूर्व सैन्य अधिकारी

चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 काउंटी प्रशासनिक केंद्रों, गांवों, टाउनशिप, पर्वत चोटियों और नदियों/झीलों का नाम बदलकर तिब्बती या चीनी अक्षरों में करने की अपनी बेतुकी रणनीति जारी रखी है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत के रूप में संदर्भित करता है और इसे 'जंगन' कहता है। चीन ने अरुणाचल में पहले भी इस तरह के नामकरण की कवायद की है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मजबूत करने के लिए चीन नए नामों के साथ अरुणाचल प्रदेश का नक्शा भी जारी करता है।

वस्तुतः भारत के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहीं है। यह राज्य पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्यांमार से घिरा है, जबकि इसके दक्षिण में असम है। नगालैंड से भी यह जुड़ा है। साथ ही इसकी उत्तरी सीमा चीन के सटी है। अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह 1914 में ब्रिटिश भारत के दौरान मैकमहोन रेखा द्वारा सीमांकित चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) के साथ 1129 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और अब चीन द्वारा विवादित है। इसलिए इस सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) कहा जाता है। चीन के साथ पूरी एलएसी 3,488 किमी लंबी है, जो पश्चिम में अक्साई चिन से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। लद्दाख के अक्साई चिन में 15,500 वर्ग किमी भारतीय क्षेत्र पर चीन का अब भी नियंत्रण है, जिस पर उसने 1962 में कब्जा कर लिया था।

खनिज संसाधन संपन्न राज्य : अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे पर चीन लगातार भारत को तंग करता रहता है। आखिर अरुणाचल में चीन का वास्तविक हित क्या है? एक कारण तवांग मठ का महत्व है जो दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। दूसरा, इसका बड़ा हित विवादित अक्साई चिन में है, जहां से वह शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ने के लिए एलएसी के करीब एक राजमार्ग का निर्माण कर रहा है। एक कारक जिसका आमतौर पर उल्लेख नहीं किया जाता है, वह अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हाइड्रोकार्बन सहित विशाल जल और खनिज संसाधन हैं।

अरुणाचल का असम और नगालैंड के साथ घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इसके विपरीत, एलएसी ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम इलाके में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के छात्रों को राज्य और क्षेत्र के साथ हमारे प्राचीन संबंधों का दस्तावेजीकरण करने के लिए इतिहास पर ईमानदारी से शोध करना चाहिए। चीन से नियमित रूप में अरुणाचल के निवासियों के लिए स्टेपलेड वीजा दिया जाता है। बीते माह नौ मार्च को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेला सुरंग के उद्घाटन सहित किसी भी वीआइपी यात्रा को नियमित तौर पर आपत्ति की जाती है। अब जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चीन किसी ऐसी गतिविधि को अंजाम दे सकता है जो भारत को असहज करे। जहां तक हालिया विवाद का संबंध है, दलाई लामा से इस बार भारतीय हित के लिए अधिक समर्थन नहीं मिला।

ताजा इनपुट अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के सामने 175 और गांवों को विकसित करने की चीन की योजना के बारे में है। ये बस्तियां सीमावर्ती गांवों के रूप में कार्य करके चीन की सैन्य तैयारियों को और बढ़ाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा असहज करने वाली बात माइक्रोसाफ्ट की यह खबर है कि चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा बनाए गए झूठे आख्यानों के माध्यम से जनता की राय को प्रभावित करके भारत में चुनावों में हस्तक्षेप करने की योजना बना रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार नई चुनौती का सामना कैसे करती है जो इंटरनेट मीडिया के जरिये राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकती है।

भारत ने हाल ही में चीन की कार्टोग्राफिक और अन्य प्रतिकूल गतिविधियों का बेहतर जवाब दिया है। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का विकास काफी बेहतर है। फर्स्ट विलेज नामक योजना के माध्यम से सीमावर्ती गांवों को और बेहतर बनाने के लिए बड़ी संख्या में परियोजनाएं चल रही हैं। उत्तराखंड में माना को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के पहले गांव के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने कहा था कि हर सीमावर्ती गांव पहला गांव होना चाहिए, न कि देश का आखिरी गांव।

सैनिकों की स्थायी तैनाती के मामले में भारत बहुत मजबूत है, लेकिन हमें चीन के प्रति पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं और प्रतिद्वंद्वियों के रूप में भारत और चीन अनिवार्य रूप से एक-दूसरे के साथ टकराएंगे। वर्ष 2047 तक एक संभावित महाशक्ति के रूप में भारत के बढ़ते उदय को किसी न किसी रूप में चीन की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति की जरूरत होगी।

अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक किया जा रहा संपर्क माध्यमों का विस्तार। फाइल

****

एजिलिटास ने लोटो का 'ब्रांड लाइसेंस' हासिल किया

नई दिल्ली : खेल-कूद से जुड़े परिधान और जूते बनाने वाली एजिलिटास स्पोर्ट्स ने 40 साल के लिए भारत तथा अन्य बाजारों के लिए डब्ल्यूएचपी ग्लोबल से इटालियन स्पोर्ट्स ब्रांड लोटो का 'ब्रांड लाइसेंस' हासिल किया है। दीर्घकालिक लाइसेंस के जरिये एजिलिटास के पास भारत, आस्ट्रेलिया और जल्द ही दक्षिण अफ्रीका में लोटो ब्रांड के डिजाइन, निर्माण, प्रचार तथा वितरण का विशेष अधिकार होगा। (प्रेट्र)

बंधन लाइफ के साथ हम सभी हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए डिजिटल नवाचार तथा मजबूत वितरण की अपनी सहयोगी ताकत को बढ़ा रहे हैं।
— सतीश्वर बी, एमडी और सीईओ, बंधन लाइफ

सेंसेक्स	73,088.33	599.34	निफ्टी	22,147	151.15	सोना प्रति दस ग्राम	₹74,100	₹400	चांदी प्रति किलोग्राम	₹86,600	₹100
डालर	₹83.44	₹0.08	क्रूड (बैंट) प्रति बैरल	$ 87.62							

एक नजर में

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा तो महंगाई में होगी वृद्धि

नई दिल्ली : बैंक आफ बड़ौदा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इससे वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा बढ़ते संघर्ष ने सुरक्षित संपत्तियों में निवेश की ओर लोगों को प्रेरित किया है और यही वजह है कि सोना, डालर और येन की कीमतों में वृद्धि दिखाई दे रही है।(एएनआइ)

नारायण मूर्ति के पोते को लाभांश से मिले 4.2 करोड़

नई दिल्ली : इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के पांच महीने के पोते एकाग्र मूर्ति ने कंपनी द्वारा घोषित किए गए लाभांश से 4.2 करोड़ रुपये कमाए हैं। एकाग्र के जन्म पर मूर्ति ने उन्हें 240 करोड़ रुपये कीमत के इन्फोसिस के 15 लाख शेयर (0.04% हिस्सेदारी) गिफ्ट दिए थे, जिसके बाद वह सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए थे। (आइएएनएस)

पीई और वीसी निवेश मार्च तिमाही में मामूली घटा

मुंबई : निजी इक्विटी (पीई) और उद्यम पूंजी (वीसी) कोषों का निवेश मार्च तिमाही में सालाना आधार पर एक प्रतिशत घटकर 13.5 अरब डालर रहा। दिसंबर, 2023 तिमाही की तुलना में यह निवेश 41 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, मात्रा के लिहाज से जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में पीई एवं वीसी निवेश सौदों की संख्या 292 थी, जो एक साल पहले के 220 की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।(प्रेट्र)

16 साल के निचले स्तर पर आया गेहूं का स्टाक

नई दिल्ली : गेहूं का स्टाक 16 सालों के अपने निचले स्तर पर आ गया है। एफसीआइ के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में गेहूं का भंडार 7.5 मिलियन टन (75 लाख टन) था, जो एक साल पहले के 8.35 मिलियन टन (83.5 लाख टन) से कम था। एक अधिकारी ने बताया कि स्टाक में कमी आई है, क्योंकि मूल्य स्थिर रखने के लिए एक करोड़ टन गेहूं खुले बाजार में बेचना पड़ा।(राइटर)

मैन्यूफैक्चरिंग और निर्यात बढ़ाने के लिए नई स्कीम

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दे रहा अंतिम रूप, इसके लिए दर्जनभर सेक्टरों का किया गया है चयन

- सरकार इन सेक्टरों के लिए यातायात, बिजली सप्लाई, लाजिस्टिक, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी जरूरतों को करेगी पूरा
- उद्यमियों को नए बाजार से लेकर सस्ते दाम पर कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकारी एजेंसियां करेंगी मदद

जागरण ब्यूरो नई दिल्ली : मैन्यूफैक्चरिंग के साथ वस्तु निर्यात में बढ़ोतरी को लेकर वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय इन दिनों नई सरकार में अपने 100 दिनों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, मैन्यूफैक्चरिंग व निर्यात प्रोत्साहन के लिए दर्जन भर सेक्टर का चयन किया जा रहा है। इन सेक्टर में निर्यात बढ़ाने की बड़ी संभावना है, जिससे भारत दुनिया की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन सकेगा। सरकार वर्ष 2030 तक निर्यात को एक लाख करोड़ डालर तक ले जाना चाहती है और इन सेक्टर का इस लक्ष्य की प्राप्ति में अहम भूमिका हो सकती है।

इन सेक्टर में भारत को वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उनकी यातायात, बिजली सप्लाई, लाजिस्टिक, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी जरूरतों को पूरा करने की भी तैयारी की जाएगी। उनके लिए ऐसे नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार की नियामक एजेंसियों के साथ नहीं उलझना पड़े और कम से कम प्रक्रियाओं का सामना करना पड़े। इनके टैक्स के प्रारूप को लेकर भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दर्जनभर सेक्टर में मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने के लिए उद्यमियों को इंसेंटिव देने से अधिक उनकी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने पर जोर होगा। नए बाजार से लेकर सस्ते दाम पर कच्चे माल की उपलब्धता में सरकारी एजेंसियां उनकी मदद कर सकती हैं। हो सकता है नई सरकार के गठन के 100 दिनों के भीतर इन सेक्टर के लिए इंसेंटिव की भी घोषणा हो।

फुटवियर को फोकस सेक्टर में किया गया है शामिल

ड्रोन और आटोमोबाइल सेक्टर को फोकस एरिया में इसलिए शामिल किया गया है, क्योंकि भारत में इन सेक्टर में अपने उत्पादन को काफी अधिक बढ़ाने की संभावना है। हाल ही में सरकार ने फुटवियर पर क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू करने की घोषणा की है, जिससे फुटवियर इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसलिए इसे फोकस सेक्टर में शामिल किया गया है।

मेडिकल डिवाइस में होंगे आत्मनिर्भर

भारत मोबाइल फोन निर्माण में बढ़त हासिल करने के बाद अब सेमीकंडक्टर निर्माण की पूरी चेन को घरेलू स्तर पर विकसित करना चाहती है। इसलिए ईएसडीएम को फोकस सेक्टर में शामिल किया गया है। भारत जरूरत का 60 प्रतिशत से अधिक मेडिकल डिवाइस आयात करता है। इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है। केमिकल को भी फोकस एरिया में शामिल किया गया है।

ये सेक्टर किए गए हैं शामिल : आटो कंपोनेंट्स, आटोमोबाइल (ईवी भी) कैपिटल गुड्स, केमिकल, इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम), मेडिकल डिवाइस, लेदर-फुटवियर।

महंगाई के मोर्चे पर मिली कामयाबी को टिकाऊ बनाने की जरूरत

आरबीआइ ने जारी किया मौद्रिक नीति समिति की बैठक का विवरण, रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर रखा था बरकरार

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा है कि मुद्रास्फीति के मोर्चे पर मिली सफलता को टिकाऊ बनाने की जरूरत है। दास ने इस महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में नीतिगत दर में यथास्थिति बनाये रखने के लिए मतदान करते हुए यह बात कही। आरबीआइ ने शुक्रवार को एमपीसी की बैठक का ब्योरा जारी किया।

एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक के बाद आरबीआइ ने रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया। मुद्रास्फीति पर चिंताओं के बीच रेपो रेट फरवरी 2023 से इसी स्तर पर बनी हुई है। दास ने कहा, 'मुद्रास्फीति को कम करने के लिए पिछले दो वर्षों में जो लाभ हुआ है, उसे बरकरार रखना होगा। टिकाऊ आधार पर सकल मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के लक्ष्य तक लाने के लिए काम करना होगा।' एमपीसी के छह सदस्यों में पांच ने नीतिगत दर में यथास्थिति के पक्ष में मतदान किया था। एमपीसी सदस्य जयंत आर वर्मा ने हालांकि रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती की वकालत की थी। दास ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और जिंस कीमतों तथा सप्लाई चेन पर उनके प्रभाव भी मुद्रास्फीति को लेकर अनिश्चितताओं को बढ़ा रहे हैं।

शक्तिकांत दास

बीते वित्त वर्ष में ईपीएफओ से 1.65 करोड़ नए सदस्य जुड़े

- साढ़े छह सालों में ईपीएफओ से जुड़े 6.1 करोड़ से अधिक सदस्य
- श्रमिक-जनसंख्या अनुपात व श्रम बल भागीदारी में दिख रहा सुधार

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से 1.65 करोड़ लोग जुड़े। यह एक साल पहले की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारियों से संबंधित नवीनतम आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'पिछले साढ़े छह सालों में 6.1 करोड़ से अधिक सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े हैं, जो नौकरी बाजार के सामान्य होने का संकेत है।'

ईपीएफओ ने 2018-19 में शुद्ध रूप से 61.12 लाख सदस्य जोड़े थे, जो 2019-20 में बढ़कर 78.58 लाख हो गए। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 में यह संख्या घटकर 77.08 लाख रह गई। इसके पीछे मुख्य वजह कोरोना महामारी थी। स्थिति सुधरने पर 2021-22 में 1.22 करोड़ नए सदस्य और 2022-23 में 1.38 करोड़ सदस्य जुड़े। पीएलएफएस रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) से संबंधित संकेतकों में 2017-18 से 2022-23 तक सुधार की प्रवृत्ति दिखती है। डब्ल्यूपीआर 2017-18 में 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 56 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह श्रम बल की भागीदारी भी 2017-18 में 49.8 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 57.9 प्रतिशत हो गई है। वहीं बेरोजगारी दर 2017-18 में छह प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है।

विदेशी मुद्रा भंडार 5.40 अरब डालर घटकर 643.16 अरब डालर पर

मुंबई, प्रेट्र : विदेशी मुद्रा भंडार 12 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 5.40 अरब डालर घटकर 643.16 अरब डालर रहा। पिछले कारोबारी सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.88 अरब डालर बढ़कर 648.56 अरब डालर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया था।

आरबीआइ के मुताबिक, 12 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 6.51 करोड़ डालर घटकर 564.65 अरब डालर रह गईं। डालर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। आरबीआइ ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 1.24 अरब डालर बढ़कर 55.79 अरब डालर हो गया। आरबीआइ ने कहा कि विशेष आहरण अधिकार 9.3 करोड़ डालर घटकर 18.08 अरब डालर रह गया।

गिरावट थमी, सेंसेक्स 599 अंक उछला

- बैंक और वाहन शेयरों में कम मूल्य पर अधिक खरीदारी से बढ़त के साथ बंद हुए बाजार
- नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 151 अंक उछलकर 22,147 के स्तर पर बंद हुआ

मुंबई, प्रेट्र : बैंक एवं वाहन शेयरों में कम मूल्य पर अधिक खरीदारी आने से घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को शुरुआती निचले स्तर से उबरकर बढ़त के साथ बंद हुए और चार दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 599.34 अंक यानी 0.83 प्रतिशत चढ़कर 73,088.33 पर बंद हुआ। हालांकि सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला था और शुरुआती कारोबार में 672.53 अंक यानी 0.92 प्रतिशत तक लुढ़कते हुए 71,816.46 के निचले स्तर तक खिसक गया था। लेकिन बैंक शेयरों में खरीदारी आने से सेंसेक्स तेजी पकड़ने में सफल रहा। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का सूचकांक निफ्टी भी 151.15 अंक यानी 0.69 प्रतिशत उछलकर 22,147 अंक पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में यह 21,777.65 के निचले स्तर तक गिर गया था लेकिन बाद में बढ़त के साथ बंद हुआ।

बढ़त में रहने वाले शेयर

बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति, विप्रो, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, आइसीआइसीआइ बैंक और आइटीसी

गिरने वाले शेयर

नेस्ले इंडिया, एचसीएल, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

सोना 400 रुपये उछला, चांदी नए रिकार्ड स्तर पर

नई दिल्ली, प्रेट्र : वैश्विक स्तर पर तेजी के रुझान के चलते सोने और चांदी की कीमतें शुक्रवार को नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गईं। दिल्ली में सोना 400 रुपये चढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 74,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 100 रुपये बढ़कर 86,600 रुपये प्रति किलोग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। विदेशी बाजारों में कामेक्स पर सोना हाजिर 2,390 डालर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी बढ़कर 28.29 डालर प्रति औंस पर बोली गई। पिछले बंद में यह 28.25 डालर प्रति औंस पर बंद हुई थी।

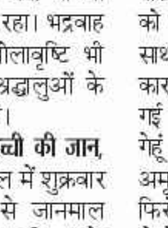

सूचीबद्ध बीमा कंपनियों में एलआइसी का प्रीमियम सर्वाधिक बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : एलआइसी ने मार्च में 36,300.62 करोड़ रुपये का कुल प्रीमियम एकत्र किया। यह एक साल पहले के 28,716.23 करोड़ रुपये से 26.41 प्रतिशत अधिक है। पिछले महीने प्रीमियम संग्रह के मामले में एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 24.76 प्रतिशत वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद आइसीआइसीआइ प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम संग्रह में 12.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

बीमा कंपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम संग्रह मार्च, 2024 में 20.05 प्रतिशत घट गया। एलआइसी ने जीवन बीमा परिषद द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रीमियम संग्रह के मामले में मार्च, 2024 तक उसकी बाजार हिस्सेदारी सर्वाधिक 58.87 प्रतिशत थी। मार्च 2024 में एलआइसी के समूह वार्षिक नवीकरणीय प्रीमियम में 200.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राष्ट्रीय फलक

गुस्सा सरकार पर, परेशान हो रही आम जनता

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

67 दिन से शंभू बार्डर बंद, तीन दिन से शंभू में रेलवे ट्रैक पर भी किसानों ने लगाया पक्का धरना, यात्री हो रहे परेशान

अमृतसर रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में इंतजार करते हुए यात्री। राघव शिकारपुरिया

क्या कहते हैं अधिकारी

किसान संगठनों के साथ बातचीत चल रही है। कोशिश की जा रही है कि वह खुद ही ट्रैक खाली कर दें।
– अर्पित शुक्ला, डीजीपी (कानून व्यवस्था)

आयोग का काम चुनाव करवाना है। कानून व्यवस्था देखना सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव में अगर कानून व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है तो आयोग दखल देता है। रेलवे ट्रैक पर धरना चल रहा है तो यह देखना पुलिस प्रशासन का काम है। – सिबिन सी, मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) ने हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अपने तीन साथियों की रिहाई के लिए बुधवार से पटियाला जिले के शंभू स्थित रेलवे स्टेशन के रेल ट्रैक पर धरना लगा रखा है। इस कारण लुधियाना के रास्ते अंबाला और अंबाला से लुधियाना की तरफ आने वाली ट्रेनों को डायवर्ट कर चलाना पड़ रहा है। कुछ को रद करना पड़ रहा है। इसके चलते अधिकतर ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। रेलवे स्टेशनों पर यात्री भी यही बात कह रहे हैं कि किसानों की नाराजगी हरियाणा और केंद्र सरकार से है। वे आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं। उधर, शंभू और संगरूर जिले के खनौरी बार्डर पर भी 13 फरवरी से नेशनल हाईवे जाम कर रखा है। 67 दिन से नेशनल हाईवे बंद होने के कारण वाहनों को भी दूसरे रास्तों से निकाला जा रहा है।

मां गंगा में बीमार है और ट्रेन हो गई कैंसल : लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर बिहार के किशनगंज निवासी मोहम्मद उदास बैठा था। उसने बताया कि उसकी मां गांव में बीमार है और उसे किशनगंज जाना है। 17 अप्रैल की उसकी टिकट थी, लेकिन कर्मभूमि एक्सप्रेस कैंसल हो गई। अब दो दिन से वह स्टेशन आ रहा है, लेकिन ट्रेन नहीं मिल रही है। घर से बार-बार फोन आ रहा है कि वह गांव जल्दी पहुंचो। अब शनिवार को आम्रपाली से कटिहार जाएगा और वहां से किशनगंज के लिए गाड़ी पकड़ने की कोशिश करेगा।

शुक्रवार को कुल 83 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इनमें से 21 ट्रेनों को रद करना पड़ा वहीं, 54 को रूट डायवर्ट कर चलाया गया और आठ को शार्ट टर्मिनेट कर चलाया गया। बता दें कि किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों को लेकर

आइएएस नवीन का मुख्यालय नोएडा स्थापित करने का आग्रह ठुकराया

राज्य ब्यूरो, जागरण, शिमला : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आइबीपीएस) की क्लर्क भर्ती परीक्षा दूसरे के स्थान पर देने के दोषी निलंबित आइएएस नवीन तंवर ने हिमाचल सरकार से आग्रह किया था कि निलंबन के दौरान उसका मुख्यालय नोएडा में स्थापित किया जाए। इस आग्रह को राज्य सरकार ने ठुकरा दिया है।

2019 बैच के आइएएस अधिकारी नवीन तंवर को 14 मार्च, 2024 को गाजियाबाद की न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआइ की अदालत ने तीन साल कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने उसे निलंबित कर मुख्यालय शिमला स्थित राज्य सचिवालय तय किया था। निलंबन से पहले गाजियाबाद निवासी नवीन चंबा जिला के भरमौर में अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर कार्यरत था। तंवर ने लिखा था कि जमानत के बाद उन्हें शर्तों के अनुसार वहीं रहना पड़ेगा।

हिमपात से गिरा पारा, मैदान में वर्षा से खेती प्रभावित

जागरण टीम, नई दिल्ली

- घाटी में मौसम ने दिखाए कई रंग, कभी तेज हवा, वर्षा, ओलावृष्टि तो कभी निकली धूप
- तापमान में गिरावट से बाधित होगी सेब की सेटिंग, गेहूं की कटाई का काम हुआ प्रभावित

उत्तर भारत में गर्मी बढ़ रही है। मगर पहाड़ों में हिमपात होने से हल्की ठंड बनी हुई है तो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के कारण कई जगह फसलों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में तड़के से ही झमाझम वर्षा हुई, जबकि घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हुई तो कहीं दिन में तेज हवा के साथ ओले भी गिरे। दिन में कुछ देर धूप खिली तो शाम होते होते फिर वर्षा शुरू हो गई। हिमचल में भी दोपहर बाद चली आंधी से जानमाल का नुकसान हुआ है। साथ ही गेहूं की कटाई का कार्य भी बाधित हुआ है। पंजाब में भी वर्षा के कारण गेहूं की पकी फसल खेतों में बिछ गई है।

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन के गांगरू में भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात ठप हो गया। शाम करीब साढ़े पांच बजे मलबा हटाकर यातायात बहाल किया गया। ताजा बर्फबारी व बारिश से तापमान में फिर से गिरावट आने से पूरी घाटी फिर से ठंड की चपेट में आ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भी विभिन्न क्षेत्रों में रुक-रुक कर वर्षा का क्रम जारी रहेगा। दूसरी ओर जम्मू और आसपास के क्षेत्रों तड़के से ही वर्षा का सिलसिला शुरू हो गया थो जो रुक-रुक कर दिन भर जारी रहा। भद्रवाह में मौसम वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हुई। वहीं, वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए चापस सेवा बाधित रही।

हिमाचल में आंधी ने ली बच्ची की जान, फसलों को नुकसान : हिमाचल में शुक्रवार दोपहर बाद चली आंधी से जानमाल का नुकसान हुआ है। कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर क्षेत्र की गंगोट पंचायत के रेही गांव में शाम करीब पांच बजे तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची आयशाना आंगन में खेल रही थी, तभी आंधी के कारण मकान की छत टूट गई और ग्रिल की चपेट में आ गई। वहीं, कुल्लू जिला के तहत मनाली के भूतनाथ चौक के पास देवदार का पेड़ गिरने से 10 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और एक भवन को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में कई क्षेत्रों में गेहूं की कटाई चल रही है, यह कार्य बाधित हुआ है। जिन बागवानों ने एंटी हेल नेट (जालियां) नहीं लगाए हैं, उन्हें नुकसान हुआ है।

पंजाब में भी गेहूं को हुआ नुकसान : पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से शुक्रवार को पंजाब के कई जिलों में तेज हवा के साथ वर्षा व ओलावृष्टि हुई। तेज हवा के कारण गेहूं की पकी फसल खेतों में बिछ गई है। कई जिलों में मंडियों में पहुंची गेहूं की फसल भी भीग गई। जालंधर, अमृतसर, पठानकोट, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर सहित कई जिलों में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने देर रात तक कई जिलों में वर्षा व ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट भी जारी किया है।

अभिव्यक्ति की आजादी दूसरों के सम्मान से परे नहीं : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपित को राहत से इन्कार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी को दूसरों की भावनाओं व विश्वासों के सम्मान से परे नहीं रखा जा सकता। याची की तरफ से जानबूझकर धार्मिक अपमान किया गया है। लिहाजा, आपराधिक मामले को रद नहीं किया जा सकता। इंटरनेट मीडिया पर भगवान शिव पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपित ओवैस खान को राहत देने से इन्कार कर दिया है।

पीठ ने कहा,विभिन्न समुदायों की धार्मिक मान्यताओं के प्रति सम्मान बनाए रखना सबका कर्तव्य है। अदालतें नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को अधिक महत्व देती हैं। ऐसी भावनाओं को अपमानित करने का कार्य सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ बहुलवादी समाज के पोषित मूल्यों का गंभीर अपमान है। यह लोकतंत्र की भावना को भी कमजोर करता है।

आरोपित पर भगवान शिव के खिलाफ गलत टिप्पणी कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप है। उसके खिलाफ अलीगढ़ में प्राथमिकी लिखी गई है। पुलिस ने दो सितंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया। याची ने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसके एकाउंट को हैक कर ऐसा किया गया है। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याची की ओर से जानबूझकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया कृत्य है। कोर्ट ने तथ्यों और रिकार्ड को देखते हुए राहत देने से इन्कार कर दिया।

विवाहेतर संबंध तलाक का आधार हो सकता है, बच्चे की कस्टडी का नहीं : हाई कोर्ट

- कोर्ट ने पूर्व विधायक के पुत्र की याचिका को किया खारिज
- नौ वर्षीय बालिका की कस्टडी उसकी डाक्टर मां को सौंपी

मुंबई, प्रेट्र : एक नौ वर्षीय बालिका की कस्टडी उसकी मां को सौंपते हुए बांबे हाई कोर्ट ने कहा है कि विवाहेतर संबंध तलाक का आधार हो सकता है, पर बच्चे की कस्टडी प्रदान करने का नहीं। जस्टिस राजेश पाटिल ने 12 अप्रैल को महिला पूर्व विधायक के पुत्र की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें परिवार अदालत के फरवरी, 2023 के फैसले को चुनौती दी गई थी। परिवार अदालत ने भी बालिका की कस्टडी मां को सौंपी थी।

इस मामले में युगल का विवाह 2010 में हुआ था और उनकी पुत्री 2015 में जन्मी थी। पेशे से डाक्टर महिला ने दावा किया था कि 2019 में उसे घर से निकाल दिया गया था। जबकि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पत्नी अपनी इच्छा से गई थी। याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह ने अदालत में दलील दी कि महिला के कई विवाहेतर संबंध हैं, लिहाजा बालिका की कस्टडी उसे सौंपना उचित नहीं होगा। अदालत ने कहा, 'एक अच्छी पत्नी नहीं होने का मतलब यह नहीं कि वह अच्छी मां नहीं है।' याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसकी बेटी अपनी मां के साथ खुश नहीं थी और उसके व्यवहार में परिवर्तन आए हैं। लिहाजा बेटी के हित में उसे उसके व उसके माता-पिता के साथ रहने की अनुमति दी जाए। जयसिंह ने अदालत से कहा, बालिका के स्कूल ने भी याचिकाकर्ता की मां को ई-मेल लिखे थे जिसमें उसके व्यवहार को लेकर चिंता जताई गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा, 'स्कूल प्रशासन के पास बालिका से जुड़े मुद्दे के बारे में उसकी राजनीतिज्ञ दादी को सूचित करने का कोई कारण नहीं था, जबकि बालिका के माता-पिता सुशिक्षित हैं और उसकी मां तो डाक्टर है।'

जस्टिस पाटिल ने कहा, बालिका नौ वर्ष की है जो युवावस्था से पहले की उम्र है और कस्टडी के ऐसे मामलों में अदालत को बच्चे हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। बालिका की देखभाल उसकी नानी कर रही थी। मां की कस्टडी में रहने के दौरान उसका अकादमिक रिकार्ड अच्छा था। अदालत ने याचिकाकर्ता को 21 अप्रैल तक बालिका की कस्टडी उसकी मां को सौंपने का आदेश दिया। बालिका जब पिता से मिलने आई थी तो पिता ने उसे वापस भेजने से मना कर दिया था। इस मामले में 2020 में महिला ने अपने पति व सास-ससुर के विरुद्ध पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी जिसमें उसने उत्पीड़न करने, हमला करने, डराने-धमकाने व बेटी को छीनने का आरोप लगाया था।

****

पंजाब की जेल में कैदियों में खूनी झड़प, दो की मौत

संगरूर के सिविल अस्पताल में घायल कैदी। (सौ. जागरण)

संगरूर के सिविल अस्पताल से घायल कैदी को पटियाला लेकर जाते हुए। (सौ. जागरण)

जागरण संवाददाता, संगरूर

पंजाब के संगरूर की जिला जेल में शुक्रवार देर शाम कैदियों और हवालातियों में खूनी झड़प हो गई। इस दौरान दो कैदियों की मौत हो गई, वहीं दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम कैदियों में रंजिश के चलते झड़प हो गई। इस दौरान मोहम्मद हरीश हर्ष, मोहम्मद शहबाज, धरमिंदर सिंह और गगनदीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जहां डाक्टरों ने मोहम्मद हरीश व धरमिंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद शहबाज व गगनदीप सिंह की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें पटियाला रेफर कर दिया गया। सिविल अस्पताल संगरूर के डा. कर्मदीप सिंह काहल ने बताया कि शाम साढ़े सात बजे के करीब जिला जेल से चार लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिनमें दो की पहले ही मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि सभी के शरीर पर तेजधार व नुकीली चीज से मारे जाने के कई निशान थे।

एपल ने चीन में एप स्टोर से वाट्सएप और थ्रेड्स को हटाया

हांगकांग, एपी : एपल ने मेटा के वाट्सएप और थ्रेड्स के साथ ही दो अन्य विदेशी एप को चीन में अपने एप स्टोर से हटा दिया है। इनमें टेलीग्राम व सिग्नल शामिल हैं। चीनी अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देने के बाद शुक्रवार को यह कदम उठाया गया है। एपल ने कहा कि हम उन देशों के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जहां काम करते हैं, भले ही हम असहमत हों। मेटा ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। इन्हें अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच हटाया गया है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर टिकटाक पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। चीनी प्रौद्योगिकी फर्म बाइटडांस के स्वामित्व वाले टिकटाक का उपयोग अमेरिका में लाखों लोगों द्वारा किया जाता है, जबकि वाट्सएप और थ्रेड्स जैसे एप आमतौर पर चीन में उपयोग नहीं किए जाते हैं। इसके बजाय चीनी कंपनी टेनसेंट के स्वामित्व वाला मैसेजिंग एप वीचैट सर्वोच्च स्थान पर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर सहित अन्य मेटा एप डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेंगे। हालांकि चीन में ग्रेट फायरवाल फिल्टर नेटवर्क के कारण ऐसे विदेशी एप का उपयोग अवरुद्ध है, जो गूगल और फेसबुक जैसी विदेशी वेबसाइटों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

भारत ने फिलीपींस को सौंपी ब्रह्मोस मिसाइल

देश के रक्षा निर्यात में बड़ा कदम, यह सौदा 37 करोड़ 50 लाख डालर का

मनीला, एएनआइ : भारत ने एक समझौते के चलते फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला सेट सौंप दिया है। भारतीय वायुसेना के सी-17 ग्लोबमास्टर विमान से क्रूज मिसाइलों को फिलीपींस पहुंचाया गया। देश के रक्षा निर्यात में ये एक बड़ा कदम है। भारत व फिलीपींस के बीच दो साल पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर समझौता हुआ था। यह रक्षा सौदा 37 करोड़ 50 लाख डालर का है। दक्षिण चीन सागर में चीन से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइलों को अपनी सीमाओं पर तैनात करेगा।

रक्षा अधिकारियों ने कहा, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात किया है। फिलीपींस तो भारत की 'एक्ट-ईस्ट' पालिसी के तहत भी अहम देश है। फिलीपींस को मिसाइलें निर्यात करना भारत के रक्षा निर्यात के रणनीतिक फैसले की अहम कड़ी है। फिलीपींस ऐसे समय में मिसाइल की डिलीवरी ले रहा है, जब दक्षिण चीन सागर में लगातार झड़पों की वजह से उनके और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए फिलीपींस ने यह मिसाइल भारत से खरीदी है। ब्रह्मोस मिसाइल की तीन बैटरियों, छह लांचर व मिसाइलों को क्षेत्र में किसी भी खतरे से निपटने के लिए फिलीपींस तटीय क्षेत्रों में तैनात करेगा। फिलीपींस ने इन मिसाइलों के लिए भारत का आभार जताया है ।

- सी-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट विमान से सुपरसोनिक मिसाइलें फिलीपींस पहुंचाई

भारत ने शुक्रवार को फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें सौंपी। दोनों देशों ने 2022 में इस संबंध में समझौता किया था। एएनआइ >>

ब्रह्मोस मिसाइल भारत का ब्रह्मास्त्र

ब्रह्मोस को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसे रूस के सहयोग से बनाया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डीआरडीआरओ और रूस के एनपीओ मशिनोस्ट्रोयेनिया का संयुक्त उपक्रम है, जिसे दुनिया के सबसे सफल मिसाइल कार्यक्रमों में से एक कहा जाता है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल न सिर्फ फिलीपींस बल्कि अर्जेंटीना जैसे मुल्कों ने भी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से तीन गुना ज्यादा तेजी के साथ लक्ष्य को भेद सकती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है।

भारतीय मूल के प्रोफेसर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित

ह्यूस्टन, थ्रेट्र: ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को जापान की इंजीनियरिंग अकादमी के अंतरराष्ट्रीय फेलो के रूप में चुना गया है। मूल रूप से कर्नाटक के निवासी कौशिक को पावर कन्वर्जन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन में योगदान के लिए चुना गया है।

प्रोफेसर कौशिक राजशेखर(फाइल)। एक्स@.यूएचइंजीनियरिंग

अकादमी ने कहा, अंतरराष्ट्रीय फेलो के रूप में कौशिक का चयन विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान और वैज्ञानिक-तकनीकी क्षेत्र में उनके योगदान का सम्मान करता है जो संपूर्ण मानव जाति के हित में ऊर्जा स्रोतों के लिए अधिक दक्षता और पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देती है। प्रो. कौशिक ने कहा कि जापान की इंजीनियरिंग अकादमी के अंतरराष्ट्रीय फेलो के रूप में चुने जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह ऐसी उपलब्धि है, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं। कौशिक को 2022 में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा के क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया था।

सुरक्षा परिषद में सुधार पर भारत के रुख का अमेरिका ने किया समर्थन

वाशिंगटन, थ्रेट्र: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हुए अमेरिका ने कहा है कि 70 साल पहले की यूएनएससी आज की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। अमेरिका की शीर्ष राजनयिक ने जी-4 देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा की शीर्ष संस्था में शामिल करने की फिर हिमायत की है।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थामस-ग्रीनफील्ड ने जापान की यात्रा के दौरान टोक्यो में अपने भाषण में कहा, यूएनएससी में केवल रूस और चीन ही दो देश हैं जो 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के विस्तार का विरोध करते हैं। पूर्व में चीन और रूस के साथ अमेरिका एक बात पर सहमत थे कि वे सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं चाहते, पर 2021 में अमेरिका इससे अलग हो गया। उसने कहा,वह यूएनएससी का विस्तार कर इसमें सुधार चाहता है। इस समय परिषद में 193 सदस्य हैं, लेकिन इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका व अन्य कई क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए हम जी-4 के सदस्यों- जापान, जर्मनी, भारत व ब्राजील के साथ चर्चा में उनके सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी पिछले वर्ष फिर से सुरक्षा परिषद में इन देशों के लिए स्थायी सदस्यता का समर्थन

- शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा, 70 वर्ष पहले की परिषद आज की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती
- यूएनएससी में जी-4 देशों-भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थामस-ग्रीनफील्ड। रायटर

किया था। लिंडा ने कहा, मैं जानती हूं कि यह बहुत मुश्किल है, इसे सितंबर तक पूरा नहीं किया जा सकता। हमें इस पर बहुत काम करना है। भारत ने गत माह जी-4 देशों की ओर से परिषद में विस्तार का माडल पेश किया था। जिसमें छह नए स्थायी और चार-पांच अस्थायी सदस्यों को शामिल कर परिषद के विस्तार की बात है। भारत कह चुका है कि वर्तमान परिषद 21वीं सदी की वास्तविक भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती।

पाकिस्तान में अब पांच जापानी नागरिकों पर आतंकी हमला

पाकिस्तान के कराची शहर में शुक्रवार को आत्मघाती हमले से क्षतिग्रस्त वैन। घटनास्थल पर जांच करते पुलिसकर्मी। एपी

करांची, थ्रेट्र: पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के बाद अब जापानी नागरिकों पर आतंकी हमला हुआ है। सिंध प्रांत के बंदरगाह शहर कराची में शुक्रवार को सुजुकी मोटर में काम करने वाले पांच जापानी नागरिकों को एक आत्मघाती हमलावर और एक बंदूकधारी द्वारा निशाना बनाया गया। लेकिन वे बाल-बाल बच गए। वहीं, दोनों हमलावर मार गिराए गए हैं। इस दौरान एक सुरक्षा गार्ड की भी जान चली गई, जबकि दो राहगीर घायल हैं। अभी तक इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआइजी) ईस्ट, अजफर महेसर ने बताया कि पांच जापानी नागरिक दो सुरक्षा गार्डों के साथ अपने आवास जमजमा क्लिफ्टन से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जाने के लिए वैन से निकले थे। आतंकी लांधी में मुर्तजा चोरंगी के पास सड़क पर पहले से जापानी नागरिकों के वैन का इंतजार कर रहे थे। हमलावरों ने उनके वैन को निशाना बनाने की कोशिश की। एक ने वैन के पास जाकर खुद को उड़ा लिया लेकिन सफलता न मिलने से दूसरा हमलावर घबरा गया और उसने फायरिंग शुरू कर दीं। इसके बाद सुरक्षा गार्डों ने दूसरे आतंकी को मार गिराया। इस दौरान एक सुरक्षा गार्ड व दो राहगीर घायल हो गए। डीआइजी ने बताया कि हमला शुक्रवार सुबह किया गया। घटना में तीनों घायलों को गंभीर अवस्था में जिन्ना हास्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां एक 45 वर्षीय सुरक्षा गार्ड ने दम तोड़ दिया।

उधर, क्योदो समाचार एजेंसी ने बताया कि टोक्यो में जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने कहा कि इस घटना में कई जापानी शामिल थे और उनमें से एक घायल हो गया, लेकिन पाकिस्तानी पक्ष ने इस जानकारी की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने उत्तरपश्चिमी प्रांत में आतंकी हमले में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) में काम करने वाले पांच चीनी नागरिकों व उनके पाकिस्तानी ड्राइवर को आत्मघाती हमले में मार गिराया था। इस पर चीनी कंपनियों ने जल विद्युत परियोजनाओं को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया था।

- बाल-बाल बचे, दोनों हमलावर मारे गए, एक सुरक्षा गार्ड की भी मौत
- दो घायलों का चल रहा इलाज, हमले की किसी ने नहीं ली है जिम्मेदारी

पांच सीमा शुल्क खुफिया अधिकारियों की हमले में मौत

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान शहर में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पांच सीमा शुल्क खुफिया अधिकारियों और एक पांच वर्षीय लड़की सहित दो नागरिकों की दुखद मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार को हुई जब सीमा शुल्क खुफिया टीम डेरा इस्माइल खान जिले के सग्गू में नियमित जांच कर रही थी, जहां उन्हें पास की झाड़ियों में छिपे हमलावरों से भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा।

स्काटलैंड में टूरिस्ट स्थल के पास दो भारतीय छात्रों के शव मिले

लंदन, थ्रेट्र : स्काटलैंड में प्रमुख टूरिस्ट स्थल के पास दो भारतीय छात्रों के शव बरामद हुए। दोनों छात्र आंध्रप्रदेश के बताए जा रहे हैं। वह यूनिवर्सिटी आफ डंडी में पढ़ाई कर रहे थे। यह घटना बुधवार को पर्थशायर में ब्लेयर आफ एटाल के पास लिन आफ टुमेल में हुई जब दोस्तों के एक समूह के दो लोग वाटरफाल के पानी में डूब गए। दोस्तों द्वारा आपातकालीन सेवा को इसकी जानकारी दी गई। स्काटिश फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने बचाव प्रयासों में सहायता टीमों को भेजा।

स्काटलैंड पुलिस ने कहा, बुधवार शाम सात बजे के आसपास ब्लेयर आफ एटाल के पास 22 व 26 साल के दो युवकों के पानी में गिरने की सूचना मिली थी। आपातकालीन सेवाओं ने जांच अभियान चलाया। इस दौरान दो शव बरामद किए गए। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने कहा, डूबने वाले छात्र आंध्र प्रदेश के थे। भारत का महावाणिज्य दूतावास उनके परिवार के संपर्क में है। एक अधिकारी ने छात्र के ब्रिटेन स्थित रिश्तेदार से भी भेंट की है।

संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करेंगे : ईरान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने कहा, शांति को बढ़ावा देंगे
- इजरायल पर हमले को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया

इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने कहा है कि ईरान की सरकार संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करेगी और वह अपने क्षेत्र में शांति व स्थिरता को बढ़ाने के लिए रचनात्मक कदम उठाने से नहीं हिचकेगी। यह बयान ईरान के दूतावास ने 18 अप्रैल को तैयार किया था, पर इसे 19 अप्रैल (शुक्रवार) को जारी किया गया है। 19 अप्रैल को सुबह में इजरायल की तरफ से ईरान के कुछ शहरों पर राकेट हमले किए गए। इजरायल ने यह हमला पिछले रविवार को उसके कुछ शहरों पर ईरान की तरफ से किए गए अप्रत्याशित हमले के बाद किया है। ईरान ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र का एक जिम्मेदार सदस्य है और इसके नियमों के पालन करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस बयान में इजरायल की सरकार की खूब निंदा की गई है और उसे अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ने वाला और सीरिया स्थित ईरान के कंसुलेट पर आतंकी हमला करने वाला बताया गया है। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने 14 अप्रैल को जो हमला किया, वह आत्मरक्षा में किया गया हमला था। ईरान ने यह भी आरोप लगाया है कि इजरायल ने वियना समझौते का उल्लंघन किया है और उसके पास अपनी रक्षा के लिए हमला करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। इन सब आरोपों के बावजूद इस विस्तृत बयान से यह भी संदेश दिया गया है कि ईरान अब इस मामले को ज्यादा बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।

ईरान

तेल अवीव के लिए एअर इंडिया की उड़ानें रद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात को देखते हुए एअर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानों को 30 अप्रैल तक के लिए रद कर दिया है। इस अवधि के दौरान जिन यात्रियों के आरक्षित टिकट हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है और आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने और किसी दूसरी तिथि को टिकट बुक करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

खाड़ी क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारत आने वाली दर्जनों उड़ानों को अब रास्ता बदलना पड़ रहा है, क्योंकि वह ईरान और इजरायल के हवाई मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर रहीं। इस मार्ग से दुबई जाने वाली तकरीबन 1,500 उड़ानों के भी रद होने की सूचना है। फ्लाईदुबई, टर्किश एयर, एमिरैट्स समेत कई एयरलाइनों ने कहा है कि वह स्थिति का जायजा ले रही हैं और इसके बाद ही आगे का फैसला करेंगी।

पेरिस में ईरानी दूतावास में एक शख्स ने खुद को उड़ाने की दी धमकी

पेरिस, एपी : पेरिस में ईरानी वाणिज्य दूतावास में खुद को उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने ईरानी वाणिज्य दूतावास में एक संदिग्ध व्यक्ति के संभवतः ग्रेनेड और विस्फोटक जैकेट ले जाने की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया। पुलिस ने अब तक हथियार मिलने की पुष्टि नहीं की है। अधिकारी हिरासत में लिए गए शख्स की पहचान की कोशिश कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध को शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे देखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पूरे वाणिज्य दूतावास को सुरक्षा घेर में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए शख्स के इरादे अबतक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अधिकारी ने कहा कि किसी विस्फोट की सूचना नहीं मिली है। फ्रांसीसी टेलीविजन और इंटरनेट मीडिया पर मौजूद तस्वीरों में पुलिस को इमारत के आसपास देखा जा सकता है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है।

यूएई की गैरजरूरी यात्रा करने से बचें भारतीय

दुबई, थ्रेट्र: भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की गैरजरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। दूतावास ने इस सप्ताह हुई भारी वर्षा के बाद परिचालन सामान्य होने तक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले भारतीयों को गैरजरूरी यात्रा को पुनर्निर्धारित करने का परामर्श जारी किया है। यूएई में इस सप्ताह भारी वर्षा हुई थी। यह खाड़ी देश इससे उबरने की कोशिश कर रहा है। मूसलधार वर्षा के चलते दुबई और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई थी। यहां हालात अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। यूएई में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है।

दूतावास ने कहा कि यूएई के अधिकारी स्थिति को सामान्य करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने सलाह दी है कि यात्री उड़ानों की प्रस्थान तिथि और समय के संबंध में संबंधित एयरलाइन से पुष्ट सूचना मिलने के बाद ही हवाईअड्डा से यात्रा कर सकते हैं। परामर्श में कहा गया कि यूएई में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या को अस्थायी रूप से सीमित कर दिया गया है। दूतावास ने परामर्श में कहा, 'दुबई एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों को परिचालन सामान्य होने तक गैरजरूरी यात्रा को पुनर्निर्धारित करने की सलाह दी जाती है। भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने 17 अप्रैल से आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है।'

दुनिया के सबसे व्यस्त हवाईअड्डों में शामिल दुबई एयरपोर्ट से अभी तक उड़ानें सामान्य नहीं हो पाई हैं। यहां आने वाली उड़ानों की संख्या सीमित की गई हैं। दुबई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे तब तक यहां न आएं, जब तक कि उनकी उड़ान की पुष्टि न हो जाए। साथ ही निर्धारित प्रस्थान समय से केवल दो घंटे पहले ही यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस बीच समीप के अबू धाबी एयरपोर्ट से उड़ानों का परिचालन सामान्य हो गया है। यह एयरपोर्ट भी जलमग्न हो गया था।

- यूएई स्थित भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

मूसलधार वर्षा के चलते दुबई में आई बाढ़ से शुक्रवार को भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। एक सड़क पर भरे पानी में डूबे वाहन। एएफपी

- भारी बारिश से मरने वालों की संख्या चार हो गई है

एअर इंडिया ने रद कीं उड़ानें

नई दिल्ली, थ्रेट्र: एअर इंडिया ने दुबई के लिए रविवार तक अपनी उड़ानें रद कर दी हैं। एयरलाइंस ने कहा,जिन ग्राहकों ने 21 अप्रैल तक यात्रा के लिए उड़ानें बुक की हैं, उन्हें पुनर्निर्धारण पर छूट और टिकट रद कराने पर पूर्ण रिफंड दिया जाएगा। साथ ही स्पाइसजेट और इंडिगो की भी सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

योग के माध्यम से संदेश

फलस्तीन के इस्लामिक संगठन हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के समर्थन में लोगों ने तेल अवीव में योग किया और इसके माध्यम से संदेश दिया कि एकाग्रता और शांति चित्त रहकर समस्याओं का समाधान निकाला जाए। रायटर

पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरने में मदद करेगा आइएमएफ

वाशिंगटन, थ्रेट्र: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की सहायता करने के लिए तैयार है। आइएमएफ के समर्थन से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और स्थिरता आएगी। आइएमएफ की बैठकों में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब इस समय वाशिंगटन में हैं। आइएमएफ में पश्चिम एशिया व मध्य एशिया विभाग के निदेशक जिहाद अजौर ने आइएमएफ और विश्व बैंक की बैठक से इतर संवाददाताओं से कहा कि कुछ प्रमुख चुनौतियों से निपटने में सहायता के लिए पाकिस्तान ने एक नए कार्यक्रम में रुचि दिखाई है। मौजूदा कार्यक्रम 10 महीने पहले शुरू किया गया था। दूसरी ओर विश्व बैंक ने पाकिस्तान सरकार से आर्थिक एवं सामाजिक सुधार के लिए कर सुधार और शुल्क एवं बिक्री कर पर छूट समाप्त करने को कहा है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान सरकार से बाल विकास के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने के साथ ही ऊर्जा एवं अन्य चीजों पर रियायत कम करने का सुझाव दिया है।

यूक्रेन का रूसी रणनीतिक बमवर्षक को मार गिराने का दावा

- रूस ने कहा, तकनीकी खराबी से दुर्घटनाग्रस्त हुआ लड़ाकू विमान
- यूक्रेन के निप्रो क्षेत्र के शहरों पर रूसी हमले में आठ लोगों की मौत

कीव, एपी: यूक्रेन की वायुसेना ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने एक रूसी रणनीतिक बमवर्षक को मार गिराया है। लेकिन रूस के अफसरों ने कहा, विमान एक लड़ाकू मिशन के दौरान तकनीकी खराबी के कारण कम आबादी वाले इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे पहले रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के मध्य निप्रो क्षेत्र के शहरों पर हमला किया, जिसमें आठ वर्षीय लड़की सहित आठ लोगों की मौत हो गई और 25 घायल हो गए।

दो वर्ष से अधिक समय के युद्ध के दौरान रूसी युद्धक विमानों को मार गिराने के यूक्रेन के पिछले दावों पर मास्को ने अक्सर चुप्पी साधी है या खंडन किया है। इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिम से हथियारों की मांग फिर दोहराई है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि मिसाइल और ड्रोन हमलों को विफल किया जा सकता है। यह पश्चिम एशिया के आसमान में प्रदर्शित किया जा चुका है। रूसी वायु सेना यूक्रेन के मुकाबले अधिक शक्तिशाली है पर पश्चिमी सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराई गई परिष्कृत मिसाइल सिस्टम रूस के लिए खतरा है, क्योंकि क्रेमलिन की सेनाएं धीरे-धीरे 1,000 किलोमीटर की अग्रिम पंक्ति के साथ आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें गर्मियों में एक बड़े रूसी हमले की आशंका है।

यूक्रेन ने कहा कि वायुसेना और सैन्य खुफिया ने विमान भेदी मिसाइलों से टीयू-22एम3 बमवर्षक को गिराने में सहयोग किया। रूस आमतौर पर अपने हवाई क्षेत्र के अंदर से यूक्रेनी लक्ष्यों पर केएच-22 क्रूज मिसाइलें दागने के लिए बमवर्षक का उपयोग करता है। यह विमान परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। वहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दरअसल उसका एक युद्धक विमान स्टावरोपोल क्षेत्र के क्रास्नोग्वार्डेस्की जिले में कम आबादी वाले स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रीजनल गवर्नर व्लादिमीर व्लादिमिरोव ने कहा कि इस दौरान एक क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि दूसरे क्रू मेंबर की तलाश की जा रही है।

रूसी विमान टीयू-22एम3 बमवर्षक का मलवा। एएफपी

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच शुक्रवार को रूसी सेना ने यूक्रेन के दनिप्रो में तावड़तोड़ हवाई हमले किए और मिसाइलें दागीं। जिससे कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक इमारतों में आग लगी गई। आग पर काबू करते यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस के फायर फाइटर। एएफपी

दुष्प्रचार को गति देने के लिए चीन ने गठित की इन्फार्मेशन फोर्स

बीजिंग, थ्रेट्र : चीन में राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने शुक्रवार को इन्फार्मेशन सपोर्ट फोर्स (आइएसएफ) के गठन की घोषणा की। यह फोर्स चीन की सेना- पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की एक शाखा होगी। चिनफिंग ने कहा है कि यह फोर्स पीएलए की रणनीतिक शाखा होगी और यह विश्व की सबसे बड़ी सेना के एक स्तम्भ की तरह कार्य करेगी। जाहिर है कि इस फोर्स के जरिये चीन विश्व में अपने दुष्प्रचार अभियान को तेज करेगा और यह फोर्स उसके प्रचार युद्ध में मुख्य भूमिका अदा करेगी।

राष्ट्रपति चिनफिंग के पास चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख का पद भी है। इसके चलते वह चीनी सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। इस नई फोर्स का गठन सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के एक निर्णय के तहत हुआ है। पार्टी के महासचिव का पद भी चिनफिंग के पास है। इस लिहाज से चीन की सत्ता के तीनों सर्वोच्च पद चिनफिंग के पास हैं। आइएसएफ के जरिये चीनी सेना अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माहौल तैयार करेगी और इसके बाद जरूरत के अनुसार कार्रवाई करेगी। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह नई फोर्स स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स (एसएसएफ) के नए संस्करण के रूप में कार्य करेगी। पीएलए की शाखा के रूप में एसएसएफ को 2015 में गठित किया गया था। चिनफिंग ने आइएसएफ के गठन की घोषणा करते हुए उसके प्रतीक वाला ध्वज फोर्स के कमांडर को सौंपा।

इस मौके पर चिनफिंग ने उम्मीद जाहिर की कि आइएसएफ पीएलए की शाखा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को उत्कृष्ट तरीके से निभाएगी। विदित हो कि चीन में पीएलए सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर कार्य करती है और पार्टी द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करती है। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठावान रहने के लिए सैनिक शपथ भी लेते हैं।

- चिनफिंग ने कहा, यह रणनीतिक बल के रूप में कार्य करेगी
- इस फोर्स के जरिये चीन विश्व में दुष्प्रचार अभियान को तेज करेगा

****

पर्पल कैप

गेंदबाज	टीम	विकेट
बुमराह	मुंबई	13
चहल	राजस्थान	12
कोएत्जे	मुंबई	12

आरेंज कैप

बल्लेबाज	टीम	रन
विराट कोहली	आरसीबी	361
रियान पराग	राजस्थान	318
रोहित शर्मा	मुंबई	297

सुपरकिंग्स पर भारी डिकाक-राहुल

लखनऊ सुपरजायंट्स ने सीएसके को आठ विकेट से रौंदा, केएल-क्विंटन ने जड़ा पचासा

पारी के दौरान डिकाक और राहुल • प्रेट्र

विकास मिश्र • जागरण

लखनऊ: आइपीएल के 34वें मुकाबले में शुक्रवार को केएल राहुल (83) और क्विंटन डिकाक (54) की 134 रनों की मजबूत साझेदारी के दम पर लखनऊ सुपरजायंट्स लगातार दो हार के बाद जीत की पटरी पर लौटा। एलएसजी ने सीएसके के 177 रनों के लक्ष्य को 19 ओवर में केवल दो विकेट गंवाकर प्राप्त कर लिया। केएल राहुल ने इसी के साथ सत्र का दूसरा और विकेटकीपर के रूप में आइपीएल में 25वां अर्धशतक जड़ा। इस मामले में वह महेंद्र सिंह धौनी से भी आगे निकल गए, जिन्होंने 24 अर्धशतक लगाए हैं।

राहुल और डिकाक की रिकार्ड साझेदारी: चेन्नई के 177 रनों की चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरे लखनऊ सुपर जायंट्स को केएल राहुल और क्विंटन डिकाक ने न केवल शानदार शुरुआत दिलाई, बल्कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर टीम की जीत की नींव रख दी। खासकर, कप्तान राहुल बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने 31 गेंदों पर पांच चौके व तीन छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। लखनऊ ने 5.4 ओवर में 50 रन और 10.5 ओवर में 100 रन का आंकड़ा छू लिया था। इसी बीच, डिकाक ने 41 गेंदों पर अपना पचासा भी पूरा किया। डिकाक के आउट होने के बाद केएल राहुल ने पथिराना की गेंद पर तेजतर्रार शाट लगाया, जिस पर जडेजा ने हवा में डाइव लगाकर अविश्वसनीय कैच बना लिया।

जडेजा की सधी बल्लेबाजी, माही ने जमाया रंग: एक समय 90 रन पर पांच व विकेट गंवाने वाली चेन्नई के लिए 150 का भी स्कोर पहाड़ लग रहा था, लेकिन रविंद्र जडेजा और मोइन (30) ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 51 रनों की साझेदारी कर स्कोर 141 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद आए महेंद्र सिंह धौनी ने अपनी बल्लेबाजी से प्रशंसकों का खूब उत्साहवर्धन किया। उन्होंने केवल नौ गेंदों पर तीन चौके व दो शानदार छक्के की मदद से नाबाद 28 रनों की पारी खेलकर सीएसके को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।

बाहर के मैदानों पर सीएसके के गेंदबाज बेअसर : गत चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए इस सत्र में विपक्षी टीमों की प्रारंभिक जोड़ी को तोड़ना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। घर पर फिर भी टीम इसे करने में सफल रही हो, परंतु बाहर आकर सीएसके के गेंदबाज बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं। शुक्रवार को इकाना स्टेडियम में भी लखनऊ के विरुद्ध टीम को 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर 134 रन पर पहली सफलता मिली। इससे पहले, विशाखापत्तनम में दिल्ली के विरुद्ध 93 रन, मुंबई के विरुद्ध 70 रन और हैदराबाद के विरुद्ध 46 रन पर पहली सफलता मिली थी। चेन्नई में पहले मैच में आरसीबी के विरुद्ध 41 रन पर टीम को पहली सफलता मिली थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात को 28 रन पर पहला झटका दिया था, जबकि कोलकाता के विरुद्ध शून्य पर सफलता मिल गई थी। सीएसके के गेंदबाजों ने पहले विकेट लेने से पूर्व इस सत्र में 58.85 की औसत से कुल सात मैचों में 412 रन दिए हैं। यहां तक कि आरसीबी का रिकार्ड भी इस सत्र में सीएसके से बेहतर है।

इकाना में धौनी का जादू

वर्तमान सत्र में लखनऊ में इसके पहले तीन मैच हो चुके हैं। तीनों में स्टेडियम लगभग 90 प्रतिशत भर गया था, लेकिन प्रशंसकों को एलएसजी-सीएसके मैच का बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि पहले से अंदेशा था कि इस बार भी इकाना स्टेडियम पर धौनी का जादू हावी रहेगा। आठ बजे तक 50 हजार कुर्सियां खचाखच भर गईं। खास बात यह है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 90 प्रतिशत दर्शक धौनी का उत्साहवर्धन करने पहुंचे। स्टेडियम परिसर के बाहर भी पीली जर्सी की खुमारी छाई रही।

स्कोर बोर्ड

चेन्नई सुपरकिंग्स : 176/6 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
अजिंक्य रहाणे बो. क्रुणाल	36	24	5/1
रचिन रवींद्र बो. मोहसिन	00	01	0/0
रुतुराज का. राहुल बो. यश	17	13	1/0
रवींद्र जडेजा अविजित	57	40	5/1
शिवम का. राहुल बो. स्टोइनिस	03	08	0/0
समीर स्टं. राहुल बो. क्रुणाल	01	05	0/0
मोइन का. बडोनी बो. बिश्नोई	30	20	0/3
महेंद्र सिंह धौनी अविजित	28	09	3/2

अतिरिक्त : 4 (लेबा-1, वा-3)
कुल : 20 ओवर में छह विकेट पर 176 रन
विकेटपतन : 1-4 (रचिन, 1.1), 2-33 (रुतुराज, 4.2), 3-68 (रहाणे, 8.1), 4-87 (दुबे, 11.1), 5-90 (रिजवी, 12.2), 6-141 (मोइन, 17.5)
गेंदबाजी : मैट हेनरी 3-0-26-0, मोहसिन खान 4-0-37-1, यश ठाकुर 4-0-45-1, क्रुणाल पांड्या 3-0-16-2, रवि बिश्नोई 4-0-44-1, मार्कस स्टोइनिस 2-0-7-1

लखनऊ : 180/2 (19 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
डिकाक का. धौनी बो. मुस्तफिजुर	54	43	5/1
राहुल का. जडेजा बो. पथिराना	82	53	9/3
निकोलस पूरन अविजित	23	12	3/1
मार्कस स्टोइनिस अविजित	08	07	1/0

अतिरिक्त : 13 (लेबा-3, वा-9, नोबा-1)
कुल : 19 ओवर में दो विकेट पर 180 रन
विकेटपतन : 1-134 (डिकाक, 14.6), 2-161 (राहुल, 17.1)
गेंदबाजी : दीपक चाहर 3-0-26-0, तुषार देशपांडे 4-0-42-0, मुस्तफिजुर 4-0-43-1, रवींद्र जडेजा 3-0-32-0, मथीशा पथिराना 4-0-29-1, मोइन अली 1-0-5-0

लखनऊ में लक्ष्य का सफल पीछा

177	लखनऊ सुपरजायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स	2024
168	दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपरजायंट्स	2024
160	पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपरजायंट्स	2023
122	लखनऊ सुपरजायंट्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद	2023

विकेटकीपर के सर्वाधिक 50 से अधिक रन

25	केएल राहुल
24	एमएस धौनी
23	क्विंटन डिकाक
21	दिनेश कार्तिक
18	रोबिन उथप्पा

लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए सर्वाधिक साझेदारी

रन	खिलाड़ी	विरुद्ध	स्थान	वर्ष
210*	राहुल और डिकाक	केकेआर	मुंबई	2022
134	राहुल और डिकाक	सीएसके	लखनऊ	2024
99	राहुल और डिकाक	सीएसके	मुंबई	2022
96	राहुल और हुड्डा	आरसीबी	कोलकाता	2022
95	राहुल और हुड्डा	दिल्ली	मुंबई	2022

आज सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम

घर वापसी कर रहे पंत पर होंगी नजरें

अभिषेक त्रिपाठी • जागरण

अभ्यास के दौरान पंत • एएनआइ

नई दिल्ली : दिल्ली कैपिटल्स की टीम शनिवार को जब अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम पर उतरेगी तो सभी की नजरें रिषभ पंत पर होंगी। पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के रूप में इस मैदान पर उतरेंगे तो यह उनके लिए एक भावुक पल होगा। पिछले वर्ष पंत यहां बैसाखियों के सहारे आए थे और उन्होंने दर्शक दीर्घा से मैच देखा था। अब वह पूरी तरह फिट हैं और पहली बार दिल्ली के घरेलू मैदान पर टीम की कप्तानी करेंगे।

अरुण जेटली स्टेडियम में कैपिटल्स की टीम ने 2019 के सत्र में अंतिम बार मैच खेला था, लेकिन तब टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथ में थी। अय्यर के चोटिल होने के बाद पंत को 2020 में कप्तान बनाया गया था और कोविड-19 के कारण उस वर्ष आइपीएल का आयोजन यूएई में किया गया था। 2021 में आधा सत्र यूएई और बाकी भारत में खेला गया था, लेकिन तब दिल्ली में मैच नहीं हुए थे। 2022 में दिल्ली में मैच हुए, लेकिन घरेलू टीम का कोई भी मैच यहां नहीं था। 2023 सत्र में पंत कार हादसे में घायल हो गए थे और वह पूरा सत्र नहीं खेल पाए थे। अब उनकी कप्तानी में दिल्ली की टीम को बेहतरीन लय में दिख रही सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध हर विभाग में बेहतर खेल दिखाना होगा। दिल्ली ने अब तक मिला जुला प्रदर्शन किया है, हालांकि पिछले दो मुकाबलों में लखनऊ सुपरजायंट्स और गुजरात टाइटंस को हराकर टीम प्लेआफ की दौड़ में बनी हुई है।

सनराइजर्स की टीम दो बार टूर्नामेंट के इतिहास का सर्वोच्च स्कोर 277 और 287 का स्कोर बना चुकी है। ऐसे में कप्तान पंत को अरुण जेटली स्टेडियम की घरेलू पिच पर अपने संसाधनों का चतुराई से इस्तेमाल करना होगा। सनराइजर्स के ट्रेविस हेड 39 मैच में शतक जड़ने का कारनामा कर चुके हैं। वहीं अभिषेक शर्मा ने भी 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं। दोनों पावरप्ले में आक्रामक प्रदर्शन करने को आतुर होंगे। दोनों का स्ट्राइक रेट 199 और 197 रहा है जो इशांत शर्मा, खलील अहमद और मुकेश कुमार की तेज गेंदबाजी तिकड़ी के लिए कड़ी चुनौती होगा। वहीं हेनरिक क्लासेन का भी स्ट्राइक रेट 199 के करीब रहा है और वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर्स में से एक हैं। ये तीनों मिलकर सनराइजर्स की बल्लेबाजी को खतरनाक बनाते हैं।

कुलदीप यादव के रूप में दिल्ली के पास ट्रंपकार्ड है जिनका इकोनामी रेट छह के करीब है। स्पिन गेंदबाजी में उनका साथ देने के लिये अक्षर पटेल के अलावा तीसरा विकल्प ट्रिस्टन स्टब्स हैं।

पंत अगर टास जीतते हैं तो बल्लेबाजी चुन सकते हैं। वैसे डेविड वार्नर की चोट उनके लिए चिंता का विषय है हालांकि पहले दो मैचों में जैक फ्रेजर मैक्गर्क ने प्रभावित किया है।

अंक तालिका		मैच	जीत	हार	टाई	नेट रन रेट	अंक
1	राजस्थान	7	6	1	0	+0.677	12
2	केकेआर	6	4	2	0	+1.399	8
3	सीएसके	7	4	3	0	+0.529	8
4	हैदराबाद	6	4	2	0	+0.502	8
5	लखनऊ	7	4	3	0	+0.123	8
6	दिल्ली	7	3	4	0	-0.074	6
7	मुंबई	7	3	4	0	-0.133	6
8	गुजरात	7	3	4	0	-1.303	6
9	पंजाब	7	2	5	0	-0.251	4
10	आरसीबी	7	1	6	0	-1.185	2

एक नजर में

एंडी मरे ने चोट से उबरकर टेनिस कोर्ट पर वापसी की

लंदन : तीन बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन एंडी मरे टखने की चोट में सर्जरी न होने की पुष्टि के बाद अभ्यास के लिए टेनिस कोर्ट में लौट आए। 36 वर्षीय मरे के बाएं टखने में पिछले महीने मियामी ओपन के एक मैच के दौरान चोट लग गई थी। मरे की टीम ने बताया कि उनकी टखने की चोट की सर्जरी नहीं होगी और जल्द ही कोर्ट पर फिर से खेलते नजर आएंगे।" शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो में पूर्व विश्व नंबर एक को इनडोर कोर्ट पर अभ्यास करते हुए देखा गया, लेकिन वापसी कब होगी पुष्टि नहीं की गई है। (एपी)

इमाद वसीम को बाहर किए जाने पर उठे सवाल

रावलपिंडी : पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज आलराउंडर इमाद वसीम को न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहले टी20 मैच के लिए टीम से बाहर किए जाने पर पूर्व खिलाड़ियों ने सवाल उठाए हैं। वसीम और तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर इस वर्ष जून में टी20 विश्व कप से पहले संन्यास से वापस आ गए, लेकिन इमाद को गुरुवार को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली। लगातार वर्षा के कारण यहां पहले टी20 मैच में दो गेंदें ही फेंकी जा सकीं और मैच को रद कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात के आफ स्पिनर उस्मान खान, मध्यक्रम के बल्लेबाज और तेज गेंदबाज इरफान खान और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को पदार्पण का मौका दिया। (प्रेट्र)

नई प्रतियोगिताओं की ईएफआइ ने घोषणा की

नई दिल्ली : भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआइ) ने अगले वर्ष होने वाली एशियाई महाद्वीपीय चैंपियनशिप के लिए बेहतरीन राइडर्स और मजबूत टीम तैयार करने के मकसद के साथ शुक्रवार को 2024-25 सत्र के लिए 41 प्रतियोगिताओं के व्यापक कैलेंडर को जारी किया। भारत पहली बार एशियाई घुड़सवारी महासंघ (एईएफ) से स्वीकृत अंडर-21 क्षेत्रीय ग्रुप तीन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा, जिसमें शो जंपिंग और ड्रेसेज प्रतियोगिताएं होंगी। भारत पहली बार पैरा-ड्रेसेज स्पर्धाओं का भी आयोजन करेगा। इन स्पर्धाओं में प्रदर्शन के आधार पर अगले वर्ष दिसंबर में थाईलैंड के पटाया में होने वाली एशियाई महाद्वीपीय चैंपियनशिप की टीम का चयन होगा। (प्रेट्र)

बुमराह को स्वीप शाट लगाना मेरा सपना था : आशुतोष

आइपीएल डायरी

आशुतोष • फाइल फोटो

मुल्लांपुर, प्रेट्र : पंजाब किंग्स के आक्रामक बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने कहा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को स्वीप शाट खेलना हमेशा से उनका सपना था जो मुंबई इंडियंस के विरुद्ध आइपीएल मैच में पूरा हुआ।

आशुतोष ने कहा, 'बुमराह को स्वीप शाट लगाना मेरा सपना था। मैं उस शाट का अभ्यास कर रहा था और विश्व के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज के सामने वह शाट खेला। मुझे भरोसा था कि मैं टीम को मैच जिता सकूंगा।' उन्होंने अपने बेहतर प्रदर्शन कर श्रेय पंजाब किंग्स के क्रिकेट विकास प्रमुख और भारत के पूर्व खिलाड़ी संजय बांगड़ को दिया। उन्होंने कहा, 'संजय सर ने मुझे कहा कि मैं स्लागर नहीं हूं और विशुद्ध क्रिकेट शाट खेल सकता हूं। यह छोटा या बयान था लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं इस पर अमल कर रहा हूं। मैंने अपने खेल में यही बदलाव किया। जीत और हार खेल का हिस्सा है। मायने यह रखता है कि एक टीम के रूप में आप कैसा खेल रहे हैं।

हार्दिक पर धीमी ओवर गति के लिए लगा जुर्माना

मुल्लांपुर : मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर धीमी ओवर गति के कारण 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आइपीएल की न्यूनतम ओवर गति से संबंधित आचार संहिता के तहत यह उनकी टीम का सत्र का पहला अपराध था, इसलिए पांड्या पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।'

विश्व कप के लिए दिल्ली में 27 या 28 को हो सकती है चयन समिति की बैठक

अभिषेक त्रिपाठी • जागरण

दिल्ली में होंगे रोहित, अगरकर भी स्पेन से सीधे पहुंचेंगे, टीम चुनने पर होगा मंथन

नई दिल्ली : टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के चयन के लिए दिल्ली में 27 या 28 अप्रैल को चयन समिति की बैठक हो सकती है। वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम भेजने की तिथि एक मई है।

सूत्रों के अनुसार, अरुण जेटली स्टेडियम में 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। इस दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दिल्ली में मौजूद रहेंगे। स्पेन में छुट्टियां बिता रहे मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर भी सीधे दिल्ली पहुंचेगें, जहां बाकी चयनकर्ता भी रहेंगे। दिल्ली में मैच के बाद मुंबई इंडियंस को लखनऊ में 30 अप्रैल को एलएसजी से मैच खेलना है। लिहाजा दिल्ली में होने वाले मुकाबले के दौरान बैठक के लिए समय सबसे उपयुक्त है क्योंकि एक मई को आइसीसी को टीम की सूची सौंपनी है। हालांकि ये पूरी संभावना है कि टी-20 विश्व कप के लिए चयन समिति इस प्रारूप में टीम के लिए खेल चुके खिलाड़ियों को वरीयता देगी। अगर कुल मिलाकर स्थिति देखी जाए तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, रिषभ पंत, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव का चयन निश्चित है। ये 10 खिलाड़ी अगर फिट हैं तो निश्चित रूप अमेरिका की उड़ान भरेंगे।

हार्दिक पांड्या का टीम में चयन काफी हद तक उनके आइपीएल में प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। हार्दिक ने अभी गेंदबाजी में प्रभावित नहीं किया और बल्ले से भी ज्यादा रन नहीं बना सके हैं। वहीं, शुभमन और यशस्वी जायसवाल के बीच में चयन की बात की जाए तो इनमें से गिल ने ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन जायसवाल की बात की जाए तो चयन समिति आइपीएल में उनके कुछ कम स्कोर को देखते हुए उनकी अनदेखी नहीं कर सकती। अगर चयनकर्ता इन दोनों को ही अवसर देते हैं तो शिवम दुबे या रिंकू सिंह में किसी एक को बाहर किया जा सकता है। विकेटकीपर में पंत के साथ संजू सैमसन का पलड़ा भारी है। हालांकि अभी के प्रदर्शन को देखते हुए केएल राहुल और इशान किशन की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

अतिरिक्त स्पिनर के स्थान के लिए अक्षर पटेल, युजवेंद्रा सिंह चहल और रवि बिश्नोई दौड़ में हैं। अक्षर जहां बाएं हाथ के स्पिनर हैं तो उपयोगी बल्लेबाज भी हैं। चहल ने अपने नौ साल के करियर में अभी तक एक भी टी-20 विश्व कप नहीं खेला है, लेकिन वह गेंदबाजी कौशल में अन्य दोनों से कहीं आगे हैं लेकिन बार बार महत्वपूर्ण टीम से उन्हें बाहर किया जाना जून में होने वाले टूर्नामेंट में उनके चयन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

गुकेश को फिर संयुक्त बढ़त, प्रगनानंद और गुजराती बाहर

कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट

युवा ग्रैंडमास्टर डी गुकेश • प्रेट्र

टोरंटो, प्रेट्र : भारत के युवा ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए अजरबैजान के निजात अबासोव को हराकर कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में संयुक्त बढ़त बना ली, लेकिन आर प्रगनानंद और विदित गुजराती 12वें दौर के बाद दौड़ से बाहर हो गए।

अमेरिका के हिकारू नकामूरा ने फ्रांस के फिरोज अलीरेजा को हराया। गुकेश और नकामूरा अब रूस के इयान नेपोम्नियाच्चि के साथ शीर्ष पर हैं जिन्होंने प्रगनानंद से ड्रा खेला। इन तीनों के 7.5 अंक हैं जबकि अमेरिका के फेबियानो कारूआना उनसे आधा अंक पीछे हैं। प्रगनानंद छह अंक लेकर पांचवें स्थान पर हैं जबकि गुजराती के पांच अंक हैं। आठ खिलाड़ियों के दोहरे राउंड राबिन टूर्नामेंट के दो दौर बाकी हैं और उनके लिए शीर्ष तीन में स्थान बनाना असंभव है। महिला वर्ग में चीन की झोंग्यी तान ने बुल्गारिया की नूरगुल सलीमोवा से ड्रा खेला। रूस की कैटरीना लागनो ने चीन की टी लेइ को ड्रा पर रोका। भारत की कोनेरू हंपी ने रूस की अलेक्जेंड्रा गोरियाश्किना से ड्रा खेला जबकि आर वैशाली ने यूक्रेन की अन्ना एम को हराया। तान के आठ अंक हैं और लेइ उनसे आधा अंक पीछे हैं। हंपी, लागनो और गोरियाश्किना छह अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं। वैशाली 5.5 अंक के साथ छठे स्थान पर हैं। 17 वर्ष के गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में खेलने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उनसे पहले 1959 में बाबी फिशर ये टूर्नामेंट खेलने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ी बने थे।

पूनिया-सुजीत की ओलिंपिक आशाओं को झटका

खेल डायरी

बिश्केक, प्रेट्र : अमन सहरावत एशियाई ओलिंपिक क्वालीफायर में शुक्रवार को अपना सेमीफाइनल हारने के बाद पेरिस ओलिंपिक के लिए कोटा प्राप्त करने से चूक गए, जबकि दीपक पुनिया और सुजीत कलकल को वजन करने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला।

अमन ने 57 किग्रा वर्ग में दबदबे वाला आगाज करते हुए अपने शुरुआती दो प्रतिद्वंद्वियों येरासिल मुख्तारुली और सुंगवान किम को तकनीकी श्रेष्ठता से हराया। यद्यपि वह उज्बेकिस्तान के गुलोमजोन अब्दुल्लेव के विरुद्ध इस लय को जारी रखने में विफल रहे और 10 अंकों से पिछड़ने के बाद हार गए।

भारतीय कुश्ती जगत को अमन से काफी आशाएं थी क्योंकि उन्होंने अपने आयु वर्ग में मजबूत माने जाने वाले रवि दाहिया को शिकस्त देकर देश के प्रतिनिधित्व का मौका प्राप्त किया था। जयदीप ने 74 किग्रा वर्ग में शानदार शुरुआत की और तुर्कमेनिस्तान के अल अर्सलान बेगेनजोव को हराया। वह क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान के ओरोजोबेक तोक्तोमाम्बेतोवबाद के विरुद्ध मुकाबला 2-2 से बराबर होने के बाद हार गए। सुमित मलिक (125 किग्रा) भी अपने पहले दौर में किर्गिस्तान के लखागवागेरेल मुनखतूर से हार गए।

धाविका शालू चौधरी को क्लीन चिट

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय डोपिंग निरोधी एजेंसी की अपील पैनल ने मध्यम दूरी की धाविका शालू चौधरी को डोपिंग के आरोपों से बरी करके चार वर्ष का प्रतिबंध हटा दिया है क्योंकि डीएनए टेस्ट में पता चला कि उनके मूत्र के नमूने से या तो छेड़छाड़ की गई या लेते समय वह दूषित हो गया था। 30 वर्ष की चौधरी पर पिछले वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था और वह नाडा की अनुशासन समिति के सामने अपील हार गई थी। उन्हें दो प्रतिबंधित दवाओं के कथित इस्तेमाल के कारण प्रतिबंध झेलना पड़ा था। 800 मीटर में राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता चौधरी ने मूत्र के नमूने के डीएनए टेस्ट की मांग की, जिसे अनुशासन समिति ने तो खारिज कर दिया लेकिन अपील पैनल ने मान लिया। डीएनए जांच लंदन के किंग्स कालेज स्थित फारेंसिक विभाग ने कराई। अपीली पैनल ने कहा, 'मूत्र के नमूने के पिछले विश्लेषण में डीएनए प्रोफाइल सही नहीं आया है। डीएनए नमूने की जांच रिपोर्ट को देखते हुए नाडा के वकील कोई और कारण नहीं बता पाए है, जिससे अपीली पैनल खिलाड़ी की अपील खारिज करने का निर्णय ले।'

आकांक्षा एशियन क्वालीफाइंग स्क्वाश में हारीं

नई दिल्ली : भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी आकांक्षा सालुंखे कुआलालंपुर में विश्व चैंपियनशिप एशियाई क्वालीफाइंग प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हारकर प्रतियोगिता बाहर हो गईं। राष्ट्रीय खेल 2023 की चैंपियन और यहां दूसरी वरीय आकांक्षा को मलेशिया की सेहवीत्रा ने 6-11, 5-11, 8-11 से हराया।

कप्तान के रूप में उदाहरण पेश करना महत्वपूर्ण : नवास

सुकांत सौरभ • जागरण

नई दिल्ली : स्पेन की विश्व कप विजेता फुटबाल टीम का हिस्सा रहे जीसस नवास वर्तमान में ला लीगा की शीर्ष टीमों में से एक सेविया के कप्तान हैं। विश्व कप को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इसे जीतना जीवन का सबसे विशेष अनुभव था। नवास इंग्लिश प्रीमियर लीग के शीर्ष क्लब मैनचेस्टर सिटी का हिस्सा भी रह चुके हैं। दोनों टीमों के अपने अनुभव को साझा करते हुए नवास ने बताया कि दोनों ही टीमें बिल्कुल अलग हैं। प्रीमियर लीग में खेल की गति अधिक तेज होती है। साथ ही तकनीकी रूप से भी दोनों लीग अलग हैं। वहीं, कप्तान के रूप में दायित्व को लेकर उन्होंने कहा कि उदाहरण पेश करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ला लीगा में सेविया ने विगत दोनों मुकाबले जीते हैं। वहीं, मंगलवार को उसे मालोर्का से भिड़ना है।

मैनचेस्टर सिटी की गति पसंद थी : नवास ने मैनचेस्टर सिटी और सेविया के बीच के अंतर को लेकर बताया, 'सेविया मेरे घर जैसा है। यहां मेरा बचपन बीता है। मैं यहां अपने खेल का पूरा आनंद ले रहा हूं। प्रीमियर लीग की गति और तकनीक ला लीगा से बिल्कुल अलग है। मुझे मैनचेस्टर सिटी के खेल की गति बहुत पसंद है। मैं जब तक टीम का हिस्सा रहा मैंने मैनचेस्टर सिटी में बहुत कुछ सीखा।'

सीखते रहना आवश्यक : कप्तान के रूप में जब टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करे तब क्या सोच होती है, इस पर नवास ने कहा, 'कप्तान के रूप में मेरा दायित्व होता है कि हर समय टीम के खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रखूं। विशेषकर युवा खिलाड़ियों के लिए हर समय उपलब्ध होना आवश्यक है। मुझे अधिक ट्रेनिंग करनी होती है, ताकि मैं उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं। सबसे महत्वपूर्ण है विनम्र रहना, क्योंकि तभी आप कुछ न कुछ सीख सकते हो।'

विश्व कप जीतने का गर्व : जीवन के सबसे विशेष क्षण के बारे में पूछने पर नवास ने बताया, 'ट्राफी जीतना जीवन का सबसे विशेष क्षण होता है। स्पेन की राष्ट्रीय टीम के साथ मैंने जो भी प्रतियोगिताएं जीतीं सभी विशेष थीं। हालांकि, विश्व कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसे जीतने का सपना हर फुटबाल खिलाड़ी का होता है। फुटबालर के रूप में यह उपलब्धि प्राप्त करना ही जीवन का सबसे विशेष क्षण था। मुझे गर्व है कि मैंने यह उपलब्धि प्राप्त की है।

बेंगलुरु युनाइटेड के साथ है साझेदारी

सेविया ने भारत में भी बेंगलुरु युनाइटेड एफसी के साथ साझेदारी कर रखी है। भारत में फुटबाल के विकास के लिए सेविया क्लब बेंगलुरु युनाइटेड एफसी के साथ स्थानीय स्तर पर काम कर रहा है। इस संबंध में सेविया के अध्यक्ष जोस मारिया ने बताया, 'भारत में स्थानीय फुटबाल कैसे काम कर रहा है, यह समझने के लिए ही सेविया एफसी ने बेंगलुरु युनाइटेड के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की है। हमने अपने भारतीय प्रशंसकों के लिए विशेष रूप से 'नेवर सरेंडर' सीरीज तैयार किया है। हमारे लिए, भारत में अपने प्रशंसक आधार को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, यहां कि संस्कृति हमारे साथ कई मूल्यों को साझा करती है। हम बेंगलुरु युनाइटेड के साथ अपने ज्ञान और अपनी कार्यप्रणाली को साझा करके भारतीय फुटबाल को उनकी विकास रणनीति में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही अगर फुटबाल महासंघ चाहे तो हम उनके साथ गठबंधन की योजना बनाने के लिए भी तैयार हैं।'

****

दैनिक जागरण
सप्तरंग
जोश नई राहों का
शनिवार, 20 अप्रैल, 2024

फिर से करना चाहती हूं हिंदी से स्नातक

काउंसलर

अरुण श्रीवास्तव
counselor@nda.jagran.com

मैंने हिस्ट्री आनर्स से बीए कर रखा है। पर मेरा मन अब हिंदी से भी आनर्स करने का है। क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है?

निशा

अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने की इच्छा रखने वालों के लिए आज के समय में अनेक तरीके हैं। यदि आप नियमित छात्र के रूप में पढ़ना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा में शामिल होना पड़ सकता है। इसके माध्यम से आप मनपसंद कालेज में प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं। हां, आप चाहें तो प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में या फिर पत्राचार के माध्यम से इग्नू या किसी अन्य मुक्त विश्वविद्यालय से भी कोर्स कर सकती हैं। केंद्र सरकार और यूजीसी के प्रोत्साहन से कुछ संस्थान अब आनलाइन कोर्स भी संचालित करने लगे हैं। आप इनमें से किसी भी विकल्प को चुन कर अपनी इच्छा पूरी कर सकती हैं।

मैंने इस वर्ष पीसीएम से बारहवीं किया है। मेरी रुचि कंप्यूटर में है। मुझे कंप्यूटर साइंस से बीएससी करनी है, लेकिन मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। इसकी मैं बेसिक कोचिंग लूंगा। क्या मुझे इसके लिए कुछ मानदंड पूरे करने होंगे? कृपया मार्गदर्शन करें।

कार्तिक राय

आज के समय में कंप्यूटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं। आप स्मार्टफोन तो चलाते ही होंगे। कंप्यूटर के बहुत सारे काम अब स्मार्टफोन से होने लगे हैं। फिर भी यदि आपको स्मार्टफोन के बहुत सारे फीचर के बारे में नहीं पता है, तो किसी जानकार से सीख सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर पर कुछ दिन काम करने पर आप इसे चलाना सीख सकते हैं। साथ ही धीरे-धीरे इसके दूसरे उपयोगी फीचर भी सीख सकेंगे। मेरे विचार से अब इसके लिए आपको अलग से कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने पर भरोसा रखें। यदि आपके किसी जानने वाले के पास लैपटाप या डेस्कटाप हो, तो आग्रह करके उनसे बुनियादी चीजें सीख सकते हैं।

टर्निंग प्वाइंट

यदि समुचित रणनीति और योजना बनाकर धैर्यपूर्वक तैयारी करें, तो आप भी निश्चित रूप से आइएएस बन सकते हैं। इसके लिए और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, बता रहे हैं अपने चौथे प्रयास में इस बार की सिविल सेवा परीक्षा (2023) में 20वां रैंक प्राप्त करने वाले आकाश वर्मा...

आप भी बन सकते हैं आइएएस!

फोटो: इमेजेज बाजार

सिविल सेवक बनने का सपना मेरा बचपन से था। शुरू से ही घर में ऐसा ही माहौल मिला, क्योंकि परिवार और रिश्तेदारों में कई लोग अच्छे पदों पर थे, इससे कहीं न कहीं मुझे भी आगे बढ़ने में उनसे प्रेरणा मिली। मैंने अपनी तैयारी एमबीए के बाद शुरू की। वर्ष 2018 में मैंने पहली बार इसके लिए कोचिंग ली। मुख्य परीक्षा के लिए लोक प्रशासन विषय रखकर पहला अटेम्प्ट मैंने 2020 में दिया। अपने पहले ही प्रयास में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन अंतिम सफलता नहीं मिली। फिर मैंने सेल्फ स्टडी पर फोकस किया। लोक प्रशासन की जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय चुना। आखिरकार चौथे प्रयास में मुझे इस बार सफलता के साथ-साथ देशभर में 20वीं रैंक भी मिल गई।

पाठ्यक्रम पर केंद्रित हो तैयारी: जहां तक सिविल सेवा परीक्षा की बेहतर तैयारी की बात है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर यही कहूंगा कि अपनी तैयारी को पूरी तरह इस परीक्षा के पाठ्यक्रम पर केंद्रित रखना चाहिए। इससे आप भ्रमित नहीं होंगे। क्योंकि 80-85 प्रतिशत पाठ्यक्रम हर साल एक जैसा ही रहता है, बस, अब प्रश्न थोड़े ज्यादा तथ्यात्मक हो गए हैं। मेरे विचार से युवाओं को सबसे पहले मुख्य परीक्षा के विषयों की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञान का स्तर बढ़ेगा और यही ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में भी काम आएगा।

एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ें: जैसा दूसरे उम्मीदवार करते हैं, उसी तरह मैंने भी अपने सामान्य अध्ययन के स्तर को सुधारने के लिए एनसीईआरटी की कक्षा छह से 12वीं तक के विभिन्न विषयों की किताबों को पढ़ा। मेरा मानना है कि चाहे आप आर्ट या कामर्स से हों या इंजीनियरिंग से, इसकी तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए।

नियमित हो अध्ययन: मैं अपने पहले प्रयास के दौरान प्रतिदिन छह से सात घंटे पढ़ता था। मेरे विचार से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते समय नियमित रूप से पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यह कोई रेस नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। इसके लिए आपको लगातार पढ़ते रहने की जरूरत होती है। मेरा चयन जब डिफेंस सर्विस में हो गया, तब जाब करते हुए प्रतिदिन तीन-चार घंटे ही पढ़ पाता था। हालांकि इसमें भी हर दिन एक टेस्ट देता था। इसमें लगभग तीन घंटे लग जाते थे और एक घंटे उसके उत्तर के विश्लेषण में लगाता था। मैं प्रश्नों को हल करने का अभ्यास खूब करता था। क्योंकि शुरुआती प्रयासों में मेरा बेसिक तैयार हो गया था। मेरी राय में यदि आप हर दिन छह-सात घंटे पूरे मन से पढ़ रहे हैं, तो इतना इस तैयारी के लिए पर्याप्त है। किसी की देखादेखी घंटों पढ़ते रहने की जरूरत नहीं है। चूंकि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस बहुत व्यापक होता है, इसलिए इसके लिए ज्यादा घंटे तक पढ़ाई करने की जरूरत होती है। लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी करते समय क्वालिटी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। ऐसा भी नहीं है कि बस लगातार पढ़ते ही रहें। यदि एक हफ्ता पढ़ें तो एक-दो दिन प्रैक्टिस पर भी समय दें। उत्तर लिखने का अभ्यास करें। अपनी समय सारिणी के अनुसार अलग-अलग विषय पढ़ें। इससे पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी।

सीसैट की रणनीति: एमबीए के लिए मैंने कैट की तैयारी पहले से कर रखी थी, इसलिए मुझे सीसैट को लेकर अधिक परेशानी नहीं हुई। बस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दिया। लेकिन यदि आप इस प्रश्नपत्र के लिए मैथ पर फोकस करें, तो इसे आसानी से क्लियर किया जा सकता है।

कोचिंग जरूरी नहीं: मेरे विचार से इस परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग जरूरी नहीं है। लेकिन यदि कोई यह कहता है कि उसने कोचिंग की मदद नहीं ली है, तो वह गलत कह रहा है। क्योंकि कोचिंग की क्लासेज आप भले ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज, माक इंटरव्यू की तैयारी घर में बैठकर नहीं हो सकती है। मैंने मुख्य परीक्षा के लिए कम से कम 40 से 50 टेस्ट सीरीज किए। कई माक इंटरव्यू भी दिए। मेरी राय में, आप जिस भी संस्थान के इंटरव्यू पैनल की मदद लें, वहां कुछ अंतराल पर कम से कम दो माक इंटरव्यू जरूर दें। इससे पैनल के एक्सपर्ट आपके बारे में ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे।

ऐच्छिक विषय चुनने का सही तरीका: ऐच्छिक विषय चुनते समय अपनी रुचि का ख्याल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसमें गहरी जानकारी होने की अपेक्षा की जाती है। वैसे, यदि आप अपने स्नातक के विषय को ही चुनते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ें: इस परीक्षा की तैयारी में अपने आपको अपडेट रखने के लिए नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। अखबारों में आपको कई ऐसे प्वाइंट्स मिलते रहते हैं, जिन पर आगे की तैयारी करने में मदद मिलती है। किसी मुद्दे पर अपनी एक तटस्थ राय बनाने में भी मदद मिलती है। अखबार प्रतिदिन करीब 20-25 मिनट पढ़ें।

प्रस्तुति: धीरेंद्र पाठक

सफलता के मंत्र

मेरी राय में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आपको धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको एक प्रयास में सफलता नहीं मिलती है, तो यह न सोचें कि आपमें क्षमता नहीं है। बस, फोकस्ड रहें और मन में यह विचार रखें कि कोई नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर, मेहनत करने से न कतराएं। पढ़ाई के घंटे न गिनें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर पढ़ें। बस जो भी पढ़ें, क्वालिटी पढ़ाई पढ़ें। जहां तक हो सके, ग्रुप में पढ़ाई करें। इससे फायदा यह होगा कि आप आपस में चीजें एक दूसरे से साझा करते रहेंगे। केवल टेस्ट देते रहने से यह संभव नहीं हो पाता। साथ ही, ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दें। इंटरनेट मीडिया से जितना हो सके, दूरी बनाकर रखें।

आनलाइन लर्निंग

करेंट अफेयर्स की आनलाइन तैयारी

आने वाले कुछ महीनों में यूपीएससी की सिविल सेवा प्रा.परीक्षा, एसएससी, पुलिस, रेलवे और आइबीपीएस समेत कई परीक्षाएं होने वाली हैं। इन सभी में करेंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइये जानें घर बैठे कैसे जनरल नालेज, करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से जुड़े प्रश्नों की कुछ एप की मदद से आनलाइन तैयारी कर सकते हैं...

जीके एंड करेंट अफेयर्स 2024: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक उपयोगी एप है, जिसके कंटेंट निश्शुल्क और आफलाइन माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप में आपको डेली करेंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश में फ्री माक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, एग्जाम टार्गेट क्वेश्चंस, नोट्स तथा एग्जाम अपडेट जैसे बहुत से फीचर एक साथ मिलेंगे। इसके अलावा, यहां पांच हजार से अधिक बहुविकल्पीय टाइप जीके क्वेश्चंस, करेंट अफेयर्स क्विज तथा जीके ट्रिक्स की भी सुविधाएं मिलेंगी। यह एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

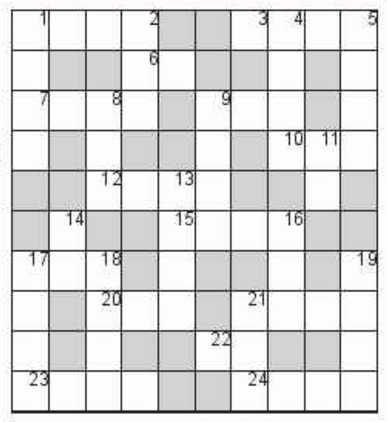

जीके क्विज जनरल नालेज एप

वर्ल्ड जीके की तैयारी में यह एप भी काफी मददगार हो सकता है। यहां पर निश्शुल्क जीके क्विज की मदद से आप अपने जनरल नालेज को बहुत आसानी से सुधार सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को जीके क्विज के अलावा, प्रैक्टिस क्विज क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज तथा जनरल नालेज के प्रश्नों का एक बहुत बड़ा बैंक यहां मिल सकता है। यह एप भी गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

वर्ग पहेली-2606

बाएं से दाएं

1 भद्दापन, बदसूरती (4)। 3 सामर्थ्य, बिसात, पद (4)। 6 मत्स्य, एक राशि (2)। 7 क्षमा करने की प्रवृति वाला (4)। 9 धोखा, छल (3)। 10 नृत्य करना, चक्कर मारना, परेशान होना (3)। 12 मुग्ध या आसक्त होना (2,2)। 15 .नरश्रेष्ठ, विष्णु (3)। 17 मध्य प्रदेश की एक नदी (3)। 20 टेसू का फल, शेर (3)। 21 सलोना, लावण्ययुक्त (4)। 22 संदेह, अविश्वास (2)। 23 चांद, मयंक (4)। 24 एक प्रकार का छंद (4)।

ऊपर से नीचे

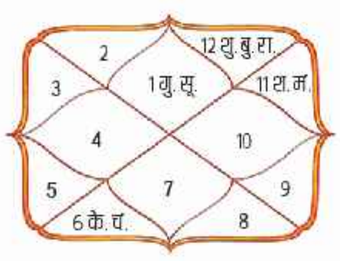

1 दुराचार, कुरीति, बुरी चाल (4)। 2 अमल करना, आज्ञा पालन (3)। 4 सिकुड़ना, संकुचित (4)। 5 किसी चीज के अभाव का दुख सहना (4)। 8 ठंडा, उद्वेग रहित (3)। 9 सुगंधित फूलों का एक वृक्ष (4)। 11 शीघ्र, जल्दी से (2)। 13 अच्छे लक्षणों का (4)। 14 चमड़ा, खाल (2)। 16 गबन, पाचनक्रिया (3)। 17 मादक वस्तु का सदा सेवन करने वाला (4)। 18 अन्न-जल, जीविका (2,2)। 19 ऋणी, दानी (4)। 21 असली का विलोम (3)।

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

आ	था	र					श	री	र
ल		ह	त		सिं	पा	ही		बा
य	ती	म			बा		द	बा	ना
	ब्र		ता	ली	य	क		जी	
	ता	ड	ना			मा			
			शा			सु	ब	ह	
	गा		ह	ता	ह	त		रा	
दा	य	क		ली			ब	ना	ना
खि		स	न	म		रा	था		ह
ला	य	क					ई	श्व	र

जागरण सुडोकू-2606

8			5			1		3
6	3			2	1			8
				8			6	
	8		6				3	
1		4			3			2
			8			7	1	
2	5					3		1
		9	2		6			
			1					9

कल का हल

1	5	2	4	3	8	9	7	6
6	3	8	2	9	7	1	4	5
9	4	7	5	1	6	2	8	3
4	1	5	6	7	3	8	2	9
3	7	9	8	2	5	6	1	4
8	2	6	9	4	1	3	5	7
7	9	1	3	8	4	5	6	2
5	8	3	7	6	2	4	9	1
2	6	4	1	5	9	7	3	8

आज का भविष्यफल- 20 अप्रैल, 2024 शनिवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी।
आज का राहुकाल : प्रात : 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक।
आज का दिशाशूल : पूर्व। आज का पर्व एवं त्योहार : मदन द्वादशी

कल 21 अप्रैल, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : पश्चिम
कल का पर्व एवं त्योहार : प्रदोष व्रत, श्री महावीर जयंती (जैन)
विक्रम संवत 2081 शके 1946 उत्तरायण, उत्तरगोल, वसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तत्पश्चात चतुर्दशी उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र तत्पश्चात हस्त नक्षत्र व्याघात योग तत्पश्चात हर्षण योग कन्या में चंद्रमा।

मेष : यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। जीवन सुखमय होगा।
वृष : गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। दायित्व की पूर्ति होगी।
मिथुन : कुछ पारिवारिक समस्या हो सकती है। महत्वाकांक्षा पूरी होगी।
कर्क : सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा सुखद होगी।
सिंह : व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
कन्या : रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। सहयोग मिलेगा।
तुला : घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। कार्य में सफलता मिलेगी।
वृश्चिक : पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।
धनु : महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
मकर : आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।
कुंभ : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें।
मीन : आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

राष्ट्रीय फलक

भूमि, समुद्र, वायु क्षेत्रों की सीमाएं हो रही हैं धुंधली : वायुसेना प्रमुख

- कहा, युद्ध लड़ने के तरीकों में आ रहा है तेजी से बदलाव
- नई संभावनाओं के साथ नए खतरे भी सामने आ रहे

नई दिल्ली, प्रेट्र : वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि भूमि, समुद्र, वायु, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र की पारंपरिक सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं, जिससे युद्ध लड़ने के तरीकों में बदलाव आ रहा है। इसके लिए हमें हमेशा चौकस रहने की जरूरत है। भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि हमारी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए जो अंतरिक्ष में हमारे हितों की रक्षा करें। वायुसेना प्रमुख ने कार्यक्रम को पहले से रिकार्ड किए गए वीडियो के जरिये संबोधित किया।

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि नई प्रौद्योगिकियों में तेजी से बदलाव आ रहा है और अंतरिक्ष को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया है। इसके चलते पहले से स्थापित योजनाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। नई संभावनाएं नए समाधान और बाहरी अंतरिक्ष तक कम लागत वाली पहुंच के लिए नया नजरिया प्रस्तुत कर रही हैं। हालांकि, इन नई संभावनाओं के साथ नए खतरे भी सामने आ रहे हैं।

वीआर चौधरी ने कहा, निजी उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी से हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र लोकतांत्रिक हुआ है। आम आदमी की अंतरिक्ष यात्रा 25 साल पहले एक सपना थी, लेकिन आज यह एक सच्चाई है। निजी उद्यमियों और सेना द्वारा अंतरिक्ष के बढ़ते दोहन के साथ निश्चित रूप से इस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। बताते चलें, मानेकशा सेंटर में आयोजित होने वाली संगोष्ठी में सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी और अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। फाइल

यूपीएससी टापर आदित्य श्रीवास्तव ने हासिल किए 54.27 प्रतिशत अंक

- यूपीएससी ने जारी किए सफल अभ्यर्थियों के अंक
- दूसरे टापर अनिमेष प्रधान को 1,067 अंक मिले
- तीसरी रैंक पर आने वाली अनन्या रेड्डी को 1,065 अंक मिले

नई दिल्ली, प्रेट्र : संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा, 2023 में चयनित अभ्यर्थियों के अंक शुक्रवार को जारी कर दिए। परीक्षा के टापर आदित्य श्रीवास्तव ने 54.27 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। दूसरी रैंक हासिल करने वाले अनिमेष प्रधान को 52.69 प्रतिशत अंक मिले हैं। बताते चलें, सिविल सेवा परीक्षा, 2023 में 1,016 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें 664 पुरुष और 352 महिलाएं शामिल हैं। परीक्षा के परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए थे। सभी सफल अभ्यर्थियों के अंक यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं।

यूपीएससी के अनुसार, आदित्य श्रीवास्तव को कुल 1,099 अंक मिले। उन्हें लिखित परीक्षा में 899 और व्यक्तित्व परीक्षण में 200 अंक मिले। वह एक प्रशिक्षु आइपीएस अधिकारी हैं और लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने आइआइटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। सिविल सेवा परीक्षा में उनका वैकल्पिक विषय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था।

ओडिशा के अंगुल जिले के निवासी अनिमेष प्रधान ने 1,067 अंक हासिल किए। उन्हें लिखित में 892 और साक्षात्कार में 175 अंक मिले। उन्होंने परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र लिया था। प्रधान ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) राउरकेला से कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक किया और वर्तमान में यहां इंडियन आयल कार्पोरेशन के रिफाइनरी डिवीजन में काम कर रहे हैं।

तीसरी रैंक पर आने वाली अनन्या रेड्डी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार के रूप में परीक्षा में शामिल हुईं। उन्हें 1,065 अंक (52.59 प्रतिशत) मिले। उन्हें लिखित में 875 और साक्षात्कार में 190 अंक मिले। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से भूगोल में बीए (आनर्स) करने वाली अनन्या ने वैकल्पिक विषय के रूप में मानव विज्ञान लिया था। वह तेलंगाना के महबूबनगर की रहने वाली हैं।

चौथी रैंक पर आने वाले पीके सिद्धार्थ रामकुमार ने 1,059 अंक (52.29 प्रतिशत) हासिल किए। उन्हें लिखित में 874 और साक्षात्कार में 185 अंक मिले। रामकुमार के पास त्रिवेंद्रम के कालेज आफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री है। इस परीक्षा में रुहानी को 1,049 अंकों (51.8 प्रतिशत) के साथ पांचवीं रैंक मिली है। उन्हें लिखित में 856 और साक्षात्कार में 193 अंक मिले। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कालेज से अर्थशास्त्र में बीए (आनर्स) की पढ़ाई की है।

आदित्य श्रीवास्तव। फाइल

लव जिहाद का शिकार हुई युवती, पीटा और जख्मों पर मिर्च डाली

- युवती चिल्लाई तो मुंह और आंख में लगा दिया था फेवीक्विक
- मप्र के गुना में अयान पठान नाम के युवक ने की युवती से बर्बरता

नईदुनिया, गुना : मध्य प्रदेश के गुना में लव जिहाद की शिकार एक युवती के साथ आरोपित अयान पठान ने शादी करने और मकान नाम कराने से इन्कार करने पर बर्बरता की। इतना पीटा कि युवती की एक आंख खराब हो गई है। इतना ही नहीं, युवती के जख्मों पर मिर्च डाली और उसकी आवाज को दबाने के लिए मुंह और आंख में चिपकाने वाला पदार्थ (फेवीक्विक) लगा दिया। युवती का इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती युवती ने बताया कि अयान पठान ने पेट पर बैठकर जूती और बेल्ट से आंखों पर कई वार किए, जिससे उसके चेहरे और आंखों में काफी सूजन है और काले निशान पड़ गए हैं।

युवती को पड़ोस में रहने वाले अयान खान ने पहले तो लव जिहाद में फंसाया। इसके बाद शादी करने और मकान स्वयं के नाम कराने का दबाव बनाने लगा। युवती की मां ने झूठ बोल दिया कि मकान तो उसने बेच दिया है। उसे नाम नहीं किया जा सकता। इससे नाराज अयान ने युवती को बेल्ट और जूतों से पीटा फिर उसके जख्मों पर मिर्च पाउडर लगा दिया।

इस पर युवती चिल्लाई तो मुंह और आंख में चिपकाने वाला पदार्थ लगा दिया। बुधवार को किसी तरह युवती अयान के चंगुल से छूटी और मां के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई। यहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया।

युवती को बहला-फुसलाकर प्रेमजाल में फंसाया

पीड़िता की मां ने बताया कि उनके पति की मौत करीब 10 साल पहले कैंसर से हो गई थी। पीड़िता उनकी इकलौती पुत्री है। लेकिन पड़ोस में रहने वाले अयान पठान ने बेटी को बहला-फुसलाकर प्रेमजाल में फंसा लिया। कैंट थाना प्रभारी दिलीप राजौरिया के अनुसार, आरोपित अयान खान को 60 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय से चार घंटे का पुलिस रिमांड मिला था। युवती की शिकायत पर अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

आदेश

पटियाला रियासत के पूर्व नाजिम के उत्तराधिकारियों के पक्ष में हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1927 में महाराजा पटियाला की ओर से बनाई गई कमेटी ने पूर्व नाजिम की पूरी संपत्ति जब्त करने का दिया था आदेश

97 वर्ष पूर्व केस में उत्तराधिकारियों को मिले 923 एकड़ भूमि

- नाजिम भगवंत सिंह ने 1927 में दायर किया था केस, हाई कोर्ट ने अब सुनाया इस मामले में फैसला

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़

पटियाला के महाराजा द्वारा हटाए गए तत्कालीन नाजिम (प्रशासक) भगवंत सिंह की जमीन को लेकर लगभग एक सदी पुराने झगड़े पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राजस्व रिकार्ड में भूमि से पंजाब सरकार का मालिकाना हक हटाने व पूर्व नाजिम के कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम मालिकाना हक राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने उन्हें कब्जा देने का आदेश जारी करने से फिलहाल इन्कार कर दिया है। 923 एकड़ उक्त जमीन के कब्जे के संबंध में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कब्जे की सुपुर्दगी का मुद्दा पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1973 के तहत सीलिंग सीमा के संबंध में अदालत में लंबित मामले के नतीजे के बाद तय किया जाएगा।

विवादित जमीन का बड़ा हिस्सा खानपुर, बुंगा, सेखा जिला मलेरकोटला और गांव तंगराला, तहसील अमलोह, अब जिला फतेहगढ़ साहिब और गांव हरयू कलां, तहसील पटरान और गांव बौंगर, तहसील और जिला पटियाला में आता है।

बता दें कि भगवंत सिंह तत्कालीन पटियाला रियासत में नाजिम थे और बड़ी जमीन के मालिक थे। अप्रैल 1927 में पटियाला के महाराजा ने एक प्रशासनिक समिति नियुक्त की थी, जिसने न केवल भगवंत सिंह को नाजिम के पद से बर्खास्त किया, बल्कि उनकी स्व-अर्जित संपत्ति और उनकी आधी पैतृक संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया। इस पर भगवंत सिंह ने 9 जून, 1927 को उपरोक्त भूमि को अलग करने से रोकने के लिए केस दायर किया। इस पर न्यायालय ने पंजाब सरकार को भगवंत सिंह के कब्जे में हस्तक्षेप करने तथा संपत्ति को अलग करने से रोक दिया। इसी बीच लाभ सिंह (वर्तमान याचिकाकर्ता) ने गांव हरियू, तहसील और जिला पटियाला में स्थित भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हुए लगभग 54 आपत्तियां दायर कीं। फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि को सही किया जाएगा और स्वर्गीय भगवंत सिंह के प्रतिनिधियों को राजस्व रिकार्ड में स्वामित्व के कालम में मालिकों के रूप में दर्शाया जाए और उपरोक्त घोषणा 1953 अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी अन्य आदेश के अधीन होगी।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। फाइल

गैंगस्टर एक्ट में कुर्क नहीं कर सकते कमाई से अर्जित संपत्ति : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कमाई से अर्जित की गई संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क नहीं की जा सकती। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने संभल जिले के हजरतनगर गढ़ी थाने में गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी पर डीएम का आदेश मनमाना मानते हुए उसे रद कर दिया है। साथ ही कहा है कि डीएम नए सिरे से विचार कर आदेश पारित करें।

यह आदेश कोर्ट ने रजी हसन व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची का दो मंजिला मकान खुद की कमाई से बनाया गया है। डीएम ने पुलिस रिपोर्ट को आधार मानते हुए संपत्ति की कुर्की का आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। डीएम ने यह आदेश बिना दिमाग लगाए यांत्रिक तरीके से पारित कर दिया। याची पर आरोप था कि उसने दो मंजिला मकान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के जरिये बनवाया है। वह एक गिरोह का सदस्य है, जो जुए में सक्रिय है। लोगों को डराने-धमकाने के साथ पैसे की वसूली करवाता है। लोगों में उसका भय और आतंक है, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। डीएम ने पुलिस की इस रिपोर्ट के आधार पर उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित कर दिया। इसे याची ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। कहा, संपत्ति पुश्तैनी है।

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मिली जमानत, जेल से रिहा

मुंबई, प्रेट्र : यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को बैंक धोखाधड़ी मामले में अदालत से जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद शुक्रवार शाम जेल से रिहा कर दिया गया। कपूर को मार्च 2020 में ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में पहली बार गिरफ्तार किया था। ईडी और सीबीआइ ने उनके खिलाफ यस बैंक में कथित धोखाधड़ी से संबंधित कुल आठ मामले दर्ज किए हैं।

इससे पहले उन्हें सात मामलों में जमानत मिल चुकी है। उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया था। सीबीआइ मामलों के विशेष जज एमजी देशपांडे ने कपूर को जमानत दे दी। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।

****

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 20 अप्रैल, 2024
आजकल
14
www.jagran.com

मैरी और पियरे क्यूरी ने पिचब्लेंड से रेडियम को अलग करने में सफलता पाई

1902 में आज ही के दिन मैरी और पियरे क्यूरी ने पेरिस में अपनी प्रयोगशाला में खनिज पिचब्लेंड से रेडियोधर्मी रेडियम को अलग करने में सफलता पाई थी। इसके लिए 1903 में दोनों को नोबेल मिला। 1898 में क्यूरी दंपती ने पिचब्लेंड में रेडियम और पोलोनियम तत्वों के अस्तित्व की खोज की थी।

पहली बार फ्रांस में किया गया पाश्चराइजेशन का सफल प्रयोग

1862 में आज ही लुई पाश्चर और क्लाउड बर्नार्ड ने फ्रेंच एकेडमी आफ साइंस के समक्ष कुत्ते के पाश्चराइज किए हुए रक्त- मूत्र के नमूने पेश किए थे जो पूरी तरह सुरक्षित थे। इस प्रक्रिया में दूध जैसे अन्य तरल पदार्थों को गर्म कर उनके बैक्टीरिया को मारकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है।

गांधीजी और पंडित नेहरू भी थे भजन गायिका जुथिका राय के प्रशंसक

घूंघट के पट खोल और पग घुंघरू बांध मीरा नाची जैसे भजनों को अमर बनाने वाली गायिका जुथिका राय का जन्म 1920 में आज ही के दिन हावड़ा में हुआ था। सात साल की उम्र में गाना शुरू किया। 13 साल की उम्र में अपना पहला एल्बम रिकार्ड किया। 15 अगस्त, 1947 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उनसे झंडा फहराने तक रेडियो पर लगातार गाने का अनुरोध किया था। इसी वर्ष सांप्रदायिक तनाव के दौरान कोलकाता में आयोजित एक सभा में गांधीजी के कहने पर उन्होंने भजन गाकर शांति का संदेश दिया था।

कानपुर में बनेगा देश का पहला वूंड केयर सेंटर

बेहतर इलाज ▶ जीएसवीएम कालेज के प्राचार्य ने शासन को भेजा प्रस्ताव, 50 करोड़ रुपये से होगा निर्माण

सेंटर के तीन मंजिला भवन में होंगी अत्याधुनिक सुविधाएं, मरीजों को मिलेगा लाभ

ऋषि दीक्षित ● जागरण

कानपुर स्थित जीएसवीएम में शुरू होगा सेंटर। फाइल

कानपुर: गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल (जीएसवीएम) कालेज देश का पहला सरकारी संस्थान होगा, जहां पुराने घाव के इलाज की अलग से व्यवस्था की जा रही है। देश के पहले वूंड केयर सेंटर में विदेश की तरह ही पुराने घाव का भी उपचार होगा और मधुमेह पीड़ितों को भी घावों का भी बेहतर इलाज किया जाएगा। मेडिकल कालेज प्रशासन ने इसके लिए राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली और लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट (एसजीपीजीआइ) जैसे उत्कृष्ट चिकित्सीय संस्थानों में पुराने घावों के इलाज की सुविधा नहीं है। मधुमेह पीड़ितों को डायबिटिक फुट की समस्या होती है। पुराने घावों के ठीक इलाज एवं देखभाल नहीं होने से 30 प्रतिशत मरीजों के पैर तक काटने की नौबत आती है। जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला, जब यहां विभागाध्यक्ष सर्जरी थे तो विदेश से वूंड केयर मैनेजमेंट का कोर्स करके भी आए थे। तभी से उन्होंने वूंड केयर सेंटर की स्थापना का प्लान बनाया था। अब उन्होंने प्रस्ताव तैयार कराकर शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा है।

प्राचार्य, जीएसवीएम मेडिकल कालेज, प्रो.संजय काला ने बताया कि देश के किसी सरकारी चिकित्सीय संस्थान में पुराने घावों के इलाज की सुविधा नहीं है। इसी कारण जीएसवीएम मेडिकल कालेज में वूंड केयर सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है। यह देश का पहला वुंड केयर सेंटर होगा, जहां सभी प्रकार के पुराने घावों से पीड़ितों का इलाज प्रबंधन किया जाएगा।

पुराने और गंभीर घाव होने के कारण

डायबिटिक फुट की समस्या, पैरों में रक्त संचार कम होना, लंबे समय तक खड़े होकर कार्य करने से पैरों में नस के गुच्छे बनने लगते, संक्रमण की वजह से घाव होना, आपरेशन के बाद के घाव, मधुमेह की वजह से घाव न भरना और रेडियोथेरेपी के बाद के घाव हैं। इसके कारण अन्य बीमारी होने का खतरा होता है।

सरकार को भेजे गए ये हैं प्रस्ताव

- 03 मंजिला बनेगा भवन।
- 20 प्राइवेट रूम दूसरे तल में होंगे।
- भूतल में वूंड केयर ड्रेसिंग रूम एवं इमरजेंसी
- पहले तल में कार्यालय एवं वार्ड।
- उपयोग में लाई जाएंगी यह मशीनें होंगी
- हाइपर बेरिक आक्सीजन
- पैरों का दबाव मापने की मशीन
- अत्याधुनिक लेजर मशीन
- वुंड केयर की आधुनिक मशीनें
- इसका होगा अलग इंतजाम
- घाव की स्पेशल ड्रेसिंग, घाव की गंभीरता मापने की मशीनें, प्रेशर बेड कम ड्रेसिंग टेबिल, आपरेशन थियेटर।

ड्रापलेट के आकार पर निर्भर नहीं करती हवाजनित बीमारी

न्यूयॉर्क टाइम्स से

प्रतीकात्मक

न्यूयार्क : जिस समय कोरोना महामारी फैली थी डब्ल्यूएचओ यह मानने को तैयार नहीं था कि कोरोना हवा से फैल सकती है। आखिरकार नवंबर 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने माना कि कोरोना हवा से फैली थी। डब्ल्यूएचओ ने सलाहकारों के समूह से वायरस फैलने के तरीकों को वर्गीकृत करने के लिए अपने दिशानिर्देशों को अपडेट करने के लिए भी कहा।

दो साल से अधिक की चर्चा के बाद समूह ने नई परिभाषाएं पेश करते हुए रिपोर्ट प्रकाशित की है। डब्ल्यूएचओ का पहले रुख यह था कि तपेदिक जैसे केवल कुछ वायरस - जो छोटी ड्रापलेट के तौर पर लंबी दूरी तक फैलते हैं, को वायुजनित बीमारी माना जा सकता है। लेकिन नई रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हवाजनित बीमारी ड्रापलेट के आकार पर निर्भर नहीं करती हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के तपेदिक विशेषज्ञ और समूह के सदस्य डा. एड नार्डेल ने कहा, यह महत्वपूर्ण पहला कदम है। माना जाता रहा है कि हवाजनित बीमारियों में पांच माइक्रोन से छोटी ड्रापलेट होनी चाहिए थी जो लंबी दूरी तक तैरती रहती हैं जब तक कि कोई सांस द्वारा उसे अंदर न ले। रिपोर्ट में कहा गया कि ड्रापलेट के लिए पांच-माइक्रोन सीमा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

साहसिक छलांग...

उत्तरी ध्रुव के करीब रूसी ध्रुवीय स्टेशन बर्नियो के पास पृथ्वी के समताप मंडल में पैराशूट से छलांग लगाते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इंजीनियर डेनिस येप्रेमोव। समताप मंडल पृथ्वी से 16 से 50 किमी की ऊंचाई तक को कहा जाता है, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इस साहसिक छलांग का वीडियो डेनिस ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। रायटर

दो और दो प्यार ★★★

फिल्म रिव्यू

प्रमुख कलाकार : विद्या बालन, प्रतीक गांधी, इलियाना डिक्रूज, सेंथिल राममूर्ति

निर्देशक : शीर्षा गुहाठाकुरता

अवधि : दो घंटे 19 मिनट

वैवाहिक रिश्ते की नर्मी-गर्मी

विद्या बालन ने काव्या के द्वंद्व और चुलबुलेपन को जीया है। चित्र सौ. :फिल्मटीम

दांपत्य जीवन से असंतुष्ट दंपती कई बार अपने सुख की तलाश विवाहेतर संबंधों में करने लगते हैं। रिश्तों में यह दूरी रोजमर्रा की व्यस्तता, जिम्मेदारियों, एकदूसरे की भावनाओं का सम्मान और प्यार का इजहार न करने की वजह से होती है। विवाहेतर संबंधों में सुख की खोज पूरी होती है, लेकिन लंबे समय बाद शादी तोड़ने को लेकर समाज का डर भी सताता है। जब पति-पत्नी के विवाहेतर संबंधों का रहस्योद्घाटन एकदूसरे के सामने होता है तो आंखें मिलाना मुश्किल हो जाता है। फिर मन की गांठें खुलती हैं। अंग्रेजी फिल्म 'द लवर्स' की रीमेक 'दो और दो प्यार' इसी विषय पर आधारित है।

मुंबई में रह रही डेंटिस्ट काव्या गणेशन (विद्या बालन) और बिजनेसमैन अनिरुद्ध बनर्जी (प्रतीक गांधी) के प्रेम विवाह को 12 साल हो चुके हैं। उनकी शादी को काव्या के परिवार की स्वीकृति नहीं मिली है। दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन संबंधों में नीरसता आ गई है। दोनों विवाहेतर संबंधों में हैं। काव्या फोटोग्राफर विक्रम (सेंथिल राममूर्ति) के साथ सपने बुन रही है, जो न्यूयार्क में सब कुछ छोड़कर मुंबई आ बसा है। अनिरुद्ध का थिएटर कलाकार नोरा उर्फ रोजी (इलियाना डिक्रूज) के साथ इश्क चल रहा है। दोनों के प्रेमी विवाह को जल्द तोड़ने की मांग करते हैं। अचानक काव्या के दादाजी का निधन हो जाता है। वह ऊटी में मायके आती है। उसके साथ अनिरुद्ध भी है। मुंबई लौटने पर विवाहेतर संबंधों को लेकर दोनों उधेड़बुन में हैं।

विज्ञापन की दुनिया से आईं निर्देशक शीर्षा गुहा ठाकुरता की यह फिल्म रिश्तों की जटिलताओं और उन दुविधाओं की ओर जाती है, जब शादीशुदा लोग अफेयर से गुजरते हैं। उन्होंने दांपत्य जीवन में बढ़ती दूरी और उन संबंधों को संजोने को लेकर भाषणबाजी देने का प्रयास नहीं किया है, ना ही नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। ऊटी में रिश्तों में ताजगी आने के बाद वह शारीरिक सुख की ओर ज्यादा आकर्षित नजर आते हैं, अपनी समस्याओं पर बात नहीं करते। यह पहलू खटकता है। फिल्म टुकड़ों-टुकड़ों में हंसाते हुए गंभीर विषय की प्रासंगिकता बनाए रखती है। काव्या और अनिरुद्ध के फिर से जागे रोमांस और मौजूदा रिश्तों को जोड़ने की कोशिशों में दोहराव दिखता है। विद्या ने लंबे समय बाद रोमांटिक कामेडी फिल्म की है। काव्या की मनोदशा, दुविधा, चुलबुलेपन और द्वंद्व को उन्होंने उचित भावों के साथ जीया है। प्रतीक गांधी साबित करते हैं कि वह हर भूमिका में सहजता से ढल जाते हैं। अनिरुद्ध की भूमिका में उनसे बेहतर शायद ही कोई हो सकता था। विक्रम बने सेंथिल का पात्र कई बार बिना संवाद के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर जाता है। इलियाना सुंदर दिखी हैं, लेकिन लेखन स्तर पर उनका पात्र कमजोर है। फिल्म मुख्य रूप से टूटने की कगार पर आई शादियों और बेवफाई के बारे में नया दृष्टिकोण भी देती है।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

अपने राय हमें जरूर बताएं : feature@jagran.com

इधर-उधर की

...तो इसलिए ब्रिटेन में भेड़ों पर किया जा रहा बाडी स्प्रे

भेड़ों के हार्मोन को प्रभावित करती है बाडी स्प्रे। इंटरनेट मीडिया

लंदन, एजेंसी: ब्रिटेन में अब इंसानों के अलावा भेड़ों पर भी बाडी स्प्रे किया जा रहा है। ऐसा किसी दुर्गंध से बचने के लिए नहीं बल्कि भेड़ों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए किया जा रहा है। ब्रिटिश भेड़ फार्म की मालकिन सैम ब्रायस ने न्यूज एजेंसी को बताया कि उन्हें एक फेसबुक ग्रुप के माध्यम से इस तरकीब का पता चला। इसे आजमाने पर उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम दिखे। यह सुगंध उन हार्मोनों को प्रभावित करती हैं जो भेड़ों को आक्रामक बनाते हैं। एक अन्य भेड़ पालक कैटलिन जेनकिंस ने कहा कि इससे परित्यक्त मेमनों को अपनाने के लिए मां भेड़ को मनाने में मदद मिलती है। भेड़ें अपने बच्चों को गंध से पहचानती हैं और बाडी स्प्रे से वह भ्रमित होकर किसी भी मेमने को संतान समझ लेती हैं।

तेजी से बढ़ रहा हृदय विकार एट्रियल फाइब्रिलेशन का जोखिम

अनुसंधान

प्रतीकात्मक

एक ताजा अध्ययन में पाया गया है कि दिल की अनियमित धड़कन की बीमारी एट्रियल फाइब्रिलेशन का जोखिम तेजी से बढ़ा है। पिछले दो दशकों के दौरान हृदय विकार एट्रियल फाइब्रिलेशन का जीवनकाल जोखिम चार में से एक, से बढ़कर तीन में से एक हो गया है। एट्रियल फाइब्रिलेशन जिसे एएफआइबी या एएफ के रूप में भी जाना जाता है, रक्त के थक्के, स्ट्रोक, हार्ट फेल और हृदय संबंधी जटिलताओं का कारण बन सकता है।

अपने जीवनकाल में एट्रियल फाइब्रिलेशन के पांच मरीजों में से दो को हार्ट फेल व एक को स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है। पिछले 20 वर्ष के अध्ययन के दौरान इसके जोखिम में खास बदलाव नहीं देखा गया। अनुमान है कि एट्रियल फाइब्रिलेशन से 2060 तक यूरोप में 1.8 करोड़ लोग व अमेरिका में 2050 तक 1.6 करोड़ लोग एट्रियल फाइब्रिलेशन से प्रभावित होंगे। ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सिस्टम में हर साल कैंसर के चार आम कारणों की तुलना में एट्रियल फाइब्रिलेशन के अधिक नए मामलों का निदान किया जाता है। एक बार एट्रियल फाइब्रिलेशन विकसित हो जाता है तो मरीज की देखभाल स्ट्रोक के जोखिम पर केंद्रित होती है। लेकिन अन्य जटिलताओं हार्ट फेल व हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए डेनमार्क के 35 लाख लोगों के नेशनल डाटा का विश्लेषण किया। इन्हें 45 वर्ष की आयु में एट्रियल फाइब्रिलेशन नहीं था लेकिन बाद के (2000 से 2022 के बीच) 22 वर्षों में 3,62,721 लोगों में एट्रियल फाइब्रिलेशन विकसित हो गया। इनमें 46 प्रतिशत महिलाएं व 54 प्रतिशत पुरुष थे। (एएनआइ)

स्क्रीन शाट

पता था शाह रुख एक दिन सुपरस्टार बनेंगे : चंकी पांडे

प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती है। ऐसा ही कुछ शाह रुख खान के साथ भी हुआ है। शाह रुख की प्रतिभा को अभिनेता चंकी पांडे ने तब ही पहचान लिया था, जब वह अभिनेता बने भी नहीं थे। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान चंकी ने शाह रुख के शुरुआती दिनों का जिक्र किया। वह कहते हैं कि शाह रुख का पहला दोस्त मुंबई में मेरे छोटे भाई चिक्की थे। वह दोनों आज भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। शाह रुख और गौरी (शाह रुख की पत्नी गौरी खान) उन दिनों किराए के मकान में रहा करते थे।

हाउसफुल 5 की शूटिंग जल्द शुरू करेंगे चंकी पांडेय। फाइल

वह अक्सर मेरे भाई से मिलने आया करते थे। हम सब साथ बैठकर वीडियो कैसेट पर फिल्में देखा करते थे। अक्सर वह हमारे घर पर ही होते थे। शाह रुख को देखकर हमेशा लगता था कि वह एक दिन सुपरस्टार बनेंगे, क्योंकि उनमें सुपरस्टार बनने वाली बात थी।

वह आग उनमें दिखाई देती थी। सुपरस्टार बनने से पहले ही उनमें वह प्रतिभा थी। शुरुआती दौर में भी वह बेहद आत्मविश्वासी थे। उन्हें पता था कि उन्हें किस दिशा में बढ़ना है। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उन्हें शुरुआती दौर से जानता हूं। वह आज भी बिल्कुल नहीं बदले हैं। यही बात अक्षय कुमार में भी दिखाई देती थी। वह एक्टिंग स्कूल में मेरे जूनियर थे। 16 साल के थे। तब क्लास में सीनियर जूनियर्स को सिखाया करते थे। मैंने भी उन्हें सिखाया है। (हंसते हुए) अब भी वह कहते हैं कि जो शुरुआती दौर में उन्होंने फिल्में की हैं, वह फ्लाप इसलिए हुई थीं, क्योंकि उन्होंने मेरी ट्रेनिंग का प्रयोग उसमें किया था। मैं तब से उन्हें जानता हूं। मुझे पता था कि वह भी एक दिन बड़े कलाकार बनेंगे। आगामी दिनों में चंकी हाउसफुल 5 में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग वह जल्द शुरू करने वाले हैं।

ठंडे बस्ते में गई टाइगर की रैम्बो

अभिनेता टाइगर श्राफ के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। ईद पर प्रदर्शित फिल्म बड़े मियां छोटे मियां बाक्स आफिस पर धमाल मचाने में नाकाम रही। इससे पहले हीरोपंती 2 और गणपत भी फ्लाप साबित हुई थी। इसका असर अब उनकी अगली फिल्मों पर पड़ता नजर आ रहा है। खबरें है कि सिद्धार्थ आनंद और टाइगर की लंबे समय से निर्माणाधीन फिल्म रैम्बो को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह हालीवुड की रैम्बो फ्रेंचाइज की पहली फिल्म रैम्बो - फर्स्ट ब्लड की आधिकारिक हिंदी रीमेक थी। साल 2017 में सिद्धार्थ और टाइगर ने इसकी घोषणा की थी। उसके बाद बीच-बीच में इसके बनने की खबरें आईं। फिल्म को पहले सिद्धार्थ द्वारा निर्देशित किया जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने देसी ब्वायज फिल्म के निर्देशक रोहित धवन को इसका निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया। विभिन्न कारणों से फिल्म के बनने की शुरुआत नहीं हो पा रही थी। पिछले साल जब निर्माताओं ने जाह्नवी कपूर को टाइगर के साथ मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाने के लिए चुना, तो रैम्बो फिर सुर्खियों में आई। इसे गत जनवरी में शुरू किया जाना था, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि टाइगर की पिछली तीन फिल्में बाक्स आफिस पर असफल रही हैं। रैम्बो बड़े बजट की फिल्म होगी। इस एक्शन प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर शूटिंग की आवश्यकता होती है।

पिछले काफी समय से हिट फिल्म की तलाश में हैं टाइगर।

जूतों के सवाल पर हर्षवर्धन का तगड़ा जवाब

स्टार किड्स को कभी नेपोटिज्म के मुद्दे पर तो कभी उनके विशेषाधिकार को लेकर ट्रोल कर दिया जाता है। ऐसी ही ट्रोलिंग अक्सर अनिल कपूर के बेटे और अभिनेता हर्षवर्धन कपूर की भी होती रहती हैं। कभी उनके फिल्में कम करने को लेकर, तो कभी उनके स्निकर्स (जूतों) के कलेक्शन को लेकर उन्हें ट्रोल कर दिया जाता है। एक ऐसे ही टिप्पणी खल गई हर्षवर्धन को और उन्हें करारा जवाब दिया है। एक यूजर ने हर्षवर्धन से एक्स पर पूछा कि कभी एक ढंग की फिल्म कर ले। कब तक पिता के पैसे से स्निकर्स खरीदता रहेगा? इस पर हर्षवर्धन ने लिखा, 'मैं तुम्हारी फिल्में कहां देख सकता हूं? तुमने कितनी फिल्में की हैं? मैंने तो रे, थार, भावेश जोशी, एके वर्सेज एके और मिर्जिया की हैं। तुम कौन हो? एक अप्रासंगिक हारा हुआ व्यक्ति, जो ट्विटर पर केवल कड़वाहट फैला सकता है।' पिछले साल जब पूर्व फुटबाल खिलाड़ी डेविड बेकहम उनके घर आए थे और हर्षवर्धन ने उनके साथ तस्वीर साझा की थी। एक ट्रोलर ने कमेंट करते हुए लिखा था कि क्या उसने ये नहीं पूछा कि तू है कौन है? इस पर जवाब देते हुए हर्षवर्धन ने लिखा था, 'भाई वो मेरे घर पर आया था। तू कौन है?' जल्द ही हर्षवर्धन ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की बायोपिक में पिता के साथ नजर आएंगे।

अपने जूतों के कलेक्शन के लिए खासे प्रसिद्ध हैं हर्षवर्धन कपूर - इंस्टाग्राम - @harshvardhankapoor

रिलीज से पहले ही पुष्पा 2 ने बना दिया रिकार्ड

क्या ऐसा हो सकता है कि फिल्म रिलीज ही नहीं हुई हो और उसने पैसे कमा लिए हों या फिर रिकार्ड बना दिया हो। ऐसा सुनने में अब तक तो नहीं आया था, लेकिन अब पुष्पा 2 : द रूल ने कुछ ऐसा ही कारनाम कर दिखाया है। दक्षिण भारतीय कलाकार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म पुष्पा 2 ने आरआरआर फिल्म से आगे निकलते हुए सबसे बड़ी डील अपने नाम कर ली है। फिल्म से जुड़े करीबी सूत्रों के अनुसार पुष्पा 2 : द रूल के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स को ढाई सौ करोड़ रुपये पर बेच दिया गया है। यह सभी भाषाओं की फिल्मों के लिए एक रिकार्ड डील है। बाहुबली 2 और केजीएफ 2 फिल्मों के बाद पुष्पा 2 बहुप्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्मों में से एक है।

ऐसे में फिल्म से जुड़े लोगों की इस फिल्म की परफार्मेंस पर पूरा भरोसा है। यह जो डील हुई है, वह बाक्स आफिस के प्रदर्शन के आधार पर परिवर्तनशील होगी। डील करने का जो नया तरीका अपनाया गया है वह बाक्स आफिस पर फिल्म की परफार्मेंस को देखकर बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल जो बेस प्राइस तक किया गया है वह ढाई सौ करोड़ है, यह आंकड़ा तीन सौ करोड़ तक बढ़ सकता है। डिजिटल अधिकारों के मामले में पिछला रिकार्ड एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने बनाया था। फिल्म 170 करोड़ रुपये में डिजिटल के लिए बिकी थी। फिलहाल पुष्पा 2 : द रूल की रिलीज में अभी समय है। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी। साल 2021 में इसके पहले पार्ट पुष्पा : द राइस ने हिंदी में 125 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

श्रीवल्ली की भूमिका में फिर लौटेंगी रश्मिका रश्मिका मंदाना - इंस्टाग्राम - @rashmika_mandanna

दुनिया का अनूठा पतंग संग्रहालय...

चीन के शानडोंग प्रांत के वेफांग में पतंगों का अनूठा विश्व पतंग संग्रहालय है, जिसमें चीन के अतीत से लेकर आधुनिक समय तक के माडल और पतंगों का संग्रह है। इसमें दुनियाभर की पतंगों की अलग-अलग शैलियों की बारह गैलरियां हैं। इस संग्रहालय के कारण वेफांग शहर पतंगों की विश्व राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। यह शहर प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेजबानी करता है। जो दुनियाभर के पतंग प्रेमियों को आकर्षित करता है। हालांकि गुजरात के अहमदाबाद में भी प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

****